



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 314] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 28, 2017/ अग्रहायण 7, 1939
No. 314] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 28, 2017/ AGRAHAYANA 7, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2017

अंतिम जाँच परिणाम

विषय : सऊदी अरब मूल के अथवा वहां से निर्यातित “नार्मल बुटानोल” अथवा “एन-बुटिल अल्कोहल” के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

सं.14/20/2016-डीजीएडी.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्पश्चात् अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात् नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. क्रिया-विधि

1. निम्नोक्त वर्णित क्रिया-विधि का अनुसरण किया गया है:-

(क) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी कहा गया है) को उपरोक्त नियमवाली के अंतर्गत संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उद्योग के बतौर दि आन्ध्रा पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एपीएल) (जिसे आगे याचिकादाता कहा गया है) से एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने सऊदी अरब मूल के अथवा वहां से निर्यातित “नार्मल बुटानोल” अथवा “एन-बुटिल अल्कोहल” (जिसे आगे संबद्ध वस्तुएं कहा गया है) का पाटन और उसके

परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने का आरोप लगाया है और संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करने का अनुरोध किया है।

- (ख) प्राधिकारी ने याचिकादाता द्वारा जांच की शुरुआत का यथोचित ठहराने के लिए प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की जांच शुरू करने का निर्णय लिया है।
- (ग) प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के उप-नियम 5 (5) के अनुसार जांच शुरू करने की कार्रवाई करने से पहले आवेदन पत्र की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावास को अधिसूचित किया है।
- (घ) प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटन-रोधी जांच शुरू करने के बारे में दिनांक 2 सितंबर, 2016 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी जो कि भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।
- (ङ) प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की एक प्रति सभी ज्ञात निर्यातकों (जिने ब्यौरे याचिकादाता द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) को भेजी थी और उन्हें पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (2) के अनुसार अपने लिखित विचारों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया था।
- (च) प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भारत में संबद्ध वस्तुओं के सभी ज्ञात आयातकों और उद्योग एसोसिएशनों को भेजी थी और उन्हें सलाह दी थी कि वे पत्र जारी किए जाने की तारीख से चालीस दिनों के भीतर लिखित विचारों से अवगत करा दें।
- (छ) प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (3) के अनुसार ज्ञात निर्यातकों और भारत में संबद्ध देश के दूतावास को आवेदन पत्र की अगोपनीय वृत्तान्त की एक प्रति प्रदान की थी।
- (ज) प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातक को प्रश्नावलियां भेजी थीं:

सऊदी अरेबिया बेसिक इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन (एसएबीआईसी)

पो.ओ. बॉक्स :59090,

रियाद – 11525 सऊदी अरब

- (झ) जांच शुरू करने के प्रत्युत्तर में संबद्ध देश से निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने उत्तर दिए हैं:-

- (1) सऊदी बुटानोल कंपनी (सबूको)
- (2) सऊदी एक्रेलिक एसिड कंपनी (साँक)
- (3) सदारा केमिकल कंपनी (सदारा)
- (4) पेट्रोकेम मिडल ईस्ट एफजेडई (पेट्रोकेम)
- (5) नेशनल इंडस्ट्रियलाइजेशन पेट्रोकेमिकल मार्केटिंग कंपनी (टसनी मार्केटिंग)
- (6) टोयटो टसूशो कार्पोरेशन (टोयटा)

- (ञ) इसके अतिरिक्त सदारा केमिकल कंपनी और सऊदी बुटानोल कंपनी द्वारा भी वर्तमान जांच के संबंध में टिप्पणियां दी गई हैं।
- (ट) पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं/एसोसिएशनों के प्रश्नावलियां भेजी गई हैं:-

के. के.एल.जे. ग्रुप ऑफ कंपनी, मुख्यालय के.एल.जे. हाउस, 63 रामा मार्ग, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110016	पी.सी.एल. ग्रुप 703, 7वां तल, डीएलएफ टॉवर, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जशोला, नई दिल्ली-110044
एपीआई इंडस्ट. कार्पोरेशन, एनके पोलीमर्स एंड एडिटिव्स मेन्युफैचरिंग कंपनी, 36/2 रिंगनवाडा,	रचना प्लास्टिक्स प्लास्टिसाईजर्स, प्लाट नंबर 116 और 117 पिपाना इंडस्ट्रियल

निकटस्थ सोमनाथ इंडस्ट्रियल इस्टेट, दमन-396201 (यूटी)	इस्टेट, यूटी आफ डी एंड एनएच, सिल्वासा, वापी, गुजरात
विसेन इंडस्ट्री लिमिटेड 102/ए विरवानी इंडस्ट्रियल इस्टेट, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 4000063	माईक्रो इन्क्स लिमिटेड, प्लॉट नंबर 2801/3ए और 3, 2083/2, 2084 और 2085-86, सर्वे नंबर 286/1 जीआईडीसी तीसरा चरण, वापी, वल्साड, गुजरात
एल्किल अमीन्स केमिकल्स लिमिटेड, प्लॉट नंबर 67, एमआईडीसी, पटल गंगा इंडस्ट्रियल एरिया ग्राम - काईरे, तहसील खालापूर, जिला - रायगड	ललिता केम इंडस्ट्रियल प्राईवेट लिमिटेड, यूनिट नंबर 2, प्लॉट नंबर 326, नांजी इंडस्ट्रियल एरिया, सर्वे नंबर 200/1/2, ग्राम - खिराडी, पुणे
के. एल.जे. ग्रुप ऑफ कंपनी, मुख्यालय के.एल.जे. हाउस, 63 रामा मार्ग, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110016	पीसीएल ग्रुप 703, 7वां तल, डीएलएफ टॉवर, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जशोला, नई दिल्ली-110044
एपीआई इंडस्ट. कार्पोरेशन, एनके पोलीमर्स एंड एडिटिव्स मेन्युफैचरिंग कंपनी, 36/2 रिंगनवाडा, निकटस्थ सोमनाथ इंडस्ट्रियल इस्टेट, दमन-396201 (यूटी)	रचना प्लास्टिक्स प्लास्टिसाईजर्स, प्लॉट नंबर 116 और 117 पिपाना इंडस्ट्रियल इस्टेट, यूटी आफ डी एंड एनएच, सिल्वासा, वापी, गुजरात
विसेन इंडस्ट्री लिमिटेड 102/ए विरवानी इंडस्ट्रियल इस्टेट, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-400063	माईक्रो इन्क्स लिमिटेड, प्लॉट नंबर 2801/3ए और 3, 2083/2, 2084 और 2085-86, सर्वे नंबर 286/1 जीआईडीसी तीसरा चरण, वापी, वल्साड, गुजरात
सी. जे. शाह एंड कंपनी, 106 बजाज भवन, 10वां तल, नरीमन प्वाइंट, मुंबई- 400021	रमणीक लाल ए. गोससालिया एंड कंपनी, नेशनल हाउस, 608, बी.जे. मार्ग, जेकब सर्किल, मुंबई-400011
हरेश पेट्रोलियम प्राईवेट लिमिटेड, 404/405, एकमा प्लाजा, अंधेरी कुरला रोड, संगम थिएटर के सामने, अंधेरी (पूर्व) मुंबई-400059	हजेल मकेंटाईल लिमिटेड, 3/10 कपाडिया चेम्बर्स, 599 जे.एस.एस. रोड, मरीन लाईन्स, मुंबई-400002
कुन्दन राईस मिल्स लिमिटेड, डी-16, सिटी चेम्बर्स, प्रशांत विहार, दिल्ली-110056	हजेल मकेंटाईल लिमिटेड, 3/10 कपाडिया चेम्बर्स, 599 जे.एस.एस. रोड, मरीन लाईन्स, मुंबई-400002
एशियल सोल्वोकेम प्राईवेट लिमिटेड, विंडसर, दूसरा तल, सीएसटी रोड, कालीना, सांताक्रूज (पूर्व)	के.एल.जे.रिसोर्सिज लिमिटेड, 76, जुहू शॉपिंग सेन्टर, दूसरा तल, गुलमोहर क्रोस, 9वां रोड, जुहू स्कीम, मुंबई-400049

मुंबई-400096	
पेट्रोकेम मिडल ईस्ट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड, 201 विजीनेस स्केयर, बी-विंग, अंधेरी कुरला रोड, एप्पल हेरिटेज के सामने, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400093	पोन प्युर केम (प्राईवेट) लिमिटेड, नंबर 32, एच-ब्लॉक, 15वां मेन रोड, अन्ता नगर, चेन्नई-600040
योग इंटरनेशन प्राईवेट लिमिटेड, खसरा नंबर 36/8, मुंडका ग्राम, दिल्ली-110041	दागा ग्लोबल केमिकल्स लिमिटेड, 302, सकर-3, ओल्ड हाई कोर्ट के सामने, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009
अपरा इंटरप्राइज, प्लाट नंबर 176, दूसरा तल, डा. केंट हाउस, सिओन (पश्चिम), मुंबई-400022	ओवरसीज पोलीमर प्राईवेट लिमिटेड, विनमार हाउस, ए-41 एमआईडीसी रोड नंबर 2, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400093
केतुल केम प्राईवेट लिमिटेड, वेस्टर्न एज-1, करकला स्पेसिज, यूनिट नंबर 403, मेट्रो शॉपिंग माल के ऊपर, बोरीवली (पूर्व), मुंबई-400066	बालमुकंद केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 4765, जीआईडीसी इस्टेट, फाल्काम चार रास्ता के समीप, अंकलेश्वर-393002
पारस डाईज एंड केमिकल्स बी-82, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली-110024	जागृति प्लास्टिक्स लिमिटेड, 107, एम.जी. हाउस, कम्युनिटी सेन्टर, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110052
सुरभी इंटरप्राइजिज प्राईवेट लिमिटेड, हेड आफिस, 4/1कामा स्ट्रीट, ग्राउंड फ्लोर, कोलकाता-700016	संजय केमिकल्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड, 5वां तला, कनमूर हाउस, 281/287, नरषी नाथ स्ट्रीट मस्जिद, मुंबई-400009 (महाराष्ट्र)
सुप्रीम इंडिया इंटरनेशनल, सी-11, जीवन ज्योति, 18/20, क्वासजी पटेल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-400001	बिजिनेस केम प्राईवेट लिमिटेड, 203/204, शिव चेम्बर्स, प्लाट नंबर 21, ए- विंग, सेक्टर-11, एमटीएनएल बिल्डिंग से अगला, सीबीडी बेलापुर (पूर्व), नवीं मुंबई
अंकिता केमिकल कार्पोरेशन, नंबर 7, श्रवण भवन, नई गौम क्रोस रोड, दादर	केतुल केम लिमिटेड, 403, वेस्टर्न एज, मेट्रो स्टोर,

ईस्ट, मुंबई-400014	बोरावली (पूर्व), मुंबई-400092
नूतन केमिकल्स लिमिटेड, जे-37, एम.आई.डी.सी. भोसारी, पुणे-411026, महाराष्ट्र, भारत	त्रिवेणी एरोमेटिक्स एंड परफ्यूमरी प्राईवेट लिमिटेड, 136, पंचरत्ना चार रस्ता, जी.आई.डी.सी., वापी-386195 गुजरात
ए.बी. इंटरप्राईजिज लिमिटेड, 202 श्रद्धानंद बिल्डिंग, 272/274 सेम्युल स्ट्रीट, मुंबई-400003	प्लास्टिक केम हंडस. कार्पोशन, ए-2001, रनवल प्राईड, 20वां तला, एल.बी.एस. रोड, मुलुंद वेस्ट, मुंबई-400080
तुलसी केमिकल्स, 3, ओल्ड नंबर 2, राजा अन्नमलई रोड, पहला तल, पुरसवाकम, चेन्नई-600084	देव केमिकल्स, 1-80 अध्यापक नगर, नांगलोई, नई दिल्ली-110041
नयाकेम आर्गेनिक्स (प्राईवेट) लिमिटेड, 242, ए टू जेड इंडस्ट्रियल एरिया, जी. कदम मार्ग, लोयर पारेल, मुंबई-400013	एग्रीकेम, 20, जल विशमभरी सीएचएस, 153-ए, एम. जी. रोड, कांडीवाली (पश्चिम), मुंबई-400067
प्रथमेश डाईकेम प्राईवेट लिमिटेड, डी-6, एम.आई.डी.सी. फेज-2, डाम्बीवली (पूर्व)	दाई-ईची करकारिया लिमिटेड, लिबर्टी बिल्डिंग सर बिठुलदास, ठाकरसी मार्ग, मुंबई-400020
के. आर्गेनिक्स प्राईवेट लिमिटेड, 209, स्टेंडफोर्ड प्लाजा, प्लॉट नंबर बी-65 ऑफ अंधेरी मलाड न्यू लिंक रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-400053	प्रीमियर सोल्वेंट्स प्राईवेट लिमिटेड, 11, सिद्धीगिरि सीएचएस, दूसरा तल, एस.वी.रोड, यूटीआई के निकटस्थ, बोरावली (पश्चिम), मुंबई-400092
ईस्टर्स सोल्वेंट्स, डब्ल्यू-180, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, पवाने, थाणे-बेलापुर रोड, थाणे-400613	फाईन आर्गेनिक्स इंडस. प्राईवेट लिमिटेड, फाईन हाउस, आनंदजी स्ट्रीट, ऑफ एम.जी.रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400072
पिडलाईट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रामाकृष्णा मन्दिर रोड, पी.बी. नंबर 17411 अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400059	इसरो प्रोडक्ट्स, सी.विंग ईस्ट-वेस्ट इस्टेट, यूनिटोप हाउस, सेफेड पूल, अंधेरी कुरला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400072

गेलेक्सी सर्फेकेन्टस लिमिटेड, सी-49/2, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, पवाने ग्राम, नवी मुंबई, वाशी-400703	लुबरीजोई इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, 9/3, थाणे-बेलापुर रोड, तुरभी, नवी-मुंबई-400705
एसडी पेंट्स लिमिटेड, निकट पावर हाउस, ढोकरोली, नाका कोलशेट रोड, थाणे-400607	कोटवेल पेन्ट्स, 6/19, तारेदेव एयर कंडीशनल मार्किट, तारदेव रोड, मुंबई-400034
कंसल नेरोलेक पेन्ट्स लिमिटेड, नेरोलेक हाउस, गणपतराव कदम मार्ग, लोयर पारेल, मुंबई-400013	भारत रेसिन्स लिमिटेड, 43, दभेल इंडस्ट्रियल कोओपरेटिव सोसाईटी लिमिटेड, दभेल, दमन-396210
सिंथेटिक्स एंड पोलिमेर इंडस/ब्लूवेल पोलिमर्स, डी-101, कोटेश्वर पेलेस, गरवारे हाउस कोले डोंगरी के सामने, लेन नंबर 4, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400069	कृष्णा एंटीओक्साईडेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड, 107/109, रहेजा प्लाजा, शाह इंडस्ट्रियल, यशराज स्टूडियों के सामने, आफ लिंक रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-400053
औचटेल प्रोडक्ट लिमिटेड, 142/सी विक्टर हाउस, एन.एम. जोशी मार्ग, लोयर पारेल, मुंबई-400077	काडिला फारमेक्युटिकल्स लिमिटेड, काडिला कार्पोरेट केम्पस, सरखेज-ढोल्का रोड, भाट, अहमदाबाद-382210
आरती ड्रग्स लिमिटेड, महेन्द्र इंडस्ट्रियल इस्टेट, ग्राउंड फ्लोर, प्लाट नंबर 109-डी, रोड नंबर 29, सिओन (पूर्व), मुंबई-400022	अतुल लिमिटेड, अतुल-396020, गुजरात
फिनियोटेक्स केमिकल्स इंडस्ट्रीज, 42/43, मनोराम चेम्बर्स, हुन्डई सेंट्रो कार शोरूम के ऊपर, एव.वी. रोड, बान्द्रा (पश्चिम), मुंबई- 400050	धीराजीलाल एंड कंपनी लिमिटेड, 300/3, जयजी दादाजी रोड, नाना चौक, मुंबई-400077
नारखेडे केमिकल्स, प्लाट नंबर सी-462, एमआईडीसी, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, पवाने, नवी मुंबई-400705	रिटोर्ट केमिकल्स (प्राईवेट) लिमिटेड, 4/पी, अरीहंत, अनुपम सिनेमा के सामने, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-400063

शालीमार पेन्ट्स लिमिटेड, सी विंग, 5वां तला, ओबराय गार्डन इस्टेट, चन्दीवली (पूर्व), मुंबई-400072	एडवांस्ड माईक्राडिवाइसिज (प्राईवेट) लिमिटेड, 21 इंडस्ट्रियल एरिया, अम्बाला कैट-133006
श्री आर्गनिक्स, प्लॉट नंबर 75, कल्याण नगर, वीकेआई रोड नंबर 4 के सामने, जयपुर (राजस्थान)	डिवीज लेबोरेटरीज लिमिटेड, डिवी टावर्स, 7-1-77/ई/1/303, धरम करन रोड, अमीरपेट, हैदराबाद-500016
डा. रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड, एपीआई एससीएम टीम, 8-2, 120/76/1/बी, दूसरा तला, अशोका चेम्बर्स, रोड नंबर 2, बनजारा हिल्स, हैदराबाद-500034	माईलान लेबोरेटरीज लिमिटेड, प्लॉट नंबर 564/ए/22, रोड नंबर 92, जुबली हिल्स, हैदराबाद-500037 (इंडिया)
हेटेरो ड्रग्स लिमिटेड, हेटेरो कार्पोरेट, 7-2, ए-2, इंडस्ट्रियल इस्टेट, सानथ नगर, हैदराबाद-500082	हैदराबाद केमिकल्स लिमिटेड, ए-24/25, एपीआईई, बालानगर, हैदराबाद-500037
श्रीपथी फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, प्लॉट नंबर 22 बी, रोड नंबर 2, जुबली हिल्स, हैदराबाद-500033	सुवेन लाईफ साईंसिज लिमिटेड, सीरीन चेम्बर्स, रोड # 5, एवेन्यू 7, बनजारा हिल्स हैदराबाद-500034
मेसर्स श्री कृष्णा फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, सी-4, इंडस्ट्रियल इस्टेट, उप्पल, हैदराबाद-500039	ओरोबिन्दो फार्म्युस्टिकल्स लिमिटेड, प्लॉट नंबर 2, मालती विहार, अमीरपेट, हैदराबाद-500038
विवीमेड लैब्स लिमिटेड, दूसरा तला, वीरिंग टावर्स, हबसीगुडा, हैदराबाद-500007	सालीसाईलेट्स एंड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड, ए-25, रोड नंबर 18, आईडीए, नाचाराम, हैदराबाद-500076
लौउरुस लैब्स प्राईवेट लिमिटेड, दूसरा तला, सीरेन चेम्बर्स, रोड नंबर 7, बनजारा हिल्स, हैदराबाद-500034	चौ. येगनेईहा एंड सन्स लिमिटेड, 1-ए, राष्ट्रपति रोड, सिकन्दराबाद-500076
एक्रोस सिंथेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड, बी4/1, साईट बी सुदेशपुर इंडस्ट्रियल एरिया, ग्रेटर नोएडा-201306	बंसल ट्रेडिंग कंपनी, 605, एनडीएम-1, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034
पायल ग्रुप, ई-24, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली-110002	इंडियन प्लास्टिकसाईजर्स मेन्युफैक्चर्स एसोसिएशन, के.एल.जे. हाउस, 63, रामा मार्ग, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110015

- (ठ) संबद्ध वस्तुओं के किसी भी आयातक/प्रयोक्ता ने प्रश्नावली के उत्तर के रूप में अथवा इस जांच की शुरुआत पर टिप्पणियां दे कर, इस जांच का उत्तर नहीं दिया है।
- (ड) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का अगोपनीय वृत्तान्त, हितबद्ध पक्षकारों की जांच के लिए एक सार्वजनिक फाईल में उपलब्ध कराया था। अनेक हितबद्ध पक्षकारों ने अनेक बार इस सार्वजनिक फाईल को देखा है। हितबद्ध पक्षकारों ने सार्वजनिक फाईल को देखा है और जिन्होंने दस्तावेजों की प्रतियों के लिए अनुरोध किया था, उन्हें प्रतियां उपलब्ध कराई गई हैं।
- (ढ) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिए गए थे कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के पर्याप्त अगोपनीय वृत्तान्त भी प्रस्तुत करें, जिन्हें सार्वजनिक फाईल से उपलब्ध कराया गया था।
- (ण) जितना आवश्यक समझा गया था, याचिकादाता और हितबद्ध पक्षकारों से और सूचना मंगाई गई थी। वर्तमान जांच के लिए जितना आवश्यक समझा गया था, घरेलू उद्योग का सत्यापन किया गया था।
- (त) निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों के परिसरों में भी मौके पर जांच की गई है:-
- (1) सऊदी बुटानोल कंपनी (सबूको)
 - (2) सऊदी एक्रेलिक एसिड कंपनी (साँक)
 - (3) सदारा केमिकल कंपनी (सदारा)
 - (4) नेशनल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रियलाइजेशन मार्केटिंग कंपनी (टसनी)
- (थ) उपरोक्त उत्पादकों/निर्यातकों को किए गए सत्यापन की एक रिपोर्ट जारी की गई थी। निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों पर आगे इस जांच परिणाम में विचार किया गया है।
- (द) सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) और डीजीएडी में संगत क्रिया-विधियों के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और निर्माण और बिक्री की लागत के आधार पर-क्षति कीमत (जिसे आगे “एनआईपी” कहा गया है) का आकलन किया गया है, ताकि जैसा लागू होता है, क्षति मार्जिन की सीमा का मूल्यांकन किया जा सके।
- (ध) वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2015 से शुरू होकर 31 मार्च, 2016 तक (12 महीनों) (जिसे आगे “जांच की अवधि” अथवा “पीओआई” कहा गया है) की है। तथापि, क्षति का विश्लेषण करने के परिप्रेक्ष्य में प्रवृत्तियों की जांच करने के लिए वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 और जांच अवधि शामिल है।
- (न) पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार प्राधिकारी ने 23 जून, 2017 को हुई सार्वजनिक सुनवाई में हितबद्ध पक्षकारों को अपने मौखिक विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया था। दूसरी सार्वजनिक मौखिक सुनवाई 24 अक्टूबर, 2017 को हुई थी। मौखिक सुनवाई में जिन हितबद्ध पक्षकारों ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे, उनसे अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों को लिखित में भी प्रस्तुत करें और साथ ही उत्तर भी दें।
- (प) जांच अवधि के दौरान प्रचलित औसत विनिमय दर को अपनाया गया है, जो कि 1 अमरीकी डालर = 65.91 रूपए है।

- (फ) नियम 16 के अंतर्गत प्राधिकारी ने 14 नवंबर, 2017 को एक प्रकटन विवरण जारी किया है और 21 नवंबर, 2017 तक प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां देने का अवसर प्रदान किया है।
- (ब) इस अंतिम जांच परिणाम में किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा *** सूचना को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत किया गया है तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उसे गोपनीय माना गया है।

ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

2. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “नार्मल बुटानोल” अथवा “एन-बुटिल अल्कोहल” है। “नार्मल बुटानोल” एक बेसिक आर्गनिक रसायन है जिसे सामान्यतया सीमा-शुल्क अधिनियम के अध्याय 29 में वर्गीकृत किया जाता है। “नार्मल बुटानोल” एक मुख्य एल्कोहल है जिसमें 4-कार्बन स्ट्रक्चर है और इसका मोलेक्यूलर फार्मूला सी4एच9ओएच है। “नार्मल बुटानोल” एसिड क्यूरेब लेक्युर्स के लिए एक विशिष्ट साल्वेंट है और बेकिंग फिनिसिज यूरिआ, मेलेमाईन अथवा फेनोलिक रेसिन्स से प्राप्त की जाती है। “नार्मल बुटानोल” के बड़े भाग को कोटिंग उद्योगों में सोल्वेंट्स के रूप में डेरिवेटिक्स में परिवर्तित किया जाता है। इस उत्पाद को सीमा-शुल्क शीर्ष संख्या 29051300 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

3. आवेदक ने यह दावा किया है कि संबद्ध वस्तुओं के निर्यात संबद्ध देश से भारत में किए जाते हैं और ये घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित नार्मल बुटानोल, भौतिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रोद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय है। उपभोक्ता इन दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त कर सकते हैं। ये दोनों वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने योग्य हैं और इसलिए पाटन-रोधी नियमावली के अंतर्गत इन दोनों वस्तुओं को “समान वस्तु” माना जाना चाहिए। इसलिए वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देश से आयात की जारी संबद्ध वस्तुओं के “समान वस्तु” माना जा रहा है।

ख.1 घरेलू उद्योग के विचार

4. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (क) वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद नार्मल बुटानोल है जिसे “एन-बुटिल अल्कोहल अथवा सामान्य बुटानोल भी कहा जाता है। नार्मल बुटानोल प्राईमरी अल्काहोल है, जो कि 4-कार्बन स्ट्रक्चर और मोलेक्यूलर फार्मूला सी4एच9ओएच है। यह स्पष्ट रूप से सचल, निष्क्रिय तरल गंध युक्त होता है। इसे सभी सामान्य विलायकों मिश्रित किया जा सकता है, लेकिन यह जल में अलग से मिश्रित किया जाने वाला तरल पदार्थ है। एनबीए चीनी और अन्य कार्बनहाईड्रेट्स के किण्वन करने का एक प्राकृतिक लघु उत्पाद है और यह अनेक खाद्य और पेय पदार्थों में विद्यमान होता है।
- (ख) नार्मल बुटानोल एसिड क्यूरेब लेक्युर्स के लिए एक विशिष्ट विलायक है और बेकिंग फिनिसिज यूरिआ, मेलेमाईन अथवा फेनोलिक रेसिन्स से प्राप्त की जाती है। “नार्मल बुटानोल” के बड़े भाग को कोटिंग उद्योगों में विलायक के रूप में व्युत्पन्नों में परिवर्तित किया जाता है।

ख.2 निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

5. विचाराधीन उत्पाद के बारे में किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई मुद्दा नहीं उठाया है।

ख.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

6. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “नार्मल बुटानोल” है। “नार्मल बुटानोल” एक बेसिक आर्गनिक रसायन है, जिसे सामान्यतया सीमा-शुल्क अधिनियम के अध्याय 29 में वर्गीकृत किया जाता है। “नार्मल बुटानोल” एक मुख्य एल्कोहल है जिसमें 4-कार्बन स्ट्रक्चर है और इसका मोलेक्यूलर फार्मूला सी4एच9ओएच है।

7. नार्मल बुटानोल एसिड क्यूरेब लेक्युर्स के लिए एक विशिष्ट साल्वेंट है और बेकिंग फिनिसिज यूरिआ, मेलेमाईन अथवा फेनोलिक रेसिन्स से प्राप्त की जाती है। नार्मल बुटानोल के बड़े भाग को कोटिंग उद्योगों और मुद्रण की स्याहियों में विलायक के रूप में प्रयुक्त करने के लिए व्युत्पन्नो में परिवर्तित किया जाता है। नार्मल बुटानोल को औषधियों और प्राकृति तत्वों, पोलिस करने में व्युत्पन्नो और क्लीनर्स, वस्त उद्योग में सोलूबिलिजर, डीसिंग तरल पदार्थों में व्युत्पन्नो, गेसोलीन में बर्फ-रोधी व्युत्पन्नो, सेल्युलोज नाईट्रेट के लिए ह्यूमएक्टेन्ट, गलाईकोल ईथर्स की उत्पादन में फीडबैक और फ्लोटेशन (ब्युटिल क्सेनथेट) और ब्युटिल मोनो कार्बोक्सलेट्स, ब्युटिल एसिटेट और ब्युटिल ब्यूटीरेट के उत्पादन के लिए प्रारंभिक सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।

8. इस उत्पाद को सीमा-शुल्क शीर्ष संख्या 29051300 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, सीमा-शुल्क का उक्त वर्गीकरण निर्देशात्मक मात्र है और यह किसी भी तरीके से वर्तमान जांच के कार्य-क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

9. “समान वस्तु” की परिभाषा से संबंधित नियम 2 (घ) में विशेष रूप से यह उल्लिखित है कि समान वस्तु का तात्पर्य ऐसी वस्तु से है जो पाटन किए जाने के कारण जांचाधीन वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जो कि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती है।

10. याचिकादाता ने यह दावा किया है कि संबद्ध देश से भारत में निर्यात की जा रही संबद्ध वस्तुएं घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित नार्मल बुटानोल भौतिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय है। उपभोक्ता इन दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त कर सकते हैं। ये दोनों वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने योग्य हैं और इसलिए पाटन-रोधी नियमावली के अंतर्गत इन दोनों वस्तुओं को “समान वस्तु” माना जाना चाहिए। इसलिए वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देश से आयात की जारी संबद्ध वस्तुओं के “समान वस्तु” माना जा रहा है।

11. प्राधिकारी नोट करते हैं कि समान वस्तु के मुद्दे पर किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई निवेदन नहीं किया गया है। प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि याचिकादाता द्वारा विनिर्मित नार्मल बुटानोल, संबद्ध देश से भारत में आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तु बनती है।

ग. घरेलू उद्योग का आधार और कार्य-क्षेत्र

12. पाटन रोधी नियमावली का नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

“(ख) “घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।”

ग.1 घरेलू उद्योग के विचार

13. घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू उद्योग के बारे किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (क) याचिका एक घरेलू उद्योग के रूप में मेसर्स दि आन्ध्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई है।
- (ख) याचिकादाता भारत में संबद्ध वस्तुओं का अकेला उत्पादक है।
- (ग) याचिकादाता ने संबद्ध वस्तुओं का न तो आयात किया है (प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से) और न ही वह संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातक अथवा आयातक से संबंधित है।
- (घ) याचिकादाता नियम 2 (ख) के अनुसार घरेलू उद्योग बनने का पात्र है।

ग.2 निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

14. घरेलू उद्योग के आधार और उसके कार्य-क्षेत्र के बारे में किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई मुद्दा नहीं उठाया है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

15. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदन पत्र घरेलू उद्योग के रूप में मेसर्स दि आन्ध्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया है। याचिकादाता भारत में संबद्ध वस्तुओं का अकेला उत्पादक है। याचिकादाता ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का कोई आयात नहीं किया है। इसके अतिरिक्त याचिकादाता, संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के किसी भी निर्यातक अथवा आयातक से) प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से (संबंधित नहीं है।

16. रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना की विधिवत् जांच करने और कानूनी प्रावधानों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी का यह मानना है कि याचिकादाता पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) और नियम 5 (3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है। इसलिए याचिकादाता घरेलू उद्योग बनता है और उसका को याचिका दायर करने का आधार है।

घ. पाटन मार्जिन

1. सामान्य मूल्य

17. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क (1) (ग) के अंतर्गत सामान्य मूल्य को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :

“(ग) किसी वस्तु के संबंध में “सामान्य मूल्य” का तात्पर्य है :

- (1) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (2) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत :

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।”

घ.1 घरेलू उद्योग के विचार

18. सामान्य मूल्य के बारे में याचिकादाता द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (क) निर्यातक देश में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए निम्नोक्त आधार बन सकते हैं:-
- (1) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में निर्यातक देश के घरेलू बाजार में समान वस्तु की कीमत;
 - (2) जब निर्यातक देश अथवा क्षेत्र अथवा उपयुक्त तृतीयक देश से समान वस्तु निर्यात की जाती है, तो उसकी तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत और
 - (3) प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत और लाभ के लिए उचित संवर्धन करने के साथ मूल देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत।
- (ख) संबद्ध देश के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की कीमत की सूचना/साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे। इसके अतिरिक्त संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं की उत्पादकों की कीमत सूचियों अथवा उद्धरणों को प्राप्त करने के भी प्रयास किए गए थे। तथापि, याचिकादाता संबद्ध देश के घरेलू बाजार में प्रचलित कीमतों की कोई भी विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने में असमर्थ रहा है।
- (ग) सबुको और आन्ध्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा प्रयुक्त ओक्सो प्रोद्योगिकी में कोई अंतर नहीं है। अतः सबुको और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित बुटोनोल उत्पान की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए याचिकादाता ने संरचित मूल्य उपागम को इस्तेमाल करके सामान्य मूल्य का निर्धारण करने का दावा किया है। याचिकादाता ने सिनगैस और बुटालकेहाईड मध्यवर्ती पदार्थों और अंतिम उत्पाद – नार्मल बुटानोल की लागत की संरचना करने के लिए कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और याचिकादाता की विद्युत कीमतों को अपनाया है। याचिकादाता ने कच्चे माल के लिए अपनी परिवर्तन लागत और खपत कारकों और अपनाई जाने वाली प्रयोज्यता का दावा किया है।
- (घ) जांच शुरू करने के बाद उत्पादक कंपनी, सऊदी बुटानोल कंपनी (सबुको) और निर्यातक कंपनियां, सऊदी एक्रेलिक एसिड कंपनी (सॉक), सदरा केमिकल कंपनी (सदरा), पेट्रोकेम मिडल ईस्ट एफजेडई, नेशनल इंडस्ट्रियलाइजेशन पेट्रोकेमिकल मार्केटिंग कंपनी (टसनी) और टोयटा ट्यूशो कार्पोरेशन द्वारा प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए गए हैं।
- (ङ) तथापि, सऊदी कयान (एसके) द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। तीन संयुक्त उद्यम कंपनियों के सबुको के नियंत्रण प्रचालनों में दैनिक आधार पर समान अधिकार हैं। हालांकि एसके ने भारत को निर्यात नहीं किया है, इसकी सॉक और सदरा की तरह सबुको के प्रचालनों पर नियंत्रण रखने में अहम भूमिका है, जैसे कि सबुको को प्रोपलीन के उसके अपने शेयरों की आपूर्ति करना और बुटानोल को उठाना और इसलिए ऐसा माना जाता है कि यह सॉक और सदरा से संबंधित है।
- (च) संयुक्त उद्यम कंपनियों में से एक कंपनी द्वारा उत्तर नहीं देने के फलस्वरूप समग्र ग्रुप के उत्तर को खारिज कर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त हितबद्ध पक्षकारों के लिखित निवेदनों में एसके की भूमिका के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
- (छ) हितबद्ध पक्षकारों के प्रतिनिधि ने सुनवाई के दौरान इन तीन संयुक्त उद्यमों के बीच किसी प्रकार का संबंध होने से साफ मनाही की है और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों को टाल दिया है। निर्यातक ने मौखिक सुनवाई किए जाने के समय निर्दिष्ट प्राधिकारी और घरेलू उद्योग उठाए गए प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया है और उसके बाद अपने लिखित निवेदनों में उनका कोई उल्लेख नहीं किया है तथा इस प्रकार मौखिक सुनवाई के मुख्य प्रयोजन को नकार दिया है।
- (ज) जैसा कि निर्यातक के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया है, सऊदी कयान की निर्यात बिक्रियां- शून्य हैं।
- (झ) टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 (पाटन-रोधी करार) के अनुच्छेद VI के क्रियान्वयन संबंधी करार में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो कि आंकड़ों का संग्रहण करने की अवधि के सही समय को विनिश्चित करता हो।

- (ज) वर्तमान जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई जांच की अवधि अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 तक की है, जो कि प्राधिकारी की सामान्य पद्धति के अनुसार है।
- (ट) ऐसी अनेक जांच हैं, जिसमें एक से अधिक देश शामिल हुए हैं और इन संबद्ध देशों में से एक देश के आयात, जांच अवधि में किए गए हैं और कभी-कभी तो ऐसे आयात जांच की अवधि के अंत में हुए हैं।
- (ठ) ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि पाटन समग्र जांच अवधि में होना चाहिए।
- (ड) निर्यातक, सऊदी कयान नई शिपर समीक्षा किए जाने का हकदार है क्योंकि वह एक ऐसा उत्पादक है, जिसने जांच अवधि के दौरान भारत को उत्पाद के निर्यात नहीं किए हैं।
- (ढ) इन उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
- (ण) प्रतिवादियों की कानूनी और प्रचालन के ढांचे के बारे में पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं दिए गए हैं और मुख्य तथ्यों को छिपाया गया है।
- (त) इन कंपनियों द्वारा मुख्य तथ्यों को छिपाए जाने से उनकी प्रश्नावली के उत्तर को खारिज करना यथोचित है।
- (थ) तीन संयुक्त उद्यम प्रवर्तक कंपनियों को एक दूसरे के साथ संबंधित कंपनियां माना जाना चाहिए और इस संबंध में मुख्य तथ्यों को छिपाया गया है।
- (द) इन कंपनियों की घरेलू बिक्रियां, निचले स्तर के उत्पाद का उत्पादन करने के लिए संबंधित पक्षकार को की गई बिक्रियां हो सकती हैं, जिसके फलस्वरूप वे अर्थक्षम घरेलू बिक्रियां नहीं हो सकती हैं।
- (ध) प्रतिवादियों के सामने पेश आ रही स्थिति, ऐसी विशिष्ट स्थिति हो सकती है, जो कि घरेलू बिक्रियों कीमतों को खारिज करने के लिए यथोचित है।
- (न) प्रचालनों के जटिल जाल से स्पष्ट होता है कि दावा की गई उत्पादन की लागत अत्यधिक अविश्वसनीय है।
- (फ) संबंधित प्रयोज्यताओं से प्रचालनों और आदानों के जटिल जाल से मूल कंपनियों द्वारा अत्यधिक समर्थन किए जाने के कारण दावा की गई उत्पादन की लागत अत्यधिक कम बताई गई है।
- (ब) उत्पादक-निर्यातकों ने यह दावा किया है कि सबुको को उत्पादक नहीं माना जाना चाहिए और इसके बजाए साक, इसके और सदरा को उत्पादक माना जाना चाहिए। ऐसा दावा अत्यधिक विवादित है।
- (भ) उत्पादक-निर्यातक अपना उत्पादन शुरू करने की तारीख को विनिश्चित करने के प्रति भी अनिच्छुक है और यदि उन्होंने वाणिज्यिक उत्पादन मार्च, 2016 में शुरू किया था, तो जनवरी, 2016 में वे कैसे आपूर्ति करना शुरू कर सकते थे। इससे यह स्पष्ट पता चलता है कि उनका प्रकटन सही नहीं है, जिससे प्रश्नावली के उनके उत्तर को खारिज करना यथोचित बनता है।
- (म) केवल सबुको द्वारा उत्पादन के क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। तथापि, साँक और सदरा (इन दोनों संयुक्त उद्यम कंपनियों) ने भी प्रारंभिक लागत का समायोजन करने का दावा किया है।
- (य) सबुको और उसकी तीन संयुक्त उद्यम प्रवर्तकों के बीच “टोलिंग करार” की बारीकी से जांच की जानी चाहिए।
- (र) तीन संयुक्त उद्यम कंपनियां, साबिक जैसी बड़ी कंपनियों के स्वामित्वाधीन हैं। उनकी सहायक कंपनियों के बीच संबंध की अवस्था के बारे में कोई प्रकटन नहीं किया गया है जिससे कि इनपुट और सेवाओं के स्रोत जैसी प्रासंगिक सूचना का पता चल सके।
- (ल) सदरा ने यह दावा किया है कि उसने संबंधित और गैर-संबंधित कंपनियों से प्रोपलीन की खरीदारी की है। संबंधित आपूर्तिकर्ता से प्रोपलीन की कीमतों की जा जांच की जा सकती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रोपलीन की खरीद निकटस्थ कीमत के स्रोत से प्राप्त की गई है।
- (व) साँक ने यह भी नहीं बताया है कि क्या उन्होंने संबंधित अथवा गैर-संबंधित पक्षकार से प्रोपलीन प्राप्त की है।

- (श) सबुको ने नार्मल बुटानोल के उत्पादन की लागत में इसो बुटानोल को श्रेय दिया है। प्राधिकारी कृपया निर्यातक द्वारा दावा किए गए उप-उत्पाद के श्रेय की जांच कर सकते हैं।
- (स) सबुको द्वारा प्रायोगिक उत्पादन शुरू करने की वास्तविक तारीख की जांच की जा सकती है।
- (ह) सबुको ने यह बताया है कि केवल प्रोपलीन की आपूर्ति प्रवर्तक कंपनियों द्वारा की जा रही है। यह बयान स्पष्ट रूप से झूठा है और ऐसा दावा भ्रामक है। प्रचालनों के लिए अन्य सुविधाओं के मूल्यांकन के बारे में उत्तर में मुख्य तथ्यों को छिपाया गया है।
- (क्ष) क्या सबुको ने टोलिंग प्रभागों के माध्यम से संयुक्त उद्यमों से लाभ के साथ टोलिंग के सभी व्यय को वसूल किया है?
- (त्र) क्या अन्य संबंधित कंपनियों से निकटस्थ कीमत पर विभिन्न इनपुट प्राप्त की गई हैं? सदरा ने दावा किया है कि उसने संबंधित और गैर-संबंधित कंपनियों से प्रोपलीन की खरीदारी की है। संबंधित आपूर्तिकर्ता से प्रोपलीन की कीमतों की जांच की जा सकती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रोपलीन को स्रोत की निकटस्थ कीमत पर खरीदा गया है।
- (ज्ञ) इन कंपनियों द्वारा घरेलू बिक्रियां, निचले स्तर के उत्पाद का उत्पादन करने के लिए संबंधित पक्षकार को की गई बिक्रियां बन सकती हैं, जिसके फलस्वरूप अर्थक्षम घरेलू बिक्रियां नहीं होना हो सकता है।
- (श्र) सबुको द्वारा शेल गैस प्रयुक्त की गई है, जिसका मूल्यांकन है।
- (कक) सबुको ने टासनी वाणिज्यिक परिसर स्थापित किया है। सबुको का घोषित पता पोस्ट बॉक्स नंबर है और डाक का पता नहीं है।

घ.2 निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

19. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के बारे में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (क) पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए याचिकादाता द्वारा प्रयुक्त की गई कार्य-प्रणाली, नियम 5 (2) के अनुच्छेद 5.2 में निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन है। प्राधिकारी को याचिकादाता द्वारा प्रयुक्त की गई कार्य-प्रणाली को खारिज कर दिया जाना चाहिए और निर्यातकों के ईक्यूआर में प्रदत्त सूचना के आधार पर पाटन मार्जिन का निर्धारण करना चाहिए।
- (ख) सीएनवी कार्य-प्रणाली और निर्यात कीमत के समायोजन के बारे में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है।
- (ग) जांच शुरू करने की सूचना यह दावा करती है कि सामान्य मूल्य की संरचना करने के लिए प्रयुक्त कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें प्रयुक्त की गई हैं, जबकि याचिकादाता का यह तर्क है कि याचिकादाता की कच्चे माल की कीमतें प्रयुक्त की गई हैं।
- (घ) मेसर्स सऊदी बुटानोल कंपनी ("सबुको") द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-
 - (1) सबुको सदरा केमिकल कंपनी, सऊदी एक्रेलिक एसिड कंपनी और सऊदी कयान पेट्रोकेमिकल कंपनी द्वारा बनाई गई एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। सबुको तीन संयुक्त उद्यम कंपनियों के लिए टोलिंग आधार पर प्रोपलीन को नार्मल बुटानोल और ईसो बुटानोल में परिवर्तित करती है। उसके बाद तीनों कंपनियां संबद्ध वस्तुओं को घरेलू बाजार में बेचने के साथ-साथ विदेशी बाजारों में निर्यात करने का कार्य करती हैं।
 - (2) उत्पाद का विनिर्माण करने के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री प्रोपलीन और सिनगैस/ओक्सोगैस है।
 - (3) सऊदी बुटानोल कंपनी ने 1 मार्च, 2016 को संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करना शुरू किया था और प्रारंभिक लागत का समायोजन करने के लिए अनुरोध किया था।

- (4) प्रक्रिया के दौरान सृजित उप-उत्पाद, बुटानोल ऑफ गैस है। संबंधित उत्पाद की उत्पादन लागत का निर्धारण करते समय बुटानोल ऑफ गैस से वसूल की गई धनराशि को क्रेडिट के रूप में माना जाता है।

(ड) सदरा द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) सदरा केमिकल कंपनी ऐसी तीन कंपनियों में से एक है, जिसने सऊदी बुटानोल कंपनी बनाने के लिए एक संयुक्त उद्यम करार किया है।
- (2) अन्य दो संयुक्त उद्यम कंपनियों के साथ सदरा केमिकल कंपनी सबुको को टोयलिंग आधार पर प्रोपलीन की आपूर्ति, एनबीए और ईसो बुटानाले में परिवर्तित करने के लिए करती है।
- (3) पेट्रोक्म मिडल ईस्ट एफजेडई के माध्यम से सदरा केमिकल कंपनी, भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यात करती है।

(च) मेसर्स सऊदी एक्रेलिक एसिड कंपनी (साक) द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) सऊदी एक्रेलिक एसिड कंपनी ऐसी तीन कंपनियों में से एक है, जिसने सऊदी बुटानोल कंपनी बनाने के लिए एक संयुक्त उद्यम करार किया है।
- (2) अन्य दो संयुक्त उद्यम कंपनियों के साथ सऊदी एक्रेलिक एसिड कंपनी सबुको को टोयलिंग आधार पर प्रोपलीन की आपूर्ति, एनबीए और ईसो बुटानाले में परिवर्तित करने के लिए करती है।
- (3) उसके बाद सदरा सऊदी एक्रेलिक एसिड कंपनी बुटानोल का घरेलू बाजार और निर्यात बाजारों में बेचती है।
- (4) नेशनल इंडस्ट्रियलाईजेशन पेट्रोकेमिकल मार्किटिंग कंपनी के माध्यम से सऊदी एक्रेलिक एसिड कंपनी भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यात करती है, जो बाद में सीधे अथवा पेट्रोक्म मिडल ईस्ट एफजेडई और टोयटा ट्वांशो कार्पोरेशन के माध्यम से भारत के ग्राहकों को निर्यात करती है।

(छ) पेट्रोक्म मिडल ईस्ट एफजेडई द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) पेट्रोक्म मिडल ईस्ट एफजेडई स्वतंत्र क्षेत्र का एक उद्यम है, जो कि जेबेल अली फ्री जोन अथोरिटी, दुबई, सऊदी अरब में स्थित है।
- (2) सऊदी एक्रेलिक एसिड कंपनी और सदरा केमिकल कंपनी दोनों के लिए पेट्रोक्म मिडल ईस्ट एफजेडई, सबुको से उनके द्वारा अधिप्राप्त किए गए बुटानोल के लिए एक निर्यातक के रूप में कार्य करती है।

(ज) पेट्रोक्म मिडल ईस्ट एफजेडई द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

पेट्रोक्म मिडल ईस्ट एफजेडई स्वतंत्र क्षेत्र का एक उद्यम है, जो कि जेबेल अली फ्री जोन अथोरिटी, दुबई, सऊदी अरब में स्थित है। सऊदी एक्रेलिक एसिड कंपनी और सदरा केमिकल कंपनी दोनों के लिए पेट्रोक्म मिडल ईस्ट एफजेडई, सबुको से उनके द्वारा अधिप्राप्त किए गए बुटानोल के लिए एक निर्यातक के रूप में कार्य करती है।

(झ) नेशनल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रियलाईजेशन मार्किटिंग कंपनी (टान्सी मार्किटिंग) द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) टान्सी मार्किटिंग एक सीमित देयता वाली कंपनी है जो कि रियाध, सऊदी अरब राज्य में पंजीकृत है।

- (2) टान्सी मार्किटिंग सऊदी एक्रेलिक एसिड कंपनी के लिए एक विपणन कंपनी के साथ-साथ निर्यातक के रूप में कार्य करती है।
- (3) यह सऊदी एक्रेलिक एसिड कंपनी से अधिप्राप्त की गई संबद्ध वस्तुओं का सीधे निर्यात करती है अथवा ऐसी वस्तुओं को अन्य व्यापारिक कंपनियों को अंतरित करती है जो बाद में उन्हें भारत को निर्यात करती है।
- (ज) टोयटा ट्रांसपोर्टेशन ने यह निवेदन किया है कि वह टान्सी मार्किटिंग द्वारा वस्तुओं को अधिप्राप्त करके सऊदी एक्रेलिक एसिड कंपनी के लिए निर्यातक के रूप में कार्य करती है।
- (ट) सऊदी अरब दूतावास द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-
- (1) वर्तमान जांच के लिए जांच अवधि अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 तक की है। यह तथ्य स्वीकार किया जाता है कि जांच अवधि से पहले और साथ ही जांच अवधि के प्रथम नौ महीनों के दौरान सऊदी अरब से कोई आयात नहीं किया गया था। सऊदी अरब से आयात जांच अवधि के अंतिम तीन महीनों में किए गए थे, जो कि 8,791 मी.टन के थे।
 - (2) 1 मार्च, 2016 को सऊदी अरब में नार्मल बुटानोल का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ था। सऊदी अरब से प्रायोगिक उत्पादन के उत्पाद के कुछ निर्यात भारत को जनवरी, 2016 और फरवरी, 2016 में किए गए थे। चूंकि जनवरी, 2016 – मार्च, 2016 के तीन महीनों के दौरान सऊदी अरब से आयात हुए थे, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विचारित जांच अवधि वास्तव में घट कर तीन महीनों की कर दी गई है हालांकि तकनीकी दृष्टि से इसे एक वर्ष की अवधि दर्शाया गया है। यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी संबद्ध जांच को निरंतर जारी रखते हैं और पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के विद्यमान होने का निर्धारण करते हैं, तो इससे यह स्पष्ट होगा कि निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने विश्लेषण के लिए जांच अवधि के बतौर केवल तीन महीनों की अल्पावधि पर ही विचार कर रहे हैं और न कि एक वर्ष, जैसा कि जांच शुरू करने की सूचना में बताया गया है।
 - (3) तीन महीनों के आयात के आंकड़े पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध का मूल्यांकन करने के लिए अपर्याप्त हैं। हालांकि पाटन-रोधी करार में जांच अवधि की न्यूनतम अवधि के बतौर कोई विनिश्चित अवधि उल्लिखित नहीं की गई है, फिर भी विश्व व्यापार संगठन की पाटन-रोधी पद्धतियों संबंधी समिति द्वारा की गई सिफारिशें निम्नानुसार हैं:-
 “पाटन की जांच करने के लिए आंकड़ों का संग्रहण करने की अवधि सामान्यतया बारह महीनों की होनी चाहिए और किसी भी स्थिति में यह जांच शुरू करने की तारीख से निकटस्थ समाप्त होने वाली छः महीनों से अनधिक नहीं होनी चाहिए, जो कि व्यवहार्य है।”
 इस प्रकार समिति यह मानती है कि जांच अवधि ऐसी होनी चाहिए कि पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध का मूल्यांकन करने के लिए उसमें कम से कम छः महीनों के आयात के आंकड़े होने चाहिए।
 कम से कम छः महीनों की अवधि के आयात के आंकड़े इस लिए आवश्यक हैं क्योंकि एक, दो अथवा तीन महीनों की अल्पावधि के आधार पर पाटन के संबंध में एक निर्णायक और विश्वसनीय निष्कर्ष निकाला जाना संभव नहीं होगा। विश्व व्यापार संगठन के पाटन-रोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1 और भारतीय पाटन-रोधी नियम के अनुबंध 1, पैरा 2 (1) में भी निर्यातक द्वारा की गई घरेलू बिक्रियों के संबंध में न्यूनतम छः महीनों के आंकड़े होने का प्रावधान है, जो कि सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए अनिवार्य हैं। इसलिए यह तर्क संगत है कि आयात के कारोबार भी न्यूनतम छः महीनों की अवधि के लिए होने चाहिए ताकि उचित तुलना की जा सके।

दूसरे, संबद्ध देश से आयात की मात्रा प्रारंभिक बिन्दु होता है और यह क्षति का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना होती है। तीन महीनों की अल्पावधि, (क) घरेलू बाजार में कीमतों पर आयातों की मात्रा और कीमत के प्रभाव और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर उसके प्रभाव का सही और निष्पक्ष छवि प्रस्तुत नहीं कर सकती है।

तीसरे, तीन महीनों की अल्पावधि, कारणात्मक संबंध का सार्थक मूल्यांकन भी नहीं कर सकेगी। यह प्रमाणित करना संभव नहीं है कि क्षति की 4 वर्षों की समस्त जांच अवधि में और विशेषकर जांच अवधि में जनवरी से मार्च, 2016 की तीन महीनों के दौरान आयातों के कारण उद्योग को क्षति हुई है।

- (4) केवल तीन महीनों के आयात के आंकड़ों से पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के विद्यमान होने के बारे में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा कोई कानूनी और न्यायसंगत निर्धारण नहीं किया जा सकता है। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच शुरू करना और जांच अवधि का चयन करना स्पष्टतया असामयिक है। इस प्रकार सऊदी अरब राज्य का निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे सऊदी अरब के खिलाफ शुरू की गई जांच को समाप्त कर दें।

(ठ) सऊदी कयान पेट्रोकेमिकल कंपनी द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) सऊदी कयान पेट्रोकेमिकल कंपनी ने सऊदी एक्रेलिक एसिड कंपनी ("साँक") और सदरा केमिकल कंपनी ("सदरा") के साथ मिल कर एक संयुक्त उद्यम कंपनी, मेसर्ज सऊदी बुटानोल कंपनी ("सबुको") स्थापित की है, जिसमें प्रत्येक की एक-तिहाई शेयर-धारिता है। सऊदी कयान पेट्रोकेमिकल कंपनी, सऊदी एक्रेलिक एसिड कंपनी और सदरा केमिकल कंपनी मेसर्ज सऊदी बुटानोल कंपनी को प्रोपलीन की आपूर्ति करती है और वह इन तीन उत्पादकों के लिए टोयलिंग आधार पर प्रोपलीन को नार्मल बुटानोल और ईसो बुटानोल में परिवर्तित करती है।
- (2) सऊदी कयान पेट्रोकेमिकल कंपनी ने जांच अवधि (1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक) के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यात नहीं किए हैं। इसके अतिरिक्त सऊदी कयान पेट्रोकेमिकल कंपनी, सऊदी अरब में ऐसे किसी निर्यातक अथवा उत्पादक से भी संबंधित नहीं है, जिसने जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यात किए हैं।
- (3) यदि संबद्ध जांच में प्राधिकारी उसके खिलाफ पाटन-रोधी शुल्क की सिफारिश करते हैं, तो पाटन-रोधी नियम, 1995 के नियम 22 के अनुसार सऊदी कयान पेट्रोकेमिकल कंपनी, न्यू शिपर समीक्षा के लिए अपने सुरक्षित अधिकार को प्रयुक्त करना चाहेगी।

(ड) उपरोक्त के अतिरिक्त सऊदी अरब नामतः सऊदी बुटानोल कंपनी, सऊदी एक्रेलिक एसिड कंपनी, सदरा केमिकल कंपनी, नेशनल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रियलाइजेशन मार्किटिंग कंपनी, टोयटा ट्ओशो कार्पोरेशन, पेट्रोकेम मिडल ईस्ट एफजेडई से उत्पादकों/निर्यातकों की प्रतिनिधि, मेसर्ज लक्ष्मी कुमारन एंड श्रीधरन एटोर्नीज द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- जांच अवधि का चयन अनुचित है। संबद्ध देश से भारत को निर्यात जांच अवधि के दौरान केवल तीन महीनों में किए गए हैं। वास्तव में प्राधिकारी द्वारा विचारित जांच अवधि केवल 3 महीनों के लिए है, हालांकि तकनीकी रूप से इसे एक वर्ष का नाम दिया गया है। विश्व व्यापार संगठन की पाटन-रोधी पद्धतियों संबंधी समिति की यह सिफारिश है कि पाटन की जांच करने के लिए आंकड़ों का संग्रहण करने की अवधि सामान्यतया बारह महीनों की होनी चाहिए और किसी भी स्थिति में यह जांच शुरू करने की तारीख से निकटस्थ समाप्त होने वाली छः महीनों से अनधिक नहीं होनी चाहिए, जो कि व्यवहार्य है। पाटन का मूल्यांकन करने के लिए तीन महीनों के आयात के आंकड़े

अपर्याप्त हैं। अल्पावधि के आयात के आंकड़े, पाटन के बारे में एक निर्णायक और विश्वसनीय छवि नहीं देंगे। अन्य ज्ञात कारकों से होने वाली क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। केवल तीन महीनों के आयात के आंकड़ों से पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के विद्यमान होने के बारे में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा कोई कानूनी और न्यायसंगत निर्धारण नहीं किया जा सकता है। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जांच अवधि का चयन करना असामयिक है। इसलिए वर्तमान जांच को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

- पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए याचिकादाता द्वारा प्रयुक्त की गई कार्य-प्रणाली, नियम 5 (2) के अनुच्छेद 5.2 में निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन है। प्राधिकारी को याचिकादाता द्वारा प्रयुक्त की गई कार्य-प्रणाली को खारिज कर दिया जाना चाहिए और निर्यातकों के निर्यातक की प्रश्नावली में प्रदत्त सूचना के आधार पर पाटन मार्जिन का निर्धारण करना चाहिए।

क. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित शंकाएं व्यक्त की हैं जिनका उत्तर दे दिया गया है:-

- 1) चूंकि इन कंपनियों द्वारा तथ्यों को छिपाया गया है, इसलिए प्रश्नावली के उनके उत्तरों को खारिज किया जाना यथोचित है।
- (2) विशिष्ट बाजार स्थिति के विद्यमान होने से स्पष्ट पता चलता है घरेलू बिक्री कीमत को खारिज किया गया है।
- (3) संबंधित प्रयोज्यताओं से प्रचालनों और आदानों के जटिल जाल से मूल कंपनियों द्वारा अत्यधिक समर्थन किए जाने के कारण दावा की गई उत्पादन की लागत अत्यधिक कम बताई गई है।
- (4) उत्पादक-निर्यातकों ने यह दावा किया है कि सबुको को उत्पादक नहीं माना जाना चाहिए और इसके बजाए सॉक, एसके और सदरा को उत्पादक माना जाना चाहिए। ऐसा दावा अत्यधिक विवादित है।
- (5) उत्पादक-निर्यातक अपना उत्पादन शुरू करने की तारीख को विनिश्चित करने के प्रति भी अनिच्छुक है और यदि उन्होंने वाणिज्यिक उत्पादन मार्च, 2016 में शुरू किया था, तो जनवरी, 2016 में वे कैसे आपूर्ति करना शुरू कर सकते थे।
- (6) केवल सबुको द्वारा उत्पादन के क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। तथापि, सॉक और सदरा (इन दोनों संयुक्त उद्यम कंपनियों) ने भी प्रारंभिक लागत का समायोजन करने का दावा किया है।
- (7) प्राधिकारी को सबुको और उसकी तीन संयुक्त उद्यम प्रवर्तकों के बीच “टोलिंग करार” की भी बारीकी से जांच करनी चाहिए।
- (8) सदरा ने प्रयुक्त की गई समस्त सामग्री/इनपुट की खरीदारी और खपत करने से संबंधित प्रश्नों के उत्तर में यह दावा किया है कि उसने संबंधित और गैर-संबंधित कंपनियों से प्रोपलीन की खरीदारी की है। याचिकादाता का प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे कृपया संबंधित आपूर्तिकर्ता से प्रोपलीन की कीमतों की जांच करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसे स्रोत से प्रोपलीन की खरीद निकटस्थ कीमत पर की गई थी।
- (9) सॉक ने प्रयुक्त की गई समस्त सामग्री/इनपुट की खरीदारी और खपत करने से संबंधित प्रश्नों के उत्तर में यह उल्लिखित किया है कि “कृपया परिशिष्ट-6 को देखें”। परिशिष्ट-6 में समस्त सूचना की गोपनीयता का दावा किया गया है। कंपनी ने यह नहीं बताया है कि क्या उन्होंने संबंधित अथवा गैर-संबंधित पक्षकार से प्रोपलीन प्राप्त की है। याचिकादाता ऐसी कठिनाई को समझने में असमर्थ है, जो कि निर्यातकों ने बहुत सरल प्रश्न का उत्तर देने में अनुभव की है।
- (10) सबुको ने नार्मल बुटानोल के उत्पादन की लागत में इसी बुटानोल को श्रेय दिया है। प्राधिकारी कृपया निर्यातक द्वारा दावा किए गए उप-उत्पाद के श्रेय की जांच कर सकते हैं।

ख. घरेलू उद्योग के उपरोक्त संदेहों के बारे में, मुद्देवार उत्तर निम्नानुसार हैं :

- (1) आरोप अस्पष्ट और गैर-प्रमाणित हैं। प्राधिकारी ने मुख्य तथ्यों को छिपाने के बारे में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है।
- (2) वर्तमान मामले में कोई विशिष्ट बाजार स्थिति नहीं है। साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं है कि घरेलू उद्योग की किस विशिष्ट बाजार स्थिति का उल्लेख किया जा रहा है। जैसा कि नोट किया गया है, प्राधिकारी द्वारा घरेलू बिक्रियों के संबंध में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया से संबंधित जांच की जानी है।
- (3) घरेलू उद्योग के पास उत्पादन की लागत के ब्यौरे नहीं हैं। उत्पादक, टोल विनिर्माताओं और व्यापारियों ने पूरे उत्तर प्रस्तुत किए हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने समस्त सूचना की जांच की है। घरेलू उद्योग का आरोप निराधार है।
- (4) आरोप निराधार है। इस संबंध में प्रस्तुत किए गए प्रत्युत्तर के परवर्ती भाग में स्पष्टीकरण और पूर्व दृष्टांत प्रस्तुत किए गए हैं।
- (5) आरोप झूठा और असंगत है। वाणिज्यिक उत्पादन 1 मार्च, 2016 को शुरू हुआ था। प्रायोगिक उत्पादन 1 मार्च, 2016 से पूर्व शुरू हुआ था।
- (6) जैसा कि नोट किया गया है, साक और सदारा उत्पादक हैं। यह प्राधिकारी की सुसंगत पद्धति के अनुसार है।
- (7) प्रतिवादी घरेलू उद्योग से सहमत है। टोलिंग करार की जांच सावधानी पूर्वक की जानी चाहिए।
- (8) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने समस्त कीमतों की जांच की है।
- (9) आरोप झूठा है। साक ने सभी आवश्यक ब्यौरे प्रदान किए हैं। घरेलू उद्योग गोपनीयता के दावों और उत्तर नहीं दिए जाने से भ्रमित है।
- (10) प्रतिवादी इस विचार से सहमत हैं कि निर्दिष्ट प्राधिकारी कृपया श्रेय की जांच करें।
 - प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों को मात्र इस कारण से खारिज नहीं किया जा सकता है कि घरेलू उद्योग प्रतिवादियों के प्रचालनों को समझने में असमर्थ है। प्रतिवादी निर्दिष्ट प्राधिकारी को पूरा सहयोग दे रहे हैं और उन्होंने निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने उत्तर प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने निर्दिष्ट प्राधिकारियों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए हैं और निर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्रतिवादियों के परिसरों में वास्तविक जांच भी की है। इस प्रकार सूचना देने से मनाही करने अथवा आवश्यक सूचना नहीं देने का कोई मामला नहीं है और इसलिए उपलब्ध तथ्यों का उपयोग करने का कोई आधार नहीं है।
 - घरेलू उद्योग यह उल्लेख करने में गलती की है कि सऊदी अरब में विचाराधीन उत्पाद के वास्तविक उत्पादक के बारे में संदेह हैं। प्रतिवादियों के प्रचालन बहुत सरल हैं। साक, सऊदी कयान ("एसके") और सदारा ने एक संयुक्त उद्यम कंपनी सबुको स्थापित की है। सबुको में प्रत्येक प्रवर्तक कंपनी की एक तिहाई शेयर-धारिता है। साक, एसके और सदारा सबुको को प्रोपलीन की आपूर्ति करती हैं और वह साक, एसके और सदारा के लिए टोलिंग आधार पर प्रोपलीन को नार्मल बुटानोल और ईसा बुटानोल में परिवर्तित करती है। प्रवर्तक कंपनियों द्वारा इसके संसाधन प्रभागों का भुगतान सबुको को किया जाता है। प्रोपलीन और बुटानोल की स्वामित्वाधिकार। साक, एसके और सदारा के पास है। नार्मल बुटानोल का स्वामित्व, सबुको को कभी भी अंतरित नहीं किया गया है। केवल इन प्रवर्तक कंपनियों द्वारा नार्मल बुटानोल को बेचा जाता है और न कि सबुको द्वारा। उत्पादन की उपरोक्त श्रृंखला से यह स्पष्ट है कि सबुको टोल संसाधक है और सदारा, साक और एसके संबद्ध वस्तुओं की उत्पादक हैं। जांच अवधि के दौरान सदारा द्वारा एक गैर-संबंधित व्यापारी कंपनी, पेट्रोकेम मिडल ईस्ट के माध्यम से भारत को निर्यात किए गए थे। एक टोल संसाधक को विनिर्माता अथवा उत्पादक नहीं माना जा सकता है, जहां उसके पास वस्तुओं का स्वामित्व अधिकार नहीं है और संबद्ध निर्यात अथवा घरेलू बिक्रियां उसके नियंत्रण में नहीं है। यह भारत में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई सुसंगत पद्धति में भी परिलक्षित होता है। यूरॉपियन यूनियन मूल की अथवा वहां से निर्यातित बल्क ड्रग सेफाड्रोक्सिल मोनोहाईड्रेट से संबंधित पाटन-रोधी जांच में निर्यातक देशों में टोल विनिर्माण के तथ्य समान थे। डीएसएम नीदरलैंड ने डीएसएम स्पेन को 7-एडीसीए की आपूर्ति, संबद्ध वस्तुओं का विनिर्माण करने के लिए आवश्यक अन्य कच्चे माल/इनपुट के साथ की थी। डीएसएम स्पेन ने स्पेन में स्थित अपने संयंत्र में संबद्ध

वस्तुओं का विनिर्माण करने के लिए विनिर्माण प्रक्रिया की थी। अंतिम विनिर्माण कार्य करने के लिए डीएसएम स्पेन को टोलिंग शुल्क का भुगतान किया गया था। उसके बाद डीएसएम नीदरलैंड द्वारा संबद्ध वस्तुओं को यूरोपीय यूनियन के भीतर घरेलू बाजार में अथवा यूरोपीय यूनियन से बाहर निर्यात बाजार में बेचा गया था। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने डीएसएम नीदरलैंड को संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक और निर्यातक माना था। प्राधिकारी ने डीएसएम नीदरलैंड के उत्तर को स्वीकार किया था और प्रश्नावली के उत्तर में दिए गए आंकड़ों के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण किया था। ऐसा कोई कारण नहीं है कि प्राधिकारी इस संबंध में स्थापित पद्धति से विचलित हो। विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और निर्यात के बारे में सरल तथ्य परक स्थिति को समझने में घरेलू उद्योग की असमर्थता अथवा अनिच्छा, उत्तर को खारिज कर दिए जाने का आधार नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग इसके के उत्तर नहीं देने को, समस्त सूचना को खारिज कर दिए जाने का आधार नहीं मान सकता है। यह विवादास्पद नहीं है कि इसके ने जांच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का सीधे अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यापारी के माध्यम से कोई निर्यात नहीं किया है। इस प्रकार इस जांच के प्रयोजनार्थ इसके द्वारा कोई आवश्यक सूचना प्रदत्त नहीं की जानी है। इससे सऊदी अरब से उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की संपूर्णता प्रभावित नहीं होती है। जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए उत्पादन और निर्यात की समग्र मूल्य श्रृंखला संपूर्ण है।

- घरेलू उद्योग ने सामान्यतया यह भी दावा किया है कि सभी तीन प्रवर्तक कंपनियां आपस में संबंधित हैं। पहले, पक्षकारों के बीच संबंध घरेलू उद्योग की परिभाषा के लिए प्रासंगिक है और निर्यातकों के मामले में स्वतः प्रासंगिक नहीं है। हालांकि यह मानते हैं कि ये कंपनियां परस्पर संबंधित हैं, फिर भी ऐसी कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है कि संबंधित कंपनियां जांच में भाग लें, यदि वे विचाराधीन उत्पाद की मूल्य श्रृंखला का भाग नहीं हैं। इस प्रकार घरेलू उद्योग ऐसा कोई भी कानूनी प्रावधान बताने में विफल है, जहां निर्यातक देशों में संयुक्त उद्यम की प्रवर्तक कंपनियों को संबंधित कंपनियां माना जाता है।
- घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि इस तथ्य के कारण कि घरेलू बिक्रियां संबंधित पक्षकारों को की जाती हैं, अर्थक्षम घरेलू बिक्रियां नहीं हो सकती हैं। यह निवेदन है कि सऊदी अरब में उत्पादकों द्वारा की गई घरेलू बिक्रियों पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए विचार किया जाता है, यदि ऐसी बिक्रियों का निर्धारण, पाटन-रोधी नियम, 1995 के अनुबंध के साथ सदंर्भित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 (क) के अनुसार व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में किया जाता है। घरेलू बिक्रियों की स्वीकार्यता के साथ कोई अतिरिक्त शर्त नहीं लगाई गई है।
- याचिका में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आर्थिक प्राचलों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, जो कि वस्तुतः उसकी अपनी लागत और खपत के अनुपात पर आधारित है। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ ऐसी सूचना की अप्रासंगिकता के संबंध में विस्तृत निवेदन पहले से ही किए गए हैं और उनको यहां दोहराया नहीं जाता है।
- घरेलू उद्योग का प्राधिकारी से यह अनुरोध है कि वे निर्यात कीमत का परिकलन करने के लिए याचिका में प्रस्तुत साक्ष्य पर विश्वास करें। ऐसी सूचना इस लिए अनावश्यक है क्योंकि प्रतिवादी वर्तमान जांच में सहयोग कर रहे हैं और निर्यात कीमत का परिकलन करने के लिए प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों पर विचार किया जाना चाहिए। यदि घरेलू उद्योग सऊदी अरब से प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर को खारिज करने के लिए कोई न्यायोचित कारण नहीं दे सकता है, तो इस तर्क का कोई वैध आधार नहीं हो सकता है कि निर्यात कीमत का परिकलन, घरेलू उद्योग द्वारा अपनी याचिका में प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर किया जाना चाहिए। इस प्रकार पर्याप्त पाटन मार्जिन से संबंधित ऐसे दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, जो कि काल्पनिक सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर आधारित है।

प्राधिकारी द्वारा जांच**सामान्य मूल्य का निर्धारण**

20. प्राधिकारी ने प्रश्नावलियां संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को प्रेषित की थीं और उनसे अनुरोध किया था कि वे निर्धारित प्रपत्र और तरीके से सूचना प्रदान करें। निम्नलिखित पक्षकारों ने निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:-

- (क) सऊदी बूटानोल कंपनी
- (ख) सऊदी एक्रेलिक एसिड कंपनी
- (ग) सदारा केमिकल कंपनी
- (घ) नेशनल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रियलाइजेशन मार्केटिंग कंपनी (टसनी)
- (ङ) टोयटा टसुशो कार्पोरेशन
- (च) पेट्रोकेम मिडल ईस्ट एफजेडई

सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए सामान्य कार्य-प्रणाली

21. प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में जहां कहीं भी लागू होता है, यह निर्धारित किया है कि क्या संबद्ध देश में उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं की कुल घरेलू बिक्रियां, भारत में संबद्ध वस्तुओं के निर्यातों के साथ तुलना करने पर प्रतिनिधिक होती हैं।

22. उसके बाद यह जांच की गई है कि क्या उनकी बिक्रियां, पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 2 के अनुसार व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के दौरान की जाती है। जहां कहीं भी उत्पादकों/निर्यातकों ने घरेलू बाजार में की गई बिक्रियों के कारोबार-वार आंकड़े प्रस्तुत किए हैं और उन्हें प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, घरेलू बाजार में बेची गई संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए उक्त सूचना पर विश्वास किया गया है।

23. व्यापार परीक्षण की सामान्य कार्यवाही करने के लिए सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए यथा निर्धारित संबद्ध उत्पाद के उत्पादन की लागत का उल्लेख किया गया है और उसकी तुलना घरेलू बिक्री कीमत से की गई है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या घरेलू बिक्रियां व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के दौरान की गई हैं अथवा नहीं। प्राधिकारी ने सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए घरेलू बाजार में लेनदेन को नोट किया है जहां संदर्भित जांच अवधि के दौरान घरेलू बिक्री कीमत मात्रा की 80% से कम लाभप्रद लेनदेन हुआ है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए केवल लाभप्रद बिक्रियों पर विचार किया गया है। लाभप्रद घरेलू बिक्रियां नहीं होने के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण, उत्पादन की लागत और सहयोगी उत्पादकों के लिए यथा सत्यापित विधिवत समंजित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत और उसमें शामिल उचित लाभ के आधार पर किया गया है।

24. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने 3 उत्पादकों/निर्यातकों के बीच संबंध होने, 3 निर्यातकों को उत्पादकों के रूप में गलत ढंग से माने जाने और साथ ही केवल 2 निर्यातकों के आंशिक उत्तर पर विचार करने और तीसरे संयुक्त उद्यम सहभागी नामतः सऊदी कयान केमिकल कंपनी द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किए जाने से संबंधित मुद्दे उठाए हैं। इस संबंध में प्राधिकारी स्पष्ट करते हैं कि ऑनसाइट पर यथा सत्यापित लेखा बहिओं/संबद्ध वित्तीय और वाणिज्यिक दस्तावेजों के अनुसार उत्पादकों/निर्यातकों के आंकड़ों पर विचार किया गया है और तदनुसार “पाटन मार्जिन” का मूल्यांकन किया गया है। संबंध होने से संबंधित मुद्दे को भी माना गया है और जहां कहीं भी संबंध विद्यमान है, वहां सामान्य मूल्य का उल्लेख लागत जमा आधार पर किया गया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए विभिन्न संबद्ध मुद्दों की जांच, ऑनसाइट पर/ उत्पादकों/निर्यातकों के रिकार्डों से की है। कच्चे माल और अंतिम वस्तुएं अर्थात् संबद्ध वस्तुओं का स्वामित्व उत्पादक/निर्यातक के रूप में, मै. साक, मै. सदारा और मै. सउदी

कयान को मानने के आधार पर किया गया है। मै. सबुको सहमत व्यवस्था के अनुसार इन तीन उत्पादकों/निर्यातकों के लिए टोलिंग/प्रसंस्करण के क्रियाकलाप करता है।

25. प्राधिकारी ने सऊदी अरब में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के संबंध यह भी नोट किया है कि-

- (क) सऊदी एक्रेलिक एसिड कंपनी ("साक"), पेट्रोकेमिकल कंपनी ("सऊदी कयान") और सदारा केमिकल कंपनी ("सदारा") ने मेसर्ज सऊदी बुटानोल कंपनी ("सबुको") नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित की है, जिसमें प्रत्येक कंपनी की एक-तिहाई शेयर-धारिता है।
- (ख) सऊदी कयान पेट्रोकेमिकल कंपनी, सऊदी एक्रेलिक एसिड कंपनी और सदारा केमिकल कंपनी मेसर्ज सऊदी बुटानोल कंपनी को प्रोपलीन की आपूर्ति करती है और वह इन तीन उत्पादकों के लिए टोलिंग आधार पर प्रोपलीन को नार्मल बुटानोल और ईसो बुटानोल में परिवर्तित करती है। सबुको ने 1 मार्च, 2016 को संबद्ध वस्तुओं का वाणिज्यिक उत्पादन करना शुरू किया था। पक्षकारों ने इस आधार पर प्रारंभिक लागत के समायोजन का दावा किया है कि जांच अवधि के दौरान यूनिट प्रारंभ होने के चरण में था।
- (ग) प्रोपलाईन का स्वामित्व और साथ ही नार्मल बुटानोल सदैव साक, सऊदी कयान और सदारा के पास रहता है।
- (घ) साक, सऊदी कयान और सदारा एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं। टोलिंग पर सबुको के साथ उनका करार वाणिज्यिक व्यवस्था पर आधारित है, जो कि इन 3 प्रयोज्यताओं को एक दूसरे से संबंधित नहीं बनाती है।
- (ङ) साक और सदारा ने अपने संबंधित/गैर-संबंधित निर्यातकों के साथ संबद्ध जांच में भाग लिया है क्योंकि उन्होंने जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यात किए हैं।
- (च) सऊदी कयान ने संबद्ध जांच में इसलिए भाग नहीं लिया है क्योंकि उसने जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यात नहीं किए हैं।

सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों का सामान्य मूल्य

मेसर्ज सदारा केमिकल कंपनी (सदारा) (उत्पादक) के लिए सामान्य मूल्य

26. जांच अवधि के दौरान सदारा ने घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं को बेचा है। घरेलू बाजार में की गई सभी बिक्रियां, जांच अवधि के दौरान गैर-संबंधित पक्षकारों को की गई थीं। भारत को किए गए निर्यातों की तुलना में घरेलू बिक्रियां पर्याप्त मात्रा में की गई थीं। चूंकि सदारा द्वारा समस्त घरेलू बिक्रियां, उत्पादन की लागत जमा एसजीए पर की गई थीं, इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण उत्पादन लागत और यथा सत्यापित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत के आधार पर किया गया है और इसमें ***% का उचित लाभ शामिल है।

27. तदनुसार सदारा के लिए संबद्ध वस्तुओं के लिए कारखाना-गत स्तर पर सामान्य मूल्य का निर्धारण ***डालर/मी.टन किया गया है, जिसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

मेसर्ज सऊदी एक्रेलिक एसिड कंपनी ("साक") (उत्पादक) के लिए सामान्य मूल्य

28. जांच अवधि के दौरान साक ने संबद्ध वस्तुओं को घरेलू बाजार में बेचा है। जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में की गई सभी बिक्रियां, भारत को किए गए निर्यातों की तुलना में अपर्याप्त मात्रा में की गई थीं और ये संबंधित पक्षकार को की गई थीं। चूंकि समस्त घरेलू बिक्रियां, उत्पादन की लागत जमा एसजीए से कम पर की गई थीं,

इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण उत्पादन लागत और यथा सत्यापित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत के आधार पर किया गया है और इसमें ***% का उचित लाभ शामिल है।

29. तदनुसार साक के लिए संबद्ध वस्तुओं के लिए कारखाना-गत स्तर पर सामान्य मूल्य का निर्धारण ***डालर/मी.टन किया गया है, जिसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

संबद्ध देशों से असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

30. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में सऊदी अरब से किसी भी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने प्राधिकारी को कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। सऊदी अरब में सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण, सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों में उच्चतम सामान्य मूल्य का उल्लेख करते हुए, श्रेष्ठ उपलब्ध सूचना के आधार पर कारखाना-गत स्तर पर किया है, जिसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

निर्यात कीमत

मेसर्ज सऊदी एक्रेलिक एसिड कंपनी ("साक"), मेसर्ज नेशनल इंडस्ट्रियलाईजेशन पेट्रोकेमिकल मार्किटिंग कंपनी ("टासनी मार्किटिंग"), मेसर्ज टोएटो टसूशो कार्पोरेशन और मेसर्ज पेट्रोकेम मिडल ईस्ट एफजेड ईस्ट एफजेडई के लिए निर्यात कीमत

31. सऊदी अरब में संबद्ध वस्तुओं के एक उत्पादक, सऊदी एक्रेलिक एसिड कंपनी ने अपनी संबंधित व्यापारिक कंपनी, टासनी मार्किटिंग और गैर-संबंधित कंपनी नामतः मेसर्ज टोएटो टसूशो कार्पोरेशन, जापान और मेसर्ज पेट्रोकेम मिडल ईस्ट एफजेड ईस्ट एफजेडई, दुबई के साथ प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। इन व्यापारिक कंपनियों ने जांच अवधि के दौरान साक द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तुओं के निर्यात भारत को किए थे। इन सभी निर्यातकों/उत्पादकों ने अपनी प्रश्नावली के उत्तर प्राधिकारी को प्रस्तुत किए हैं।

32. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सऊदी एक्रेलिक एसिड कंपनी ने समुद्री भाड़े, बीमा और क्रेडिट व्यय के लिए समायोजन करने का दावा किया है और उनकी स्वीकृति दी गई है। तदनुसार, साक के लिए संबद्ध वस्तुओं के लिए भारित औसत निर्यात कीमत का निर्धारण, ***डालर/मी.टन किया गया है, जिसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

मेसर्ज सदारा केमिकल कंपनी ("सदारा") और मेसर्ज पेट्रोकेम मिडल ईस्ट एफजेड ईस्ट के लिए निर्यात कीमत

33. सऊदी अरब में संबद्ध वस्तुओं की उत्पादक, सदारा ने अपने गैर-संबंधित व्यापारी नामतः मेसर्ज पेट्रोकेम मिडल ईस्ट एफजेड ईस्ट एफजेडई, दुबई के साथ प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं।

34. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सदारा ने समुद्री भाड़े, बीमा और क्रेडिट व्यय के लिए समायोजन करने का दावा किया है और उनकी स्वीकृति दी गई है। तदनुसार, सदारा के लिए संबद्ध वस्तुओं के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण, ***डालर/मी.टन किया गया है, जिसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

सऊदी अरब से असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

35. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में सऊदी अरब से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्राधिकारी को कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। प्राधिकारी ने सऊदी अरब में सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण, सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों में न्यूनतम कारखाना-गत निर्यात कीमत का उल्लेख करते हुए, श्रेष्ठ उपलब्ध सूचना के आधार पर किया है, जिसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

पाटन मार्जिन

क्रमांक	उत्पादक	निर्यातक	सामान्य मूल्य	कारखाना-गत निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन
			अमरीकी डालर/मी.टन	अमरीकी डालर/मी.टन	अमरीकी डालर/मी.टन	%	सीमा
1.	सदारा	पेट्रोकेम मिडल ईस्ट एफजेड	***	***	***	***	85-95
2.	साक	टासनी मार्किटिंग	***	***	***	***	35-45
3.	साक	टासनी मार्किटिंग पेट्रोकेम मिडल ईस्ट एफजेड	***	***	***	***	35-45
4.	साक	टासनी मार्किटिंग-टोयटो ट्सुशो	***	***	***	***	35-45
5.	उपरोक्त क्रमांक (1) और (4) से भिन्न असहयोगी/बाकी उत्पादक/निर्यातक		***	***	***	***	85-95

प्राधिकारी ने इस जांच परिणाम के पैरा-93 में संबद्ध देश से आयातों की अवधि और केवल मार्च, 2016 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की पर्याप्तता की जांच की है।

इ क्षति

इ 1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

36. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (क) संबद्ध देश से आयात जनवरी, 2016 से शुरू हुए थे और मात्र तीन महीनों में ऐसे पाटित आयातों की मात्रा इतनी अधिक हो गई कि उसके कारण घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति होने लगी।
- (ख) याचिकादाता ने जांच अवधि के भीतर क्षति की समग्र सूचना को दो भागों में वर्गीकृत किया है – (1) अप्रैल, 2015 – जब संबद्ध देश से कोई आयात नहीं हुए थे और (1) जनवरी – मार्च, 2016 – जब संबद्ध देश कोई आयात होने शुरू हुए थे।
- (ग) जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति, विशेष कर संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति की मात्रा और सीमा की जांच करते समय प्राधिकारी जनवरी से मार्च, 2016 की अवधि पर अलग से विचार कर सकते हैं।
- (घ) जांच पश्चात अवधि में आयातों से पता चलता है कि जांच अवधि के दौरान आयात, भारत को आकस्मिक निर्यात नए संयंत्र से नहीं किए गए थे, बल्कि वे उत्पाद का पाटन करने के लिए संबद्ध निर्यातकों द्वारा देखा गया बाजार का एक अवसर था।
- (ङ) सबुको में स्थापित क्षमताएं, तीन प्रवर्तक कंपनियों द्वारा उत्पादन में सहभागिता और उत्पादन का उपयोग करने के लिए उनके पास विकल्प से यह भी पता चलता है कि जांच अवधि के दौरान आयात आकस्मिक नहीं थे, बल्कि इन कंपनियों का भारतीय बाजार को हथियाने के चैतन्य निर्णय थे।

- (च) घरेलू उद्योग और विदेशी उत्पादकों द्वारा पेश की जा रही कीमतों की बीच अत्यधिक अंतर है। इस प्रकार संबद्ध देश से पाति आयातों के कारण घरेलू उद्योग लागत से अधिक कीमतें बढ़ाने में असमर्थ है।
- (छ) जहां तक कि घरेलू उद्योग ने जब कभी भी उप-अनुकूलतम कीमतों की पेशकश की है, उसकी बिक्रियां कम हुई हैं। इस प्रकार उसकी बिक्रियों की मात्रा में गिरावट आना, संबद्ध देश से पाटित आयातों का सीधा परिणाम है।
- (ज) घरेलू उद्योग द्वारा पेश की गई उप-अनुकूलतम कीमतों के बावजूद आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं और घरेलू उद्योग पर कीमत का दबाव डाल रहे हैं।
- (झ) आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण कर रहे हैं और कीमत में ऐसी वृद्धि को रोक रहे हैं, जो कि पाटन नहीं होने के कारण हो जाती।
- (ञ) बिक्रियों, उत्पादन और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में सुधार हुआ है क्योंकि जांच अवधि के पहले नौ महीनों अर्थात् अप्रैल-दिसंबर, 2015 के दौरान अन्य स्रोतों से पाटन-रोधी शुल्क लागू करने की जांच की कार्रवाई चल रही थी। तथापि, जांच अवधि के अंतिम तीन महीनों अर्थात् जनवरी से मार्च, 2016 में उपरोक्त प्राचलों के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में अत्यधिक गिरावट आई है, क्योंकि संबद्ध देश से नया पाटन होना शुरू हो गया था। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी ने 19 फरवरी, 2016 को सकारात्मक जांच परिणाम अधिसूचित कर दिया था, जिसमें इन स्रोतों से आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की गई थी।
- (ट) समस्त क्षति अवधि के दौरान लाभ, निवेशों पर प्रतिलाभ और नकदी लाभ के रूप में घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन हानिकर था। जांच अवधि की जनवरी से मार्च, 2016 तक की अवधि के दौरान पाटित आयातों के शुरू होने के कारण स्थिति और बदतर हो गई।
- (ठ) पाटन मार्जिन बहुत अधिक है।
- (ड) घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित करने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण कारक संबद्ध देश से आयात की कीमत है। इस प्रकार बाजार में उत्पाद का पाटन होने के कारण कीमत न्यूनीकरण हुआ है।
- (ढ) मात्रा और कीमत दोनों प्राचलों में घरेलू उद्योग की संवृद्धि हानिकर है।
- (ण) संबद्ध देश से पाटन के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है।
- (त) क्षति मार्जिन अत्यधिक है।
- (थ) पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के अनुसार निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता है।
- (द) उपाय का रूप अमरीकी डालर में निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है।
- (ध) जांच अवधि को दो भागों में विभाजित करने का प्रयोजन, घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन पर संबद्ध वस्तुओं के पाटन के प्रभाव और क्षति के साथ उसके कारणात्मक संबंध होने को दर्शाना है।
- (न) मात्र 3 महीनों में संबद्ध वस्तुओं के पाटन का प्रभाव इतना अधिक महसूस किया गया है कि उसके कारण घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है।
- (प) दिसंबर, 2015 तक आयात, अन्य स्रोतों से विचाराधीन उत्पाद के पाटन थे और जहां मार्च, 2016 के बाद पाटन-रोधी शुल्क लगाए गए थे। जांच अवधि की अंतिम तिमाही में सऊदी अरब से संबद्ध वस्तुओं के आयात होने शुरू हुए थे और ये कम समय पर अत्यधिक होने लगे। एक स्रोत से अन्य स्रोत में अंतरण होने से यह स्पष्ट नहीं होता है कि कारणात्मक संबंध टूट गए हैं।
- (फ) विगत अवधि में याचिकादाता को प्रोपलीन के आपूर्तिकर्ता के संयंत्र में आग लगने के कारण उसके बंद होने से संबंधित मुद्दे की जांच निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पहले से ही कर ली गई है।
- (ब) वर्तमान जांच अवधि में संयंत्र के बंद होने का कारण, संबद्ध देश से कम कीमत के पाटित आयात होने के कारण बाजार में अलाभप्रद कीमतों को ध्यान में रखते हुए उत्पादन का आस्थगन करना था।

- (भ) घरेलू उद्योग को विधि के अंतर्गत संरक्षण की मांग करने से महले 100% मांग को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त उचित कीमतों पर देश में उत्पाद के आयातों पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

ड. 2 निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

37. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त किए गए विचार निम्नानुसार हैं:-

- (क) आवेदन पत्र न तो जांच शुरू किए जाने की पूर्व-शर्तों को पूरा करता है और न ही ये नियम 5 के अंतर्गत पर्याप्तता और परिशुद्धता की जांच किए जाने के योग्य है क्योंकि उसमें पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
- (ख) गोपनीयता - याचिका में प्रस्तुत किए गए अगोपनीय वृत्तान्त में कुछ सूचना भ्रामक है अथवा अपर्याप्त है, जिस पर हितबद्ध पक्षकार सार्थक टिप्पणियां नहीं कर सकते हैं। घरेलू उद्योग को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह कुछ सीमाओं में आंकड़े प्रस्तुत करें ताकि तालिका को ठीक तरह से समझा जा सके।
- (ग) याचिका में आरोपित कीमत कटौती पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। सऊदी अरब के उत्पादकों द्वारा भारतीय व्यापारियों को निर्यात किए जाते हैं, जो भंडारण और माल गोदामों पर व्यय करते हैं। ऐसी लागतों से पहुंच मूल्य में 25% से 30% तक की वृद्धि होती है। कीमत में कटौती, घरेलू उद्योग की कीमत की भारत में व्यापारियों की पुनःबिक्री की कीमत के साथ तुलना के आधार पर करनी चाहिए।
- (घ) सऊदी अरब से आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध नहीं है। वर्ष 2014-15 में सऊदी अरब से आयात शून्य थे जो कि जांच अवधि में बढ़ कर 8,791 मी.टन हो गए हैं। इसी अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्रियां भी बढ़ कर 7,111 मी.टन हो गई हैं।
- (ङ) भारत में अन्य देशों से भी पाटित कीमतों पर आयात हो रहे हैं और जांच अवधि में ये पाटन-रोधी शुल्क से मुक्त थे, जो कि जांच अवधि के पूरा होने के बाद लगाए गए थे। सऊदी अरब से आयातों ने भारत में जांच अवधि (अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016) के अंतिम तीन महीनों और समस्त क्षति अवधि में प्रवेश करना शुरू किया था।
- (च) घरेलू उद्योग को हुई क्षति, स्वतः पहुंचायी हुई क्षति है। याचिकादाता की वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि उसके पास कच्चे माल की आपूर्ति करने का केवल एक स्रोत था और आपूर्तिकर्ता के संयंत्र में आग लगने की दुर्घटना होने के कारण उसको बंद करना पड़ा था।
- (छ) सऊदी अरब से आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाना जन हित के विरुद्ध होगा। मांग और पूर्ति में अंतर व्याप्त है। घरेलू उद्योग पूर्ण क्षमता में उत्पादन करने पर भी भारत में केवल 32% मांग की आपूर्ति करने में सक्षम होगा।
- (ज) लागत के आंकड़ों का अगोपनीय वृत्तान्त नहीं दिया गया है।
- (झ) सऊदी अरब से उत्पादकों/निर्यातकों नामतः सऊदी बुटानोल कंपनी, सऊदी एक्रेलिक एसिड कंपनी, सदारा केमिकल कंपनी, नेशनल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रियलाइजेशन मार्किटिंग कंपनी, टोयटा टसुशो कार्पोरेशन और पेट्रोकेम मिडल ईस्ट एफजेडई की प्रतिनिधि मेसर्स लक्ष्मी कुमारन एंड श्रीधरण एटोर्नी द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-
- याचिका में आरोपित कीमत कटौती के मार्जिन पर विचार किया जाना चाहिए। सऊदी अरब से उत्पादकों ने भारतीय व्यापारियों को निर्यात किए हैं, जो भंडारण और माल गोदामों पर व्यय करते हैं। ऐसी लागतों से पहुंच मूल्य में 25% से 30% तक की वृद्धि होती है। कीमत में कटौती, घरेलू उद्योग की कीमत की भारत में व्यापारियों की पुनःबिक्री की कीमत के साथ तुलना के आधार पर करनी चाहिए।

- भारत में अन्य देशों से भी पाटन कीमतों पर आयात हो रहे थे और जांच अवधि में ये पाटन-रोधी शुल्क से मुक्त थे, जो कि जांच अवधि के पूरा होने के बाद लगाए गए थे। सऊदी अरब से आयातों ने भारत में जांच अवधि (अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016) के अंतिम तीन महीनों और समस्त क्षति अवधि में प्रवेश करना शुरू किया था।
- घरेलू उद्योग को हुई क्षति, स्वतः पहुंचायी हुई क्षति है। याचिकादाता की वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि उसके पास कच्चे माल की आपूर्ति करने का केवल एक स्रोत था और आपूर्तिकर्ता के संयंत्र में आग लगने की दुर्घटना होने के कारण उसको बंद करना पड़ा था।
- सऊदी अरब से आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाना जन हित के विरुद्ध होगा। मांग और पूर्ति में अंतर व्याप्त है। घरेलू उद्योग पूर्ण क्षमता में उत्पादन करने पर भी भारत में केवल 32% मांग की आपूर्ति करने में सक्षम होगा।
- घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के भीतर क्षति की समग्र सूचना को दो भागों में वर्गीकृत किया है – (1) अप्रैल से दिसंबर 2015 और (1) जनवरी से मार्च, 2016। घरेलू उद्योग ने इसका प्रतिवाद नहीं किया है कि जांच अवधि के नौ महीनों की प्रथम अवधि में संबद्ध देश से आयात नहीं हुए थे। घरेलू उद्योग ने यह भी स्वीकार किया है कि वर्तमान जांच अवधि में आंकड़ों को संग्रहण तीन महीनों के लिए प्रभावशाली था और न कि एक वर्ष के लिए जैसा कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अभिज्ञात किया गया है। घरेलू उद्योग इसकी मनाही नहीं करता है कि पाटन की जांच करने की अवधि सामान्यतया बारह महीनों की होनी चाहिए और किसी भी मामले में यह छः महीनों से कम नहीं होनी चाहिए। तथापि, घरेलू उद्योग पाटन-रोधी पद्धति संबंधी समिति द्वारा किए गए ऐसे प्रेक्षणों पर विश्वास करता है कि जांच प्राधिकारी पाटन और क्षति दोनों के लिए आंकड़ों का संग्रहण करने की अवधि निर्धारित करने के लिए संबद्ध जांच की विशिष्ट परिस्थितियों पर विचार कर सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे प्रत्येक मामले में उपयुक्त हैं। घरेलू उद्योग का यह दावा है कि पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध का निर्धारण, तीन महीनों के आयात के आंकड़ों पर आधारित है।
- घरेलू उद्योग के दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पहले, घरेलू उद्योग ऐसी “विशिष्ट परिस्थिति” का उल्लेख करने में विफल रहा है, जिसके लिए जांच की अल्पावधि आवश्यक होगी। दूसरे, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पद्धति के अनुसार वास्तव में विगत समस्त जांच में पाटन-रोधी पद्धति संबंधी समिति की सिफारिश का अनुपालन किया है। घरेलू उद्योग भारत में अथवा किसी अन्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसा एक भी मामला प्रस्तुत करने में विफल रहा है, जिसमें पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध का निर्धारण केवल तीन महीनों के आंकड़ों के आधार पर किया गया हो। तीसरे, यदि वर्तमान मामले में “विशिष्ट परिस्थिति” में आंकड़ों के संग्रहण के लिए जांच की अल्पावधि की आवश्यकता होती, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी, जांच शुरू करने की सूचना में सामान्यतया एक वर्ष की जांच की अवधि का चयन नहीं करते। अन्य शब्दों में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पहले ही यह निर्णय ले लिया था कि ऐसी कोई “विशिष्ट परिस्थिति” नहीं है, जिसके लिए जांच की अल्पावधि की आवश्यकता है। चौथे, *गुआटेमाला-सीमेंट II* में पैनल द्वारा दिए गए प्रेक्षणों पर घरेलू उद्योग का विश्वास करना गलत है। *गुआटेमाला-सीमेंट II* में पैनल के प्रेक्षण ने विशिष्ट परिस्थिति के विद्यमान होने के कारण क्षति का निर्धारण करने के लिए एक वर्ष की अल्पावधि की स्वीकृति दी है और न कि तीन महीनों की।

- मात्र इस कारण से कि पाटन-रोधी करार में जांच अवधि के लिए विशिष्ट अवधि का अधिदेश स्पष्ट नहीं है, का यह तात्पर्य नहीं है कि जांच अवधि की एक मास, दो मास अथवा तीन मास की अल्पावधि की स्वीकृति दी गई है। इसी ट्यूब अथवा पाईप फिटिंग्स के मामले में अपील निकाय ने स्पष्ट रूप से यह नोट किया है कि जांच अवधि, स्थिर अवधि में संग्रहीत आंकड़े प्रदान करती है, जिसे जांच प्राधिकारी द्वारा पाटन का निर्धारण करने के लिए स्वीकृत किया जाना चाहिए, जो कि बाजार में ऐसे उतार-चढ़ाव होने अथवा अन्य अनिश्चितताओं के अध्यधीन होगी, जो कि उचित मूल्यांकन को विकृत कर सकती हैं।
- यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी, तीन महीनों की अवधि पर आधारित पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध में अपने निर्धारण को आधार बनायेंगे, तो इससे गलत दृष्टांत स्थापित होगा। ऐसी कोई न्यूनतम अवधि नहीं होगी, जिसके लिए आयात के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा और निर्धारण ऐसे मामलों पर आधारित होगा जिनमें एक महीने अथवा दो महीने से आयात हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस पर विवाद नहीं हो सकता है कि तीन महीनों के आंकड़े, सऊदी अरब में उत्पादकों और निर्यातकों के निर्यात चलन को उचित रूप से परिलक्षित नहीं कर सकते हैं। पाटन-रोधी शुल्क की सिफारिश प्रकृति से संभावित है, जो कि आगामी पांच वर्षों के लिए लागू होती है। ऐसी आवश्यकता है कि पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध का मूल्यांकन, निर्यातक देश में उत्पादक और निर्यातक के निर्यात चलन को परिलक्षित करने वाले आयात के आंकड़ों के आधार पर किया जाए। इस प्रकार यह तर्क देना गलत है कि तीन महीनों की अल्पावधि विश्व व्यापार संगठन के पाटन-रोधी करार और पाटन-रोधी नियम के प्रावधानों के समनुरूप है। परिणामस्वरूप तीन महीनों के आंकड़ों के आधार पर पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध का किया गया दावा गलत और अविश्वसनीय है।
- यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस तथ्य के बावजूद कि आयात के आंकड़े केवल तीन महीनों के हैं, जांच जारी रखने का निर्णय लेते हैं, तो यह निवेदन है कि क्षति और कारणात्मक संबंध का निर्धारण करने के लिए जांच अवधि को नौ महीनों और तीन महीनों में पृथक रूप से वर्गीकृत नहीं किया जाए। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जांच की अवधि नियत करने के बाद घरेलू उद्योग निरंतर उसको उप-विभाजित नहीं कर सकता है। समग्र जांच अवधि को एक मानते हुए सऊदी अरब मूल के आयातों और आरोपित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध पूर्णतया नहीं होगा। इसी अवधि में जब कि सऊदी अरब से आयात हो रहे थे, घरेलू उद्योग के उत्पादन और घरेलू बिक्रियों में वृद्धि हुई है। इसलिए इससे ऐसा संकेत मिलता है कि सऊदी अरब से आयातों का घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन को प्रभावित नहीं किया है। इसी प्रकार उत्पादन क्षमता भी स्थिर बनी रही है तथा उत्पादन, क्षमता उपयोग और बाजार के हिस्से में वृद्धि हुई है।

भारत में घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता और मी.टन में कुल मांग

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	जांच अवधि
सऊदी अरब से आयात	मी.टन	0	0	0	8,791
यूरोपीय यूनियन, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमरीका से आयात	मी.टन	31,929	42,016	55,243	50,606

कुल मांग	मी.टन	46,769	49,798	59,243	70,552
उत्पादन क्षमता	मी.टन	22,500	22,500	22,500	22,500
विक्रियां	मी.टन	14,472	6,425	4,037	11,154
उत्पादन	मी.टन	14,409	5,484	4,203	11,080
क्षमता उपयोग	%	64.04%	24.37%	18.68%	49%
बाजार का हिस्सा	%	31%	13%	7%	16%

- इस प्रकार घरेलू उद्योग को यदि कोई क्षति हुई है, तो उसका कारण यूरोपीय यूनियन, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमरीका से नार्मल बुटानोल का आयात होना है, जो कि आयातों की मात्रा का 85% भाग बनते हैं और घरेलू मांग में उनका हिस्सा 72% था। इसके अतिरिक्त 7 महीनों के लिए उत्पादन संयंत्र का बंद हो जाना, 23 अगस्त, 2013 को आग की दुर्घटना होना, इन दोनों घटनाओं के स्थाई परिणाम होना तथा कच्चे माल की आपूर्ति की कमी होना ऐसे कारक हैं, जिनके कारण घरेलू उद्योगको आरोपित क्षति हुई है।
- घरेलू उद्योग पहली बार ऐसा दावा कर रहा है कि सऊदी अरब से आयात होने के कारण उसको आर्थिक क्षति हो रही है, जो कि जांच पश्चात अवधि पर आधारित है। प्रारंभ से ही यह निवेदन किया गया है कि घरेलू उद्योग अब ऐसा दावा नहीं कर सकता है कि उसको आर्थिक क्षति होने का खतरा है। जांच के कार्य-क्षेत्र का निर्धारण, जांच शुरू करने की सूचना से किया गया है, जिसमें क्षति के खतरे का निर्धारण नहीं किया गया है। घरेलू उद्योग ने याचिका प्रस्तुत करते समय अथवा सार्वजनिक सुनवाई के दौरान कभी भी ऐसा आरोप नहीं लगाया है कि उसे आर्थिक क्षति हो रही है। जैसा कि याचिका में आरोप लगाया गया है, वर्तमान जांच आर्थिक क्षति का निर्धारण करने तक सीमित है और जिसके लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जांच शुरू करने की सूचना में यह निर्धारित किया है कि प्रथम दृष्टया साध्य हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी की यह सुस्थापित पद्धति है कि मूल जांच में आर्थिक क्षति का निर्धारण करने के लिए जांच पश्चात अवधि पर विचार नहीं किया जाता है। हाल ही में चीन जनवादी गणराज्य मूल की अथवा वहां से निर्यातित “एल्वाय अथवा नॉन-एल्वाय स्टील के बॉयर रॉड” के आयातों से संबंधित पूरी की गई पाटन-रोधी जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाया है कि –

“हितवद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि जांच पश्चात अवधि की प्रवृत्तियों की जांच की जानी चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल जांच में जांच पश्चात अवधि की प्रवृत्तियां प्रासंगिक नहीं होती हैं। पाटन-रोधी नियम के नियम 23 के अनुसार शुरू की गई पुनरीक्षा में जांच अवधि पश्चात की प्रवृत्तियां इसलिए प्रासंगिक होंगी क्योंकि प्राधिकारी को पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति होने की जांच करनी होती है।”

निर्दिष्ट प्राधिकारी की यह सुस्थापित पद्धति है कि वह मूल जांच में जांच अवधि के आंकड़ों के आधार पर आर्थिक क्षति का निर्धारण करें। अन्य शब्दों में मूल जांच में जांच पश्चात अवधि के आंकड़े अप्रासंगिक हैं।

- घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे निम्नानुसार हैं:-

- (1) तीन संयुक्त प्रवर्तक कंपनियों को एक दूसरे से संबंधित माना जाना चाहिए।
- (2) निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रतिवादियों के इस दावे की बारीकी से जांच करनी चाहिए कि भारतीय व्यापारियों/आयातकों द्वारा किए गए व्यय के कारण पहुंच मूल्य में 25% से 30% तक की वृद्धि हुई है।

- (3) जांच अवधि के अंतिम तीन महीनों में सऊदी अरब से आयात शुरू होने के फलस्वरूप जांच अवधि के अंतिम तीन में घरेलू बिक्रियां विस्थापित हुई हैं।
- (4) वार्षिक रिपोर्ट में साक्ष्य यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को वर्ष 2014-15 के लिए कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता के संयंत्र के बंद हो जाने के कारण हुई है और न कि जांच अवधि में।

ख. घरेलू उद्योग के दावों पर सऊदी अरब के उत्पादकों/निर्यातकों के प्रत्युत्तर निम्नानुसार हैं:-

- (1) ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है जिसमें प्राधिकारी को ऐसी आवश्यकता हो कि वे तीन प्रवर्तक कंपनियों को संबंधित कंपनियां मानें। घरेलू उद्योग ने भी ऐसे किसी कानूनी प्रावधान का उल्लेख नहीं किया है। ऐसा कोई मामला नहीं है, जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्रवर्तक कंपनियों को इसलिए संबंधित कंपनियां माना हो क्योंकि वे एक साथ मिल कर एक संयुक्त उद्यम पर नियंत्रण रखती हैं।
- (2) निर्दिष्ट प्राधिकारी निश्चित रूप से प्रतिवादियों द्वारा किए गए दावे की जांच कर सकते हैं।
- (3) जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्रियों को कोई क्षति नहीं हुई है अथवा विस्थापन नहीं हुआ है। आर्थिक क्षति का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ केवल विगत तीन महीनों के आंकड़ें अपर्याप्त हैं। निष्पक्ष और सार्थक जांच प्राधिकारी आर्थिक और कारणात्मक संबंध के अपने मूल्यांकन के लिए तीन महीनों की अवधि को आधार नहीं बना सकते हैं।
- (4) वर्ष 2014-15 को क्षति की जांच अवधि में शामिल किया गया है। इस प्रकार वार्षिक रिपोर्ट यह दर्शाती है कि इस अवधि के दौरान अन्य कारकों के कारण में क्षति हो सकती है, जिनका विश्लेषण करने की भी आवश्यकता है। साथ ही यह भी विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि यदि जांच अवधि अर्थात् 2016-17 में घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन प्रभावित हुआ था, तो उसका कारण विगत वर्ष में अनुभव की गई कठिनाइयां हो सकता है।

ड. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

38. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और विविध हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों को नोट कर लिया है। प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियम के अनुसार और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग की क्षति की जांच की है।

39. याचिकादाता द्वारा प्रदत्त सूचना की पर्याप्तता और परिशुद्धता के संबंध में नियमों का उल्लंघन करने के तर्क के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत पाटन-रोधी नियम के नियम 5 के अनुसार केवल पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के विद्यमान होने के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर की गई थी।

40. गोपनीयता के तर्क के संबंध में उल्लेखनीय है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीय के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का अगोपनीय वृत्तान्त भी प्रस्तुत करें। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय वृत्तान्त को सार्वजनिक फाईल के रूप में उपलब्ध कराया है।

41. पाटन-रोधी नियम में ऐसी अपेक्षा है कि प्राधिकारी मात्रा और कीमत दोनों के प्रभाव की जांच करके क्षति की जांच करेंगे। क्षति का निर्धारण करने में इन दोनों की तथ्यपरक जांच की व्यवस्था है, (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव; और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव। पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए

इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पादों की कीमतों की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में महत्वपूर्ण स्तर तक कमी करना है या ऐसा कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा में बढ़ गई होती।

42. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (IV) में उल्लिखित प्रावधान निम्नानुसार है:

"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों, घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा।"

43. यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी प्राचल गिरावट को दर्शाएं, जब कि प्राधिकारी यह मानते हैं कि क्षति के सभी प्राचलों का गहन रूप से और सार्थक ढंग से यह निष्कर्ष देना होता है कि क्या घरेलू उद्योग को पाटन के कारण क्षति हुई है अथवा नहीं।

44. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपने निवेदनों में दिए गए तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए सार्थक ढंग से क्षति के प्राचलों की जांच की है। साथ ही प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम के पैरा 93 में इस प्रकटन विवरण पर दी गई टिप्पणियों की भी जांच की है।

45. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 तक (12 महीने) मानी गई है। तथापि, संबद्ध देश से आयात, जांच अवधि की अंतिम तिमाही अर्थात् जनवरी – मार्च, 2016 में हुए हैं।

I. मांग का निर्धारण

46. संबद्ध वस्तुओं की मांग का निर्धारण, डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त किए गए सभी देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के साथ घरेलू समान उत्पाद की घरेलू बिक्रियों को जोड़ कर किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:-

मांग	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	जांच अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी.टन	14,472	6,425	4,037	11,154
आयात – संबद्ध देश	मी.टन	0	0	0	8,791
आयात – पाटन - रोधी उपायों वाले देश	मी.टन	31,929	42,015	55,243	50,606
आयात – अन्य देश	मी.टन	205	750	0	0.32
मांग/खपत	मी.टन	46,606	49,190	59,280	70,551
प्रवृत्ति		100	106	127	151

*जांच अवधि : 2015-16

II. पाटित आयातों की मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

(क) आयात की मात्रा और घरेलू उद्योग का हिस्सा

47. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि जनवरी, 2016 से मार्च, 2016 तक की जांच अवधि के दौरान सऊदी अरब से पूर्णरूपेण आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिसे नीचे तालिका में दर्शाया गया है:-

मांग	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	जांच अवधि
आयात -	मी.टन	0	0	0	8,791
आयात – संबद्ध देश	मी.टन	31,929	42,015	55,243	50,606
आयात – पाटन-रोधी उपायों वाले देश	मी.टन	205	750	-	0.32
कुल आयात	मी.टन	32,134	42,765	55,243	59,397
मांग	मी.टन	46,606	49,190	59,280	70,551
उत्पादन	मी.टन	14,409	5,484	4,203	11,080
निम्नोक्त के संबंध में आयात -					
कुल आयात	%	संबद्ध देश से कोई आयात नहीं			15%
खपत	%				12%
उत्पादन	%				79%

III. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव

48. जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, नियमावली के अनुबंध-II (ii) में निम्नानुसार निर्धारित है :

“जहां तक नियम 18 के उप नियम (2) में किए गए उल्लेखानुसार कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के कारण कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण कीमत में होने वाली वृद्धि में अन्यथा काफी अधिक न्यूनीकरण हुआ है अथवा कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रुकावट आई है जिसमें अन्यथा काफी हद तक वृद्धि हो गई होती।”

49. यदि कोई कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री होने, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण हुआ है, तो उसके संदर्भ में घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच की गई है।

(क) कीमत कटौती

50. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत की तुलना, व्यापार के समान स्तर पर घरेलू उद्योग की निबल बिक्री वसूलियों, सभी छूटों और करों के निबल के साथ की है। इस तुलना से पता चलता है कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश के मूल की संबद्ध वस्तुओं का आयात भारतीय बाजार में ऐसी कीमतों पर किया गया था जो कि विगत तीन महीनों में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों से कम थीं। नीचे तालिका यह दर्शाती है कि संबद्ध देश से कीमत में कटौती हुई है, लेकिन यह केवल जांच अवधि के 3 महीनों के दौरान हुई है, चूंकि जांच अवधि के पहले 9 महीनों के दौरान कोई आयात नहीं हुआ है।

विवरण	यूनिट	जांच अवधि
निबल बिक्री कीमत	रूपए/किलोग्राम	***
पहुंच कीमत	रूपए/किलोग्राम	39.43
कीमत कटौती	रूपए/किलोग्राम	***
कीमत कटौती	%	25-35%
कीमत कटौती	सीमा (%)	25-35%

(ख) कम कीमत पर बिक्री

51. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा कम कीमत पर बिक्री करने के प्रभाव की भी जांच की है। इस प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित क्षति रहित कीमत की तुलना आयातों की पहुंच कीमत के साथ की गई है, जो कि निम्नानुसार है

विवरण	यूनिट	जांच अवधि
क्षति रहित कीमत	रूपए/किलोग्राम	***
पहुंच कीमत	रूपए/किलोग्राम	39.43
कीमत कटौती	रूपए/किलोग्राम	***
कीमत कटौती	%	55-75%
कम कीमत पर बिक्री	सीमा (%)	55-75%

52. यह देखा गया है कि जनवरी, 2016 से मार्च, 2016 तक की अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमतें, घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित की गई क्षति रहित कीमत से अत्यधिक कम थीं। प्राधिकारी ने बाद में इस अंतिम जांच परिणाम के पैरा 93 में इस मुद्दे की जांच की है।

(ग) कीमत न्यूनीकरण/कीमत न्यूनीकरण

53. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात, घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास अथवा न्यूनीकरण कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अत्यधिक सीमा तक ह्रास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि होनी रुकी है, जो कि अन्यथा अत्यधिक सीमा तक हो गई होती, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में हुए परिवर्तनों पर विचार किया है। नीचे तालिका में वास्तविक स्थिति दर्शाई गई है:-

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	जांच अवधि
बिक्री कीमत	रू./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	92	73
बिक्रियों की लागत	रू./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	113	79

54. यह देखा गया है कि वर्ष 2014-15 तक लागत में वृद्धि हुई है और उसके बाद जांच अवधि में उसमें गिरावट आई है। वर्ष 2013-14 तक बिक्री कीमत में वृद्धि हुई थी और उसके बाद वर्ष 2014-15 और जांच अवधि में उसमें गिरावट है। याचिकादाता ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग अपनी लागत से कम कीमत पर संबद्ध वस्तुओं को बेचने के लिए निरंतर दबाव में था जिसके परिणामस्वरूप उसे समग्र क्षति अवधि के दौरान वित्तीय घाटे हुए हैं और पाटन देशों के वर्तमान और विगत सेट से पाटित आयातों के कारण उसे समग्र क्षति अवधि के दौरान वित्तीय घाटे

हुए हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के अंतिम तीन महीनों में सऊदी अरब से आयातों ने भारतीय बाजार में प्रवेश किया था, जो कि उस समय प्रचलित कीमतों के सदृश थे।

IV. घरेलू उद्योग के लिए आर्थिक प्राचल

55. पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-2 में ऐसा अपेक्षित है कि क्षति का निर्धारण करने में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की सार्थक जांच करना निहित होगा। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली में आगे यह भी प्रावधान निहित है कि घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की जांच करने में सभी संबद्ध आर्थिक कारकों का सार्थक और निष्पक्ष मूल्यांकन करने के साथ-साथ उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सूचकों को भी शामिल किया जाना चाहिए, जिनमें बिक्रियों, लाभ, उत्पादन, बाजार के हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिलाभ अथवा क्षमता उपयोग, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन के मार्जिन का परिमाण, नकदी प्रवाह, मालसूचियां, रोजगार, वेतन, संवृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता जैसे वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव भी शामिल होने चाहिए। घरेलू उद्योग से संबंधित क्षति के विभिन्न प्राचलों का उल्लेख नीचे किया गया है।

(क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्रियां

56. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्रियों के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्य—निष्पादन

निम्नानुसार है:-

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	जांच अवधि
क्षमता	मी.टन	22,500	22,500	22,500	22,500
उत्पादन	मी.टन	14,409	5,484	4,203	11,080
क्षमता उपयोग	%	64.04%	24.37%	18.68%	49.24%
घरेलू बिक्रियां	मी.टन	14,472	6,425	4,037	11,154
मांग	मी.टन	46,606	49,190	59,280	70,551

57. उपरोक्त तालिका में यह देखा गया है कि विगत दो वित्तीय वर्षों के साथ तुलना करने पर जांच अवधि के दौरान उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्रियों के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्य—निष्पादन में सुधार हुआ है। तथापि, मूल वर्ष 2012-13 की तुलना में उत्पादन, घरेलू बिक्रियों और क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।

58. याचिकादाता ने यह दावा किया है कि उत्पादन, बिक्रियों की मात्रा और क्षमता उपयोग में गिरावट अलाभप्रद कीमतों के कारण आई है और न कि अन्य कारकों से। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयात की कीमतों में जांच अवधि के प्रथम 9 महीनों के दौरान गिरावट आई थी और ये उसके बाद भी सऊदी अरब से कीमतों सहित, जो कि जांच अवधि के अंतिम 3 महीनों में भारत में प्रचलित कीमतों के समान थीं, उसमें निरंतर गिरावट जारी रही।

59. यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि में देश में उत्पाद की मांग में जितनी वृद्धि हुई है, घरेलू उद्योग के उत्पादन, घरेलू बिक्रियों और क्षमता उपयोग में उतनी वृद्धि नहीं हुई है। प्राधिकारी का मानना है कि यूरोपीय यूनियन, मलेशिया, सिंगापुर, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमरीका से पाटित कीमतों में सुधार केवल जांच पश्चात अवधि में हुआ था और इसके प्रभाव केवल जांच पश्चात अवधि में ही उपलब्ध होंगे, जो कि इस जांच का भाग नहीं है।

(ख) लाभ, लाभप्रदता, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी लाभ

60. घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत, बिक्री कीमत, लाभ/हानि, नकदी लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ निम्नानुसार है:-

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	जांच अवधि
बिक्रियों की लागत	रु./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	113	79
बिक्री कीमत	रु./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	92	73
लाभ/हानि (प्रति यूनिट)	रु./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-155	-732	-268
लाभ/हानि सकल		***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-69	-204	-206
ब्याज पूर्व लाभ		***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-58	-305	-280
नकदी लाभ		***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-82	-308	-290
निवेश पर प्रतिलाभ		***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-67	-360	-379

61. उपरोक्त विश्लेषण यह दर्शाता है कि समस्त जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत लागत से नीचे रही है जिसके फलस्वरूप उसे प्रति यूनिट घाटा हुआ है। क्षति अवधि में ब्याज पूर्व लाभ, नकदी लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ नकारात्मक रहा है। यह देखा गया है कि जांच अवधि में भी घाटे हुए हैं। तथापि, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि केवल जनवरी, 2016 के बाद ही सऊदी अरब से आयात होने शुरू हुए हैं और प्राधिकारी ने इस मुद्दे का समाधान, बाद में इस परिणाम के पैरा 93 में प्रकटन पश्चात टिप्पणियों के प्रत्युत्तर में कर दिया है।

(ग) बाजार का हिस्सा

62. घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच की गई है, जो कि निम्नानुसार हैं:-

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	जांच अवधि
घरेलू उद्योग	%	31%	13%	7%	16%
संबद्ध देश	%	0%	0%	0%	12%
पाटन-रोधी उपाय करने वाले देश	%	69%	85%	93%	72%
अन्य देश	%	0%	2%	0%	0%

63. उपरोक्त तालिका में यह देखा गया है कि वर्ष 2014-15 तक घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से में गिरावट आई है, लेकिन जांच अवधि में उसमें सुधार हुआ है। विगत दो वित्तीय वर्षों अर्थात् 2013-14 और 2014-15 के साथ तुलना करने पर जांच अवधि में घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से में सुधार हुआ है। तथापि, पाटन-रोधी जांच अधीन अन्य गैर-संबद्ध देशों के पास बाजार का प्रमुख हिस्सा होने के कारण जांच अवधि में घरेलू उद्योग के बाजार का हिस्सा, मूल वर्ष 2012-13 में बाजार हिस्से से कम था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सऊदी अरब से आयात जांच अवधि के अंतिम तीन महीनों में हुए हैं और घरेलू उद्योग पर उनके प्रभाव का समाधान, बाद में इस जांच परिणाम के पैरा 93 में कर दिया गया है।

(घ) रोजगार, उत्पादकता और वेतन

64. रोजगार, उत्पादकता और वेतन से संबंधित स्थिति निम्नानुसार है:-

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	जांच अवधि
रोजगार		***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	97	93
वेतन	लाख रूपए	***	***	***	***
वेतन	सूचीबद्ध	100	103	112	107
उत्पादकता प्रति दिन	मी.टन प्रति दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	38	29	77
उत्पादकता प्रति कर्मचारी	मी.टन प्रति दिन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	39	30	82

65. क्षति अवधि के दौरान रोजगार के स्तर में गिरावट आई है, जबकि वेतन में वृद्धि हुई है। याचिकादाता ने दावा किया है कि रोजगार और वेतन, घरेलू उद्योग के प्रतिकूल कार्य-निष्पादन को परिलक्षित नहीं करते हैं क्योंकि ये कारक कंपनी और अर्थव्यवस्था के समग्र प्राचलनों द्वारा अधिशासित होते हैं। उत्पादकता उसी दिशा की ओर उन्मुख हुई है, जिसमें उत्पादन हुआ है, इस प्रकार विगत दो वित्तीय वर्षों की तुलना में उसने सुधार दर्शाया है। याचिकादाता ने दावा किया है कि अलाभप्रद उत्पाद कीमतों (अर्थात् पाटन) के कारण घरेलू उद्योग के उत्पादन को नुकसान हुआ है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सऊदी अरब से आयात केवल जनवरी से मार्च, 2016 के दौरान हुए हैं और इनके प्रभावों का उचित ढंग से समाधान, इस परिणाम के पैरा 93 में प्रकटन पश्चात टिप्पणियों के प्रत्युत्तर में कर दिया गया है।

ड. मालसूचियां

66. संबद्ध वस्तुओं की मालसूची से संबंधित आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं:-

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	जांच अवधि
औसत माल सूची	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	50	11	16

67. यह देखा गया है कि उत्पादन के स्तर में गिरावट आने के साथ औसत मालसूची के स्तर में भी गिरावट आई है, जब कि जांच अवधि में उत्पादन का स्तर, विगत 2 वर्षों की तुलना में दोगुना हो गया है, जांच अवधि में मालसूची का स्तर, इस कारक पर प्रतिकूल स्थिति परिलक्षित नहीं करता है।

(च) संवृद्धि

68. घरेलू उद्योग की संवृद्धि से संबंधित आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं:-

संवृद्धि	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	जांच अवधि
उत्पादन	मी.टन	-	-62%	-23%	164%
घरेलू बिक्रियां	मी.टन	-	-56%	-37%	176%
बिक्रियों की लागत	रूपए/कि.ग्रा.	-	12%	1%	-30%
बिक्री कीमत	रूपए/कि.ग्रा.	-	10%	-16%	-21%
लाभ/(हानि)	रूपए/कि.ग्रा.	-	55%	373%	-63%
निवेश पर प्रतिलाभ	%	-	1%	-6%	0%
बाजार का हिस्सा	%	-	-18%	-6%	9%

संवृद्धि की तालिका, विगत 2 वर्षों की तुलना में जांच अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा विशेष रूप से मात्रा के प्राचलों में सुधार दर्शाती है।

69. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादन और बिक्रियों की मात्रा जैसे मात्रा के प्राचलों के रूप में घरेलू उद्योग की संवृद्धि, तात्कालिक पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि में सुधार दर्शाती है। समस्त क्षति अवधि के दौरान लाभ, नकदी लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ जैसे कीमत के प्राचलों के रूप में संवृद्धि प्रतिकूल बनी रही है। तथापि, सऊदी अरब से आयात केवल जनवरी, 2016 के बाद होने शुरू हुए हैं और घरेलू उद्योग पर इसके प्रभाव का विश्लेषण, इस परिणाम के पैरा 93 में किया गया है।

(छ) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

70. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग देश में उत्पाद की बढ़ती मांग की स्थिति में भी अपनी क्षमता का उपयोग करने में असमर्थ रहा है जिसके परिणाम स्वरूप हुए उसे भारी घाटे हुए हैं। इस परिणाम के पैरा 93 में इस तथ्य की जांच की गई है कि क्या मात्र तीन महीनों में सऊदी अरब से आयात को इसका कारण माना जा सकता है।

(ज) पाटन और पाटन मार्जिन का स्तर

71. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से आयात देश में पाटित कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं और पाटन का मार्जिन न्यूनतम सीमाओं से अधिक है। सऊदी अरब से आयातों और क्षति के बीच संबंध होने के बारे में जांच, इस जांच परिणाम के पैरा 93 में की गई है।

(झ) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

72. संबद्ध देश और अन्य देशों दोनों से आयात की कीमतों की जांच, लागत ढांचे में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्द्धा, पाटित आयातों से भिन्न कारक जिनसे घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतें प्रभावित हो सकती हैं, से ऐसा पता चलता है कि संबद्ध देश से आयातित सामग्री और अन्य देशों से उत्पाद का समवर्ती पाटन का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और क्षति रहित कीमत से कम था, जिसके कारण भारतीय बाजार में अत्यधिक कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री हो रही थी। इस प्रकार घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक, पाटनरोधी जांच के अंतर्गत जनवरी से मार्च, 2016 तक की मात्र तीन महीनों की अवधि के दौरान सऊदी अरब सहित पहले से पाटनरोधी जांच के अध्यधीन पांच देशों नामतः यूरोपीय यूनियन, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमरीका से संबद्ध वस्तुओं का पहुंच मूल्य है।

(ज) क्षति पर निष्कर्ष

73. इस प्रकार यह देखा गया है कि जांच अवधि के अंतिम केवल तीन महीनों में संबद्ध देश से आयात, पूर्ण रूपेण और भारत में उत्पादन और खपत के प्रसंग दोनों में अत्यधिक मात्रा में भारत में प्रवेश कर रहे हैं। यह पाटित आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में भी कटौती कर रहे हैं।

74. संबद्ध देश के साथ-साथ अन्य गैर-संबद्ध देशों से पाटित आयातों ने उत्पादन, घरेलू बिक्रियों, क्षमता उपयोग, मालसूचियों, बाजार के हिस्से, लाभ, नकदी लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ के रूप में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव डाला है।

75. जब जांच अवधि के पहले नौ महीनों अर्थात् अप्रैल – दिसंबर, 2015 में अन्य स्रोतों से पाटन-रोधी शुल्क लगाने के लिए जांच की प्रक्रिया अभी चल रही थी, तब बिक्रियों, उत्पादन क्षमता और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ था। तथापि, जांच अवधि के बाद पाटन-रोधी उपाय लागू किए गए थे। जांच अवधि की अंतिम तिमाही अर्थात् जनवरी- मार्च, 2016 में उपरोक्त प्राचलों के संबंध में कार्य-निष्पादन में अत्यधिक गिरावट आई थी क्योंकि संबद्ध देश से नया पाटन होना शुरू हो गया था। सऊदी अरब से आयातों के संयुक्त प्रभाव की भूमिका की जांच, इस जांच परिणाम के पैरा 93 में की गई है।

76. प्राधिकारी ने जांच अवधि के पहले 9 महीनों और अंतिम 3 महीनों पर भी पृथक रूप से विचार किया है, जो कि निम्नानुसार हैं:-

77. जांच अवधि के प्रथम 9 महीनों में (अप्रैल, 2015 से दिसंबर, 2015 तक):

क्षति के प्राचल कीमत में कटौती

क्रमांक	विवरण	यूनिट	अप्रैल से दिसंबर, 2015
1	पहुंच कीमत – जिन देशों पर पाटन रोधी शुल्क लगता है		
क	यूरोपीय यूनियन	रूपए/किलोग्राम	63.80
ख	मलेशिया	रूपए/किलोग्राम	54.53
ग	दक्षिण अफ्रीका	रूपए/किलोग्राम	56.40
घ	संयुक्त राज्य अमरीका	रूपए/किलोग्राम	59.88
ङ	सिंगापुर	रूपए/किलोग्राम	58.29
2	एनएसआर	रूपए/किलोग्राम	***
3	कीमत कटौती		
क	यूरोपीय यूनियन	रूपए/किलोग्राम	***
ख	मलेशिया	रूपए/किलोग्राम	***
ग	दक्षिण अफ्रीका	रूपए/किलोग्राम	***
घ	संयुक्त राज्य अमरीका	रूपए/किलोग्राम	***
ङ	सिंगापुर	रूपए/किलोग्राम	***

क्षति के प्राचल – कीमत न्यूनीकरण

क्रमांक	विवरण	यूनिट	अप्रैल से दिसंबर, 2015
1	एनआईपी	रूपए/किलोग्राम	***
2	एनएसआर	रूपए/किलोग्राम	***
3	कीमत न्यूनीकरण	रूपए/किलोग्राम	***
4	लाभ/(हानि)	रूपए/किलोग्राम	***
5	निवेश पर प्रतिलाभ	%	***

क्षति के प्राचल – बाजार का हिस्सा

क्रमांक	विवरण	यूनिट	दिसंबर, 2015
1	मांग		
क	घरेलू उद्योग की विक्रियां	मी.टन	10,362
ख	सऊदी अरब से आयात	मी.टन	-
ग	उन देशों से आयात जिन पर पाटन रोधी शुल्क लगता है	मी.टन	37,502
	कुल	मी.टन	47,864
2	बाजार का हिस्सा		
क	घरेलू उद्योग	%	22%
ख	सऊदी अरब	%	0%
ग	जिन देशों पर पाटन रोधी शुल्क लगता है	%	78%

यह देखा गया है कि जांच अवधि के प्रथम 9 महीनों में केवल मलेशिया से सकारात्मक कीमत कटौती हुई है। कीमत न्यूनीकरण के प्रभाव भी निश्चय ही अत्यधिक हैं। घरेलू उद्योग के बाजार का हिस्सा, मांग का 22% है।

78. जांच अवधि के विगत तीन मास (जनवरी से मार्च, 2016):**क्षति के प्राचल – कीमत कटौती**

क्रमांक	विवरण	यूनिट	जन. से मार्च, 2016
1	पहुंच कीमत - सऊदी अरब	रू./किग्रा.	39.43
2	पहुंच कीमत – जिन देशों पर पाटन रोधी शुल्क लगता है		
क	यूरोपीय यूनियन	रू./किग्रा.	59.19
ख	मलेशिया	रू./किग्रा.	37.83
ग	दक्षिण अफ्रीका	रू./किग्रा.	39.75
घ	संयुक्त राज्य अमरीका	रू./किग्रा.	38.38
ड	सिंगापुर	रू./किग्रा.	38.36

3	एनएसआर	रू./किग्रा.	***
4	कीमत कटौती		
क	सऊदी अरब	रू./किग्रा.	***
ख	यूरोपीय यूनियन	रू./किग्रा.	***
घ	मलेशिया	रू./किग्रा.	***
ङ	दक्षिण अफ्रीका	रू./किग्रा.	***
च	संयुक्त राज्य अमरीका	रू./किग्रा.	***
छ	सिंगापुर	रू./किग्रा.	***

यूरोपीय यूनियन को छोड़ कर सऊदी अरब सहित सभी प्रमुख देशों के लिए कीमत कटौती सकारात्मक है, जो कि पहले 9 महीनों में नकारात्मक थी।

क्षति के प्राचल- कीमत न्यूनीकरण

क्रमांक	विवरण	यूनिट	जनवरी से मार्च, 2016
1	एनआईपी	रू./किग्रा.	***
2	एनएसआर	रू./किग्रा.	***
3	कीमत न्यूनीकरण	रू./किग्रा.	***
4	लाभ/(हानि)	रू./किग्रा.	***
5	निवेश पर प्रतिलाभ	%	***

विगत 9 महीनों की तुलना में कीमत न्यूनीकरण मामूली कम है। घरेलू उद्योग के बाजार का हिस्सा, जो कि मांग का 22% था, अब घट कर 3% रह गया है।

क्षति के प्राचल – बाजार का हिस्सा

क्रमांक	विवरण	यूनिट	जनवरी से मार्च, 2016
क	घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी.टन	792
ख	सऊदी अरब से आयात	मी.टन	8,791
ग	आयात - जिन देशों पर पाटन रोधी शुल्क लगता है	मी.टन	13,104
	कुल	मी.टन	22,688
2	बाजार का हिस्सा		
क	घरेलू उद्योग	%	3%
ख	सऊदी अरब	%	39%
ग	पाटन रोधी शुल्क लगने वाले अन्य देश	%	58%

79. जांच अवधि के दौरान आयातों का मासिक-वार एनएसआर और पहुंच मूल्य

माह	सीआईएफ कीमत					
	सउदी अरब	मलेशिया	सिंगापुर	दक्षिण अफ्रीका	यूएसए	ईयू
	रु./किग्रा.	रु./किग्रा.	रु./किग्रा.	रु./किग्रा.	रु./किग्रा.	रु./किग्रा.
जन.-16	39.94	36.86		36.66	34.75	
फर.-16	35.53	38.31		36.31	-	
मार्च-16	34.60	37.26	37.98	36.74	-	54.40
	पहुंच कीमत					
जन.-16	43.46	37.23	-	39.88	37.81	-
फर.-16	38.65	38.69	-	39.50	-	-
मार्च-16	37.65	37.63	38.36	39.98	-	59.19

मास	एनएसआर	क्षमता उपयोग	सउदी अरब	मलेलेश मलेशिया	सिंगापुर सिंगापुर	दक्षिण अफ्रीका	संयुक्त राज्य अमरीका	यूरोपीय यूनियन
		%		रु./कि.ग्रा..		रु./कि.ग्रा.		रु./कि.ग्रा.
अप्रैल-15	***	***	-	59.17	55.74	55.95	59.88	56.53
मई-15	***	***	-			60.77		61.30
जून -15	***	***	-	63.27		65.38		64.34
जुलाई -15	***	***	-	62.08	64.73			67.45
अगस्त -15	***	***	-	61.21	63.68			68.65
सितंबर -15	***	***	-	55.92	60.10			
अक्टूबर -15	***	***	-	51.24	54.33	57.86		
नवंबर -15	***	***	-	46.86	50.41	50.71		
दिसंबर -15	***	***	-	39.25	47.89	45.38		
जनवरी -16	***	***	43.46	37.23		39.88	37.81	
फरवरी -16	***	***	38.65	38.69		39.50		
मार्च -16	***	***	37.65	37.63	38.36	39.98		59.19

यह देखा गया है कि जांच अवधि के पहले 9 महीनों में मलेशिया और सिंगापुर से पहुंच मूल्य में गिरावट आई है और यह उसी स्तर पर निरंतर बना हुआ है तथा जांच अवधि के अंतिम 3 महीनों में उसमें गिरावट आई है। इसी प्रकार जांच अवधि के प्रथम 9 महीनों में एनएसआर भी गिरावट की प्रवृत्ति और जांच अवधि के अंतिम 3 महीनों में उसमें मामूली सुधार दर्शाता है।

च. कारणात्मक संबंध का मूल्यांकन

80. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग की क्षति का कारण प्रोपलीन के एक स्रोत पर उसकी निर्भरता है क्योंकि एचपीसीएल नामक आपूर्तिकर्ता ने आग की दुर्घटना, जांच अवधि में अन्य देशों से पाटन तथा मांग और पूर्ति में अत्यधिक अंतर व्याप्त होने के कारण आयात की अपरिहार्यता जैसे अन्य कारकों से अपना संयंत्र बंद कर दिया था। प्राधिकारी ने क्षति रहित कीमत का परिकलन करते समय इन

पहलुओं पर विचार किया है ताकि पाटन और परिणामी क्षति के कारणात्मक संबंध का मूल्यांकन करते समय इन प्राचलों के कारण होने वाली अकुशलता को घरेलू उद्योग की क्षति का कारण नहीं माना जाए।

81. प्राधिकारी विभिन्न कारों का उचित पृथक्कीकरण करते हैं, ताकि पाटित आयातों के कारण हुई क्षति की मात्रा का मूल्यांकन किया जा सके। वर्तमान जांच में प्राधिकारी ने जांच अवधि का दो अवधियों में पृथक्कीकरण किया है – (1) अप्रैल-दिसंबर, 2015 – जिसमें संबद्ध देश से कोई आयात नहीं हुआ है और (2) जनवरी-मार्च, 2016 – जिसमें संबद्ध देश से निर्यात होने शुरू हुए हैं।

82. प्राधिकारी ने पाटन और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की जांच करने के लिए नीचे पाटन-रोधी नियमों में सूचीबद्ध अन्य कारकों की जांच की है, जो कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति के कारण हो सकते हैं।

(क) तृतीय देशों से आयात

83. प्राधिकारी ने डीसीआईएंडएस से प्राप्त हुए संबद्ध वस्तुओं के कारोबार-वार आयात आंकड़ों के आधार पर जांच की है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग संबद्ध देश के साथ-साथ अन्य देशों, जिसके लिए पहले से पृथक् से जांच की गई थी, से देश में प्रवेश कर रहे पाटित आयातों से होने वाली क्षति का सामना कर रहा है। प्राधिकारी ने इन देशों से कीमतों के प्रभाव और साथ ही घरेलू उद्योग की क्षति का मूल्यांकन किया है, जिनका उल्लेख इस परिणाम के अंतिम भाग के पैरा 93 में किया गया है।

(ख) मांग में संकुचन

84. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग ने अत्यधिक सुधार दर्शाया है। घरेलू उद्योग को मांग में संभावित संकुचन के कारण क्षति नहीं हो सकती है।

(ग) विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापारिक प्रतिबंधित पद्धतियां तथा प्रतिस्पर्धा

85. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी कोई व्यापारिक प्रतिबंधित पद्धति नहीं है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

(घ) प्रोद्योगिकी में विकास

86. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई प्रोद्योगिकी और विनिर्माण प्रक्रिया, संबद्ध देश में उत्पादकों द्वारा अपनाई गई प्रोद्योगिकी और विनिर्माण प्रक्रिया के नितांत तुलनीय है। तथापि, संबद्ध देश के उत्पादक/निर्यातक की क्षमता में व्यापक अंतर है जो कि घरेलू उद्योग की क्षमता से कई गुना अधिक है।

(ङ) खपत के पैटर्न में परिवर्तन

87. घरेलू उद्योग उन्हीं संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, जिनका भारत में आयात किया गया है। खपत के पैटर्न में संभावित परिवर्तन ऐसे कारक नहीं है जिनके कारण घरेलू उद्योग को ऐसी क्षति हुई है, जिसका उसने दावा किया है।

(च) निर्यात निष्पादन

88. चूंकि याचिकादाता ने विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है, घरेलू उद्योग को क्षति केवल घरेलू प्रचालनों के कारण हुई है, जिसका उसने दावा किया है।

(छ) अन्य उत्पादों के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन

89. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों के कार्य-निष्पादन ने प्राधिकारी द्वारा किए गए घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन को प्रभावित नहीं किया है। प्राधिकारी ने केवल विचाराधीन उत्पाद से संबंधित सूचना पर विचार किया है।

(ज) घरेलू उद्योग की उत्पादकता

90. क्षति रहित कीमत का परिकलन करते समय कच्चे माल की अनुपलब्धता जैसे विभिन्न कारकों के कारण उत्पादकता पर पड़ने वाले प्रभाव पर उपयुक्त रूप से विचार किया गया है।

91. प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियम के अनुबंध-2 में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुसार घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया है। क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत की तुलना, संबद्ध देश में प्रत्येक प्रतिवादी निर्यातक से संबद्ध आयात के पहुंच मूल्य के साथ की गई है। भारत औसत क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए प्रत्येक निर्यातक/उत्पादक के लिए इस प्रकार से निर्धारित किए गए क्षति मार्जिन पर विचार किया गया है। सहयोगी उत्पादक/निर्यातक के लिए अलग-अलग निर्धारण किया गया है, जबकि असहयोगी उत्पादक/निर्यातक के लिए उपलब्ध श्रेष्ठ सूचना को अपनाया गया है। इसका विश्लेषण कि क्या इस क्षति मार्जिन के परिकलन का कारण 9 महीनों की अल्पावधि में सऊदी अरब से आयात हो सकते हैं, इस परिणाम के पैरा 93 में किया गया है।

क्षति मार्जिन

क्रमांक	उत्पादक	निर्यातक	क्षति रहित कीमत	पहुंच कीमत	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
			यूएस\$/मी.टन	यूएस\$/मी.टन	यूएस\$/मी.टन	%	सीमा
1.	सदारा	पेट्रोकेम मिडल ईस्ट एफजेडई	***	***	***	***	80-90
2.	साक	टासनी मार्किटिंग	***	***	***	***	70-80
3.	साक	टासनी मार्किटिंग - पेट्रोकेम मिडल ईस्ट एफजेडई	***	***	***	***	70-80
4.	साक	टासनी मार्किटिंग - टोयटा टसुशो कार्पोरेशन	***	***	***	***	70-80
5.	उपरोक्त क्रमांक (1) से (4) में उल्लिखित कंपनियों से भिन्न असहयोगी/बाकी उत्पादक/निर्यातक		***	***	***	***	80-90

92. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

- याचिकादाता का अनुरोध है कि निम्नोक्त तथ्यों का प्रकटन किया जाए ताकि वह प्रकटन विवरण पर सार्थक टिप्पणियां देने में उसे सक्षम हो सके :-

- (क) प्राधिकारी कृपया संबद्ध देश से निर्यातकों/उत्पादकों की रिपोर्ट के सत्यापन का अगोपनीय वृत्तान्त का प्रकटन करें ताकि वह परिकलित पाटन मार्जिन पर सार्थक टिप्पणियों दे सके।
- (ख) प्राधिकारी कृपया प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों को मेल अथवा पत्र द्वारा संप्रेषित समस्त सूचनाओं और इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उन पर प्रस्तुत किए गए उत्तरों एक प्रति उपलब्ध कराएं। याचिकादाता किसी गोपनीय सूचना का अनुरोध नहीं कर रहा है। याचिकादाता इस सूचना के केवल अगोपनीय वृत्तान्त का अनुरोध कर रहा है।

- (ग) ऐसा प्रतीत होता है कि सऊदी कयान ने बहुत विलंबित चरण में कुछ निवेदन किए हैं। याचिकादाता का अनुरोध है कि ऐसे निवेदन उसे उपलब्ध कराए जाएं।
- (घ) प्राधिकारी वास्तविक पाटन मार्जिन का प्रकटन कर सकते हैं। इस मामले में क्षति मार्जिन, पाटन मार्जिन से बहुत अधिक है। किसी भी स्थिति में यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी एक बार अंतिम जांच परिणाम जारी कर देते हैं, तो हितबद्ध पक्षकार निर्धारित वास्तविक पाटन मार्जिन को जान जायेंगे। उस चरण में जो गोपनीय नहीं रहेगा, वह इस चरण में गोपनीय नहीं हो सकता है।

- प्रकटन विवरण पर अपनी सार्थक टिप्पणियां देने के लिए घरेलू उद्योग हेतु उपरोक्त तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तथापि, जब तक ऐसा प्रकटन नहीं कर दिया जाता है, तब तक घरेलू उद्योग प्रकटन विवरण पर अपने निम्नलिखित प्राथमिक निवेदन करता है। जब कभी भी उपरोक्त अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन किया जाएगा, घरेलू उद्योग उन पर अतिरिक्त निवेदन करना चाहेगा।
- याचिकादाता मानता है कि प्रकटन विवरण नियम 16 की अपेक्षाओं को तब तक पूरा नहीं करता, जब तक कि समस्त क्षति अवधि में आयात नहीं होने और उसी अवधि में अन्य स्रोतों से पाटित आयातों की मौजूदगी के संबंध में पक्षकार के तर्क को दर्ज नहीं कर लिया जाता है, लेकिन उसमें घरेलू उद्योग की क्षति के संबंध में इस पहलू पर उसका समान प्रभाव का निहित नहीं है। प्रकटन विवरण में मात्र यह उल्लेख है कि प्राधिकारी का सऊदी अरब से आयातों और घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध होने की जांच करने के प्रयोजनार्थ इन पहलुओं पर विचार करने का प्रस्ताव है। प्रकटन विवरण में आगे यह भी उल्लेख है कि प्राधिकारी का इस पर भी विचार करने का प्रस्ताव है कि क्या सऊदी अरब से आयातों के 3 महीनों की अल्पावधि, संबद्ध विश्व व्यापार संगठन के दिशानिर्देशों/पाटन-रोधी नियमों और विश्लेषणात्मक मूल्यांकन करने के आलोक में पाटन और घरेलू उद्योग की क्षति के प्रमुख प्राचलों का निर्धारण करने के लिए यथोचित और न्यायसंगत हैं। याचिकादाता का निवेदन है कि ये विवरण स्पष्टतया बताते हैं कि प्रकटन विवरण अपूर्ण है। जब प्राधिकारी ने स्वयं कारणात्मक पहलुओं पर कोई जांच नहीं की है (अथवा हितबद्ध पक्षकारों को नहीं बताया है), तो इससे साफ पता चलता है कि प्रकटन विवरण में कारणात्मक संबंध के बारे में “अनिवार्य तथ्य” निहित नहीं हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जो भी प्रकट किया है वह तथ्य नहीं है। यह एक “सूचना” है। याचिकादाता का निवेदन है कि अनिवार्य तथ्यों के प्रकटन का तात्पर्य संबद्ध तथ्यों के विद्यमान होने से संबंधित प्रकटन से है। इस संबंध में संबद्ध तथ्य यह हैं: (क) क्या पाटन हुआ है, (ख) पाटन की मात्रा, (घ) क्या क्षति हुई है, (ग) क्षति मार्जिन और (घ) क्या पाटन अथवा कुछ अन्य कारकों के कारण क्षति हुई है।
- प्रकटन विवरण से याचिकादाता के निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:-
 - (क) विचाराधीन उत्पाद नार्मल बुटानोल है।
 - (ख) याचिकादाता भारत में संबद्ध वस्तुओं का एक मात्र अकेला घरेलू उत्पादक है।

- (ग) विचाराधीन उत्पाद का निर्यात, सामान्य मूल्य से कम कीमतों पर किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप संबद्ध देश से पाटन हो रहा है। प्रतिवादी निर्यातकों के लिए निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन अत्यधिक है।
- (घ) घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है और संबद्ध देश से पाटित आयातों के प्रतिकूल कीमत प्रभाव, ऐसी क्षति के प्रमाण हैं।
- (ङ) पाटन के कारण होने वाली घरेलू उद्योग की क्षति का निदान करने के लिए पाटन-रोधी शुल्क लागू करने की आवश्यकता है।
- सऊदी कयान ने बहुत विलम्बित चरण में कुछ निवेदन किए हैं और “न्यू शिपर समीक्षा” करवाने के लिए आवेदन करने के अपने अधिकार का दावा किया है। याचिकादाता का निवेदन है कि सऊदी कयान, साक और सदरा से संबंधित है क्योंकि इन्होंने संयुक्त रूप से सबुको बनाई है और इसलिए सऊदी कयान को भविष्य में “न्यू शिपर समीक्षा” से लाभान्वित होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। किसी भी स्थिति में ये मुद्दा वर्तमान मामले से विषयेतर है और याचिकादाता का निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि कृपया हकादारी अथवा अन्यथा कंपनी के बारे में किसी भी प्रकार का कोई प्रेक्षण नहीं किया जाए।
- प्रकटन विवरण के पैरा संख्या 18 (ठ) घरेलू उद्योग के विचारों के शीर्ष के अंतर्गत ऐसा असावधानी पूर्वक उल्लेख किया गया है कि –

“निर्यातक, सऊदी कलान ऐसा उत्पादक होने के नाते, जिसने जांच अवधि के दौरान भारत में उत्पाद का निर्यात नहीं किया है, “न्यू शिपर समीक्षा” करवाने का हकदार नहीं है।”

- यह अनुरोध है कि उपरोक्त विवरण को निम्नोक्त तरह से पढा जाए:

“निर्यातक, सऊदी कलान ऐसा उत्पादक होने के नाते, जिसने जांच अवधि के दौरान भारत में उत्पाद का निर्यात नहीं किया है, “न्यू शिपर समीक्षा” करवाने का हकदार नहीं है।”

- प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्रतिवादी निर्यातकों की उत्पादन की लागत पर इस कारणवश विचार किया है क्योंकि घरेलू बाजार में की गई बिक्रियां, व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के दौरान हुई बिक्रियों की प्रतिनिधिक नहीं थीं। प्रकटन विवरण से यह स्पष्ट नहीं है कि किस कारणवश सबुको द्वारा अपनी संबद्ध कंपनियों से प्राप्त किए गए टोलिंग प्रभार उचित हैं क्योंकि अन्यथा संबंधित पक्षकारों के नार्मल बुटानोल के उत्पादन की लागत, सही और उचित राशि नहीं दर्शाएंगी। प्राधिकारी अंतिम जांच परिणाम में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख कर सकते हैं।
- दोनों उत्पादकों ने निर्यात कीमत में कमीशन का दावा नहीं किया है। प्राधिकारी कृपया अंतिम जांच परिणाम में कमीशन की लागत के लिए निर्यात कीमत का समायोजन करने पर विचार कर सकते हैं।
- याचिकादाता का निवेदन है कि विधि के अंतर्गत ऐसी अपेक्षा नहीं है कि पाटित आयातों को क्षति का एकल अथवा मुख्य कारण होना चाहिए। कारणात्मक संबंध के बारे में न्यायशास्त्र का यह सुव्यवस्थिति सिद्धांत है कि पाटन को क्षति का मुख्य कारण होने की आवश्यकता नहीं है, भले ही वह अकेला कारण रहा हो। ब्राजील से मेलेबल कास्ट आयरन अथवा पाईप फिटिंग्स (डब्ल्यूटी/डीएस219/एबी/आर) के मामले में अपील निकाय का निर्णय निम्नानुसार है:-

“193. अब हम यह उल्लेख करते हैं कि.....यूरोपीय कमीशन ने पहले अन्य कारकों को अभिज्ञात किया था, जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है। उसके बाद प्रत्येक “अन्य कारक” का पृथक् रूप में मूल्यांकन करने के बाद यूरोपीय यूनियन ने यह निर्धारित किया था कि क्षति के लिए प्रत्येक कारक का योगदान नगण्य था (अथवा एक कारक के लिए इतना नहीं था कि वह पाटित आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को तोड़ सके).....”

- यह सुस्थापित विधि है कि पाटन-रोधी जांच में कारणात्मक संबंध विद्यमान होने की आवश्यकता को पूरा करना करने के लिए यह पूर्णतया आवश्यक नहीं है कि पाटित आयात, क्षति का एक मात्र अथवा प्रमुख कारण हो। कोरिया से डीओटीपी तथा जापान और टर्की से स्टील कंक्रीट रि-इनफोरसिंग बार के मामलों में यूएसआईटीसी ने यह निर्धारित किया है कि अन्य कारकों के कारण क्षति विद्यमान होना नकारात्मक निर्धारण के लिए बाध्यकारी नहीं है। इसके प्रासंगिक उद्धरण संलग्न हैं।
- यह मानते हुए लेकिन स्वीकार नहीं करते हुए कि क्षति के कारणों में अन्य कारकों के विद्यमान होने से सऊदी अरब से पाटन और घरेलू उद्योग की क्षति के बीच कारणात्मक संबंध विकृत अथवा टूटते नहीं हैं, जिससे कि ऐसा निष्कर्ष निकाला जाए कि सऊदी अरब से पाटित आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हुई है। याचिकादाता ब्राजील से मेलेबल कास्ट आयरन अथवा पाईप फिटिंग्स पर पाटन-रोधी शुल्कों के मामले में विश्व व्यापार संगठन की पेनल रिपोर्ट का हवाला देता है और उस पर विश्वास करता है।
- जबकि प्रतिवादी निर्यातकों ने ऐसे “अन्य कारकों” को अभिज्ञात किया है, जो कि घरेलू उद्योग की क्षति का कारण हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने “अन्य कारकों” के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति की मात्रा का उल्लेख नहीं किया है।
- याचिकादाता का निवेदन है कि ऐसे अनेक मामले हैं, जिनमें समस्त जांच अवधि के दौरान एक विशेष देश से आयात नहीं हुए हैं। इसलिए यह किंचित संभव है और वस्तुतः एक से अधिक देश से आयातों के संबंध में प्राधिकारी द्वारा संचालित कुछेक जांच में ऐसा मामला है कि जांचाधीन एक अथवा अधिक देशों से आयात, जांच अवधि के केवल कुछ महीनों में हुए हैं, जो कि जांच शुरू होने या जांच के बीच में या जांच की समाप्ति पर अथवा जांच के बाद हुए हैं। तथापि, यदि ऐसे आयात 3% से अधिक हुए हैं, तो प्राधिकारी ने ऐसे देश को संबद्ध देशों के दायरे से इस कारणवश बाहर नहीं किया है कि ऐसे देश से आयात समस्त जांच अवधि में फैले हुए नहीं थे। इस कारण मात्र से कि आयात, जांच अवधि में समान रूप से फैले हुए नहीं थे अथवा जांच अवधि के शुरू होने या समाप्त होने पर हुए हैं, यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसे आयातों के कारण क्षति नहीं हुई है। इस प्रकार जांच अवधि के किसी भाग में आयातों के विद्यमान होने का अभिप्राय यह नहीं है कि उनसे तब तक कारणात्मक संबंध विद्यमान नहीं हैं, जब तक कि आयात पाटित कीमतों पर होते हैं और घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- इस मामले में जांच अवधि 12 महीनों की है, जो कि प्राधिकारी की सामान्य पद्धति के अनुसार है। यह आवश्यक नहीं है कि समस्त जांच अवधि के दौरान पाटित आयात विद्यमान हों। क्षति अवधि अथवा जांच अवधि में आयातों की निरंतरता की जांच करने के लिए पाटन-रोधी विधि में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। पाटन-रोधी शुल्क लागू करने की आवश्यकता यही है कि आयात आयात 3% से अधिक और उनकी कीमतें पाटित कीमतें होनी चाहिए। वर्तमान मामले में जांच अवधि में सऊदी अरब के बाजार का हिस्सा 14.80

% है और निर्यात कीमत 36.24 रुपए प्रति किलोग्राम है, जो कि सभी आयातक देशों से निम्नतम है और घरेलू उद्योग से कम है। ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें निर्यातक द्वारा किए गए निर्यात छुट-पुट थे, लेकिन उनमें पृथक विशिष्ट मार्जिन स्वीकृत किया गया है। प्राधिकारी ने कभी भी आग्रह नहीं किया है कि आयात न्यूनतम 6 महीनों की अवधि के लिए होने चाहिए ताकि निर्यातक के व्यवहार का मूल्यांकन किया जा सके कि क्या वह आदतन वस्तुओं का पाटन करने का है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने निम्नलिखित ऐसे मामलों में पाटन-रोधी शुल्क की सिफारिश की है, जिनमें आयात केवल जांच अवधि में अथवा उसके भाग में होने सूचित किए गए हैं। इस आशय का साक्ष्य संलग्न है।

- (क) एमोनियम नाइट्रेट – जोर्जिया – जांच अवधि के तीन महीनों (2015-16 की जांच अवधि में केवल जुलाई, अगस्त और फरवरी में) में आयात।
 - (ख) केवल जांच अवधि में आस्ट्रेलिया, यूरोपीय यूनियन और सिंगापुर से फ्लेक्सिबल स्लेबस्टॉक पोलियोले के आयात।
 - (ग) जांच अवधि (2008-09) में मलेशिया, थाईलैंड और विएतनाम से आर-डीवीडी के आयात।
 - (घ) कुछ फोस्फोरस आधारित मिश्रण – केवल जांच अवधि में यूरोपीय यूनियन और चीन से पीओसी13 के आयात।
 - (ङ) डीएफएस- प्रथम मामले में – केवल जांच अवधि में चीन से आयात।
 - (च) केवल जांच अवधि में कातार से कॉस्टिक सोडा के आयात। इसके अतिरिक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जांच की खतरे की भी जांच की गई थी।
 - (छ) यूरोपीय यूनियन, सिंगापुर और जोर्जिया से विटामिन ए पालमीटे के आयात- जोर्जिया से आयात केवल जांच अवधि में सूचित किए गए थे।
 - (ज) चीन और संयुक्त अरब अमीरात से विटरीफाईड/प्रोकलीन टाईलों के आयात।
- वर्तमान मामले में निर्यातकों के पाटन करने के व्यवहार के बारे में कोई संदेह नहीं है क्योंकि संबद्ध वस्तुओं का पाटन, वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने से पहले शुरू हो गया था और प्राधिकारी ने अत्यधिक पाटन मार्जिन निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त इन निर्यातकों द्वारा मात्र 3 महीनों की अल्पावधि में पाटित कीमतों पर किए गए निर्यात की अत्यधिक मात्रा से उनके उग्र पाटन व्यवहार का पता चलता है। निर्यातकों के व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए किसी अन्य तथ्य की जरूरत नहीं है। पाटन-रोधी शुल्क को 5 वर्ष की संभावित अवधि के लिए लागू करते समय निर्यातक गैर-पाटित कीमतों पर वस्तुओं का निर्यात करने के लिए स्वतंत्र है और संबंधित आयातक, निर्यातक के सक्रिय सहयोग से अदा किए गए अतिरिक्त शुल्क की वापसी का दावा कर सकता है। इसके अलावा माध्यावधि समीक्षा करने का भी प्रावधान है जिसके द्वारा लागू किए गए पाटन-रोधी शुल्क को निर्यातक के व्यवहार के आधार पर कम किया जा सकता है अथवा समाप्त किया जा सकता है।
 - प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण के पैरा 92 में यह उल्लेख किया है कि जांच अवधि के प्रथम 9 महीनों में अन्य देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग पर कीमत का दबाव था, जो कि अप्रैल, 2016 में लागू पाटन-रोधी शुल्क के अध्येक्षित था। घरेलू उद्योग यह स्वीकार करता है कि जांच अवधि के प्रथम 9 महीनों के दौरान इन देशों से कीमत का दबाव था। तथापि, जांच अवधि के अंतिम 3 महीनों में घरेलू उद्योग पर कीमत का दबाव इतना अधिक बढ़ गया था कि कच्चे माल की कीमतों में समान गिरावट आए बिना उसे अपनी बिक्री कीमत

घटा कर 4.50 रुपए/प्रति किलोग्राम तक कम करनी पड़ी। इसके अलावा सऊदी अरब से पाटित आयातों ने न केवल घरेलू उद्योग पर कीमत का दबाव डाला, बल्कि उसने अन्य देशों को भी कड़ी प्रतिस्पर्धा दी, जो कि जांच अवधि के प्रथम 9 महीनों में अत्यधिक निर्यात कर रहे थे। जांच अवधि के अंतिम 3 महीनों में अन्य देशों का हिस्सा, कुल आयातों में 100% से घट कर 60% हो गया और मांग में 78% से घट कर 51% हो गया। जांच अवधि के अंतिम 3 महीनों में घरेलू उद्योग और अन्य आयातों के हिस्से में आई गिरावट, सऊदी अरब से आयातों के बढ़ने का मुख्य कारण थी, जिससे सऊदी अरब से पाटित आयातों और क्षति की बीच सीधा संबंध होने का पता चलता है।

- जबकि यह स्वीकार किया जाता है कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। इसके साथ ही अन्य जांच में भी संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण उसे क्षति हुई है। इस जांच में संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण भी क्षति हुई है। इसलिए *“वर्तमान अवधि में सऊदी अरब से आयातों के पाटन के कारण हुई क्षति के प्रभाव की अनदेखी नहीं की जा सकती है, भले ही ऐसा पाटन किसी भी अवधि में हुआ हो।”* यदि संबद्ध आयातों के कारण हुई क्षति को 3 महीनों के लिए पृथक नहीं किया जाता है, तो निम्नलिखित प्राचल संबद्ध आयातों के कारण हुई क्षति को दर्शाते हैं, जैसा कि प्रकटन विवरण में सिद्ध किया गया है:-

(क) प्रतिवादी निर्यातकों के लिए अत्यधिक पाटन मार्जिन।

(ख) कीमत में कटौती और कम कीमत पर बिक्री होना भी अत्यधिक है।

(ग) जांच अवधि में संबद्ध आयातों का बाजार का हिस्सा 12% होना।

- जबकि घरेलू उद्योग ने पूर्व जांच में यूरोपीय यूनियन, मलेशिया, सिंगापुर, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमरीका के खिलाफ उपचारी उपाय करने की मांग की थी, घरेलू उद्योग इस जांच में सऊदी अरब से पाटन के खिलाफ राहत उपाय की मांग कर रहा है। जांच अवधि के प्रथम 9 महीनों में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में मामूली सुधार हुआ है, जबकि अन्य देशों से पाटित आयात विद्यमान थे, लेकिन जांच अवधि के अंतिम 3 महीनों में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में तेजी से गिरावट आई है, जबकि संबद्ध देश से निर्यातकों ने अभूतपूर्व पाटन करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण घरेलू उद्योग को उत्पादन, बिक्रियों की मात्रा, बाजार के हिस्से और क्षमता उपयोग जैसे मात्रात्मक प्राचलों के रूप में आर्थिक क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त कीमत प्राचलों के रूप में क्षति अत्यधिक गहन हो गई है क्योंकि घाटों और नकदी घाटों में वृद्धि हुई है और निवेश पर प्रतिलाभ में और गिरावट आई है, जो कि पहले से नकारात्मक था।
- प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने सऊदी अरब से आयातों के बारे में पहली बार दावा किया है कि उनके कारण उसे आर्थिक क्षति हुई है, जो कि जांच पश्चात अवधि के आंकड़ों पर आधारित है। यह निवेदन है कि धारा 9-ख (1) (ख) (3) के अनुसार “क्षति” में क्षति के सभी तीन रूप शामिल हैं, यथा घरेलू उद्योग की स्थापना को आर्थिक क्षति, आर्थिक क्षति का खतरा और आर्थिक मंदी।

- चीन से सिलाई मशीनों की सुईयों के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने आर्थिक क्षति के साथ क्षति के खतरे की जांच की है और उस पर विचार किया है, जबकि जांच शुरू करने की सूचना में उस पर विचार नहीं किया गया है।
- घरेलू उद्योग का निवेदन है कि पाटन-रोधी शुल्क का रूप, संयुक्त राज्य अमरीका के डालर में पाटन-रोधी शुल्क की निर्धारित मात्रा होनी चाहिए।

निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों/अन्य पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

सऊदी अरब से उत्पादकों/निर्यातकों नामतः सऊदी बुटानोल कंपनी ("सबुको"), सऊदी एक्रेलिक एसिड कंपनी ("साक"), सदरा केमिकल कंपनी ("सदरा"), नेशनल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रियलाइजेशन मार्किटिंग कंपनी ("टान्सी मार्किटिंग"), टोयटा ट्वाओशो कार्पोरेशन ("टोयटा"), पेट्रोकेम मिडल ईस्ट एफजेडई के प्रतिनिधि मेसर्स लक्ष्मी कुमारन एंड श्रीधरन एटोर्नीज ने विभिन्न निवेदन किए हैं, जो कि निम्नानुसार हैं:

- हम निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सऊदी अरब में उत्पादकों की पहचान का समर्थन करते हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सही नोट किया है कि साक नार्मल बुटानोल का उत्पादक है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सही पाया है कि साक, सऊदी कयान और सदरा एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं।
- प्रतिवादी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा प्रतिवादियों को सहयोगी उत्पादक/निर्यातक माने जाने का निर्धारण करने का भी समर्थन करते हैं।
- यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रकटन विवरण में प्रकट किए गए इन अनिवार्य तथ्यों में से किसी एक में भी परिवर्तन करना हो, तो हमारा निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे हमें उस पर अपनी टिप्पणियां देने के लिए हमें पर्याप्त अवसर प्रदान करें।
- निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह विचार करने का प्रस्ताव किया है कि *"क्या सऊदी अरब से आयातों के 3 महीनों की अल्पावधि, संबद्ध विश्व व्यापार संगठन के दिशानिर्देशों/पाटन-रोधी नियमों और विश्लेषणात्मक मूल्यांकन करने के आलोक में पाटन और घरेलू उद्योग की क्षति के प्रमुख प्राचलों का निर्धारण करने के लिए यथोचित और न्याय संगत हैं।"*
- प्रतिवादियों का निवेदन है कि विश्व व्यापार संगठन के दिशानिर्देशों, पाटन-रोधी नियम और विश्लेषणात्मक मूल्यांकन करने के आलोक में 3 महीनों के आयात के आंकड़ों के आधार पर पाटन और घरेलू उद्योग की क्षति के प्रमुख प्राचलों का निर्धारण करने के लिए यह यथोचित और न्याय संगत नहीं है।
- निर्दिष्ट प्राधिकारी ने स्वीकार किया है कि वर्तमान जांच में आंकड़ों का संग्रहण करने की अवधि तीन महीनों की है। विश्व व्यापार संगठन की पाटन-रोधी पद्धतियों संबंधी समिति के अनुसार आंकड़ों का संग्रहण करने की अवधि न्यूनतम छः महीनों की होनी चाहिए। यह बताती है कि –

"यह समिति पाटन और परिणामी क्षति के विद्यमान होने का निर्धारण करने के लिए मूल जांच के संबंध में ये सिफारिश करती है कि –

1. एक सामान्य नियम के अनुसार

(क) पाटन की जांच करने के लिए आंकड़ों का संग्रहण करने की अवधि सामान्यतया बारह महीनों की होनी चाहिए और किसी भी स्थिति में यह छः महीनों से कम नहीं होनी चाहिए, जैसा व्यवहारिक है, यह जांच शुरू करने की तारीख के निकटस्थ होनी चाहिए।”

इसके अतिरिक्त समिति मानती है कि आंकड़े संग्रहण करने की छः महीनों की अवधि पाटन के विद्यमान होने का निर्धारण करने के लिए पर्याप्त है। दिशा-निर्देशों का वस्तुतः तात्पर्य यह है कि जांच अवधि ऐसी होनी चाहिए ताकि संबद्ध देशों से न्यूनतम छः महीनों के आयात/निर्यात के आंकड़े प्राप्त हो जाएं। हालांकि यह प्रावधान सिफारिश के रूप में है, लेकिन इस प्रावधान की प्रकृति के बारे में दिशा-निर्देशों में कोई संदिग्धता नहीं है, जो कि इस पर बल देती है कि न्यूनतम अवधि छः महीनों से कम नहीं होनी चाहिए।

- भारतीय प्राधिकारी ने जांच अवधि का निर्धारण करने के समय पाटन-रोधी समिति की सिफारिश का सुसंगत रूप से अनुपालन किया है। किसी भी मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मात्र तीन महीनों के आयात/निर्यात के आंकड़ों के आधार पर पाटन और क्षति की सकारात्मक सिफारिश जारी नहीं की है।
- जांच अवधि का चयन करने के लिए यूरोपीय यूनियन द्वारा अपनाई जा रही पद्धति, डीजीएडी द्वारा अपनाई जा रही पद्धति से भिन्न नहीं है। यूरोपीय यूनियन विशेष रूप से जांच अवधि के रूप में एक वर्ष की अवधि अपनाती है। जांच अवधि लंबी रही है अथवा कुछ मामलों में कम रही है। कुछ मामलों में कम अवधि 11 महीनों, 9 महीनों और 6 महीनों की रही है, लेकिन 3 महीनों की नहीं रही है।
- जांच अवधि की न्यूनतम छः महीनों की अवधि का उद्देश्य सुस्थिर समय अवधि में आंकड़ों का संग्रहण सुनिश्चित करना है। पाटन के साथ-साथ क्षति का विश्वसनीय निर्धारण करने के लिए सुस्थिर अवधि के लिए आंकड़े अत्यावश्यक होते हैं।

(1) पाटन का निर्धारण करने के लिए तीन महीनों की घरेलू बिक्रियों के आयात/निर्यात आंकड़े अपर्याप्त होते हैं।

- यूरोपीय यूनियन-ट्यूब अथवा पाईप फिटिंग्स के मामले में यूरोपीय यूनियन ने 1 अप्रैल, 1998 से 31 मार्च, 1999 तक की एक वर्ष की जांच अवधि के दौरान अपनी जांच की थी। जनवरी, 1999 में इस अवधि के अंत में ब्राजीलियन रियल का 42 प्रतिशत तक अवमूल्यन हो गया था। ब्राजील ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय यूनियन का यह दायित्व है कि वह सामान्य मूल्य की तुलना अवमूल्यन पश्चात अवधि से निर्यात कीमतों के साथ करे।
- अपील निकाय ने यह पाया कि ब्राजील के ऐसे दृष्टिकोण से ऐसा पता चलेगा कि बहुत कम अवधि के आंकड़ों के आधार पर निर्धारण किया गया है। जांच अवधि के भीतर एक समय अवधि से आंकड़ों का ऐसा पक्षपात पूर्ण संग्रहण, पाटन का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ जांच अवधि पर जांच प्राधिकारियों की विश्वसनीयता के उद्देश्यों को निष्फल कर देगा।
- यूरोपीय यूनियन-ट्यूब अथवा पाईप फिटिंग्स के मामले में पेनल ने यह भी पाया कि सुस्थिर अवधि के आंकड़ों के संग्रहण पर आधारित पाटन के निर्धारण की बाजार के उतार-चढ़ाव अथवा अन्य अनिश्चितताओं

के कम अध्यधीन होने की संभावना होती है, जो कि उचित मूल्यांकन को विकृत कर सकती हैं और जांच की पर्याप्त रूप से लंबी अवधि यह सुनिश्चित करने के लिए जटिल होती है कि अभिज्ञात किया गया कोई पाटन छुट-पुट होने के बजाय सुस्थिर होता है।

- वर्तमान मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने साक द्वारा किए गए निर्यातों के सकारात्मक पाटन मार्जिन निर्धारित किया है।
- साक के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इसलिए सामान्य मूल्य संरचित किया है क्योंकि इसने ऐसा निर्धारित किया है कि साक की घरेलू बिक्रियां उत्पादन की लागत से कम की गई हैं। तदनुसार, सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ साक की घरेलू बिक्रियों को अलग रखा गया है। सामान्य मूल्य का निर्धारण उत्पादन की लागत सहित एसजीए व्यय और उचित लाभ के आधार पर किया गया है।
- अनुच्छेद 9 क (1) (ग) में यह प्रावधान है कि सामान्य मूल्य, व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत होती है, जब वह यथानिर्धारित निर्यातक देश में खपत के लिए नियत हो अर्थात् जब निर्यातक देश के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्रिया हुई हो। जब ऐसी बिक्रियां उचित तुलना की अनुमति नहीं देती हैं, तो सामान्य मूल्य का निर्धारण, अनुच्छेद 9 क (1) (ग) (2) (ख) के अनुसार उत्पादन की लागत सहित एसजीए व्यय और उचित लाभ के आधार पर किया जा सकता है।
- जब सामान्य मूल्य का निर्धारण, उत्पादक/निर्यातक द्वारा की गई घरेलू बिक्रियों के आधार पर किया जाता है, तो पाटन-रोधी करार का अनुच्छेद 2.2.1 और पाटन-रोधी नियम का अनुबंध-1, पैरा 2 (1), निर्यातक द्वारा ऐसी घरेलू बिक्रियों का न्यूनतम छः महीनों के आंकड़ों के संग्रहण करने की व्यवस्था प्रदान करता है। इसी प्रकार जब सामान्य मूल्य की संरचना, उत्पादक/निर्यातक के उत्पादन की लागत के आधार पर की जाती है, तो यह केवल तभी युक्तिसंगत होता है, जबकि उत्पादक/निर्यातक की उत्पादन की ऐसी लागत भी अचित समय अवधि अर्थात् न्यूनतम छः महीनों की होनी चाहिए। न्यूनतम छः महीनों की अवधि यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है कि उत्पादन की लागत के आंकड़े स्थिर हैं और वे उसकी वास्तविक लागत के प्रतिनिधिक हैं।
- वर्तमान मामले में सबुको (साक का टोल संसाधक) का वाणिज्यिक उत्पादन केवल मार्च, 2016 में शुरू हुआ था। केवल एक महीने के लिए उत्पादन की वास्तविक लागत के आंकड़े उपलब्ध थे और इस प्रकार केवल एक महीने के उत्पादन की लागत, के आधार पर साक के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया था। केवल एक महीने के लागत के आंकड़ों के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण को यथोचित और न्याय संगत नहीं माना जा सकता है।
- उपरोक्त के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के यह भी निवेदन किया जाता है कि सामान्य मूल्य का परिकलन करने के लिए प्राधिकारी ने {***}।

- इसके अतिरिक्त निर्यात कीमत का निर्णायक और विश्वसनीय निर्धारण करने के लिए छः महीनों की अवधि के लिए आयात/निर्यात के आंकड़े आवश्यक हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, पाटन-रोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1 और पाटन-रोधी नियम के अनुबंध-1, पैरा 2 (1) में यह निर्धारित है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए निर्यातक द्वारा घरेलू बिक्रियों के लिए न्यूनतम छः महीनों की अवधि के लिए आयात/निर्यात के आंकड़े आवश्यक हैं। यह तर्क संगत है कि निर्यात कीमत और परिणामी क्षति मार्जिन भी छः महीनों की अवधि के आयात/निर्यात के आंकड़ों पर आधारित होनी चाहिए। वर्तमान मामले में सऊदी अरब से नार्मल बुटानोल के आयात/निर्यात के आंकड़े केवल तीन महीनों अर्थात् जनवरी, 2016 से मार्च, 2016 तक उपलब्ध हैं क्योंकि इस अवधि से पहले सऊदी अरब से नार्मल बुटानोल का कोई निर्यात नहीं हुआ था। एक, दो या तीन महीनों की कम अवधि के आयात आंकड़ों को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।
- सदरा के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इसलिए सामान्य मूल्य संरचित किया है क्योंकि इसने ऐसा निर्धारित किया है कि सदरा की घरेलू बिक्रियां उत्पादन की लागत से कम की गई हैं। तदनुसार, सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ सदरा की घरेलू बिक्रियों को अलग रखा गया है। सामान्य मूल्य का निर्धारण उत्पादन की लागत सहित एसजीए व्यय और उचित लाभ के आधार पर किया गया है।
- अनुच्छेद 9 क (1) (ग) में यह प्रावधान है कि सामान्य मूल्य, व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत होती है, जब वह यथानिर्धारित निर्यातक देश में खपत के लिए नियत हो अर्थात् जब निर्यातक देश के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्रिया हुई हो। जब ऐसी बिक्रियां उचित तुलना की अनुमति नहीं देती हैं, तो सामान्य मूल्य का निर्धारण, अनुच्छेद 9 क (1) (ग) (2) (ख) के अनुसार उत्पादन की लागत सहित एसजीए व्यय और उचित लाभ के आधार पर किया जा सकता है।

(2) तीन महीनों के आयात के आंकड़े क्षति की पहचान करने के लिए अपर्याप्त हैं।

- निर्दिष्ट प्राधिकारी ने नोट किया है कि उन्होंने पक्षकारों द्वारा अपने निवेदनों में दिए गए तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रख कर क्षति के प्राचलों की सार्थक जांच की है।
- प्रकटन विवरण में क्षति की जांच करने के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि -

“जांच अवधि के अंतिम तीन महीनों में भारत में संबद्ध देश से आयात, पूर्णतया तथा भारत में उत्पादन और खपत के प्रसंग में अत्यधिक मात्रा में प्रवेश हुए थे। ये पाटित आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं।”

- निर्दिष्ट प्राधिकारी ने आगे यह भी नोट किया है कि -

“चूंकि केवल अंतिम तीन महीनों में सऊदी अरब से आयात हुए हैं, इसलिए जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षति की जांच करने के लिए प्राधिकारी के पास अत्यंत सीमित आंकड़े थे और उनका प्रस्ताव है कि जांच अवधि के पहले 9 महीनों और अंतिम 3 महीनों पर पृथक रूप से विचार किया जाए।”

- जब जांच की अवधि एक वर्ष की समय अवधि के लिए निर्धारित की गई थी, तो क्षति का निर्धारण भी एक वर्ष की समय अवधि के आंकड़ों के आधार पर किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक वर्ष की जांच अवधि का नौ महीनों और तीन महीनों में उप-विभाजन करने से लंबी अवधि की जांच अवधि का चयन करने का प्रयोजन निरर्थक हो जाएगा।
- अन्य शब्दों में निर्दिष्ट प्राधिकारी यह निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि सऊदी अरब जांच अवधि की अंतिम तिमाही में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन को कुप्रभावित कर रहा है और इसलिए सऊदी अरब से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की आर्थिक क्षति हो रही है।
- संबद्ध देश से आयात की मात्रा प्रारंभिक बिन्दु है और यह क्षति का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। पाटन-रोधी करार के अनुच्छेद 3.1 और पाटन-रोधी नियम के अनुबंध-1, पैरा 1 में यह प्रावधान है कि क्षति का निर्धारण सकारात्मक साक्ष्य पर आधारित होगा और उसमें (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव, दोनों की तथ्यपरक जांच करना निहित होगा। तीन महीनों की अल्प अवधि, (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव, की सही और निष्पक्ष छवि प्रस्तुत नहीं कर सकती है।
- इस प्रकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को आंकड़ों को संग्रहण करने की अल्पावधि के रूप में जांच अवधि पर निर्णय लेने का पूर्ण विवेकाधिकारी नहीं है और इससे सकारात्मक निर्धारण नहीं होगा तथा यह पाटन-रोधी करार और पाटन-रोधी नियमों के अन्य प्रावधान का उल्लंघन होगा।
- प्रकटन विवरण में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह पाया है कि –
“इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सऊदी अरब से आयातों की अवधि, मात्र 3 महीनों की है और जांच अवधि के प्रथम 9 महीनों में कीमतों में गिरावट आनी शुरू हो गई थी जो कि सऊद अरब से आयातों से पूर्व अवधि थी, प्राधिकारी का यह प्रस्ताव है कि सऊदी अरब से आयातों और घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की जांच करने के प्रयोजनार्थ इन पहलुओं पर विचार किया जाए।”
- इस पर बल देना अनावश्यक है कि जांच अवधि के प्रथम 9 महीनों में कीमतों में गिरावट आनी शुरू हो गई थी और जांच अवधि के प्रथम 9 महीनों में घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति के लिए सऊदी अरब से आयातों को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त क्षति की जांच करने की अवधि से पहले तीन वर्षों के दौरान घरेलू उद्योग को हुई किसी भी प्रकार की क्षति के लिए अन्य कारकों, जैसे कि एचपीसीएल (जो कि कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता है) के संयंत्र का बंद हो जाना, अन्य देशों से आयात होना जिन पर पाटनरोधी शुल्क पहले से लागू हो रहे थे आदि को जिम्मेदार माना जा सकता है और न कि सऊदी अरब से आयातों को, जिसका सामान्य कारण यह है कि उक्त अवधि के दौरान सऊदी से कोई आयात नहीं हुए थे।
- बेहतर यही है कि केवल जांच अवधि के अंतिम तीन महीनों में सऊदी अरब से आयात, घरेलू उद्योग की क्षति के लिए उत्तरदायी माने जा सकते हैं। तथापि, ऐसा विश्लेषण करना गलत और अनुचित है।
- विनम्र निवेदन है कि 3 महीनों की अल्पावधि, कारणात्मक संबंध का सार्थक निर्धारण करने के लिए उपयुक्त नहीं होगी। कारणात्मक संबंध का निर्धारण करने के लिए अल्पावधि अपर्याप्त है। पाटन-रोधी करार के अनुच्छेद 3.5 और पाटन-रोधी नियम के अनुबंध-2 के पैरा 5.2 के अनुसार यह प्रदर्शित होना चाहिए कि पाटित आयात, पाटन प्रभाव के कारण घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं। यह प्रमाणित करना संभव नहीं है कि 4 वर्ष की समस्त क्षति जांच अवधि के दौरान और विशेष कर जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को हुई क्षति, जनवरी से मार्च, 2016 तक के तीन महीनों के दौरान हुए आयातों के कारण हुई है।

यह कहना अनावश्यक है कि ऐसा मूल्यांकन, पाटन-रोधी करार के अनुच्छेद 3.1 और पाटन-रोधी नियम के अनुबंध-2 के पैरा (1) के अंतर्गत सार्थक जांच करने की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है।

- इसके अतिरिक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटित आयातों से भिन्न किसी ऐसे अन्य ज्ञात कारकों की भी जांच करेंगे, जो कि उस समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हों तथा इन कारकों के कारण हुई क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है।
- अनेक वर्षों से अर्थात् 4 वर्षों की क्षति की जांच करने की अवधि से घरेलू उद्योग की स्थिति की जांच करना इसलिए उपयुक्त है क्योंकि ऐसा करने से यह पता चलेगा कि मंदी, व्यवसाय अथवा उत्पाद चक्र अथवा घरेलू उद्योग की संरचनात्मक समायोजन करने की समस्याएं आदि जैसे अन्य कारक क्षति के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए यह कहना अनावश्यक है कि 3 महीनों की अवधि से कारणात्मक संबंध का ऐसा निर्धारण नहीं हो पाएगा।
- वर्तमान मामले में पाटन-रोधी करार और भारतीय पाटन-रोधी नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कारणात्मक संबंध का ऐसा कोई निर्धारण करना संभव नहीं होगा, जहां आयात केवल तीन महीनों में हुए हैं, सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर तथ्यपरक निर्धारण की आवश्यकता को छोड़ दो।
- निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह पाया है कि जांच अवधि में उत्पादन, बिक्रियों की मात्रा और क्षमता उपयोग जैसे कुछ प्राचलों में सकारात्मक सुधार हुआ है।
- बाजार के हिस्से, उत्पाद आदि जैसे अन्य प्राचलों के लिए जहां जांच अवधि से पहले नकारात्मक प्रवृत्ति रही है, ऐसी क्षति के लिए सऊदी अरब से आयातों को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है।
- निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि जांच अवधि के दौरान भी कुछ प्राचलों में नकारात्मक प्रवृत्ति बनी रही है और जांच अवधि के अंतिम तीन महीनों में सऊदी अरब से आयात होने शुरू हुए हैं। जांच अवधि के दौरान कुछ प्राचलों में नकारात्मक प्रवृत्ति के निरंतर बने रहने के लिए सऊदी अरब से आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, जो कि जांच अवधि के केवल अंतिम तीन महीनों में हुए थे।
- हम प्रकटन विवरण में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण से इसलिए असहमत हैं क्योंकि संबद्ध देश के साथ-साथ अन्य गैर-संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग के कार्य-निपादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। समस्त जांच अवधि के दौरान गैर-संबद्ध देशों से आयात हुए हैं। तथापि, जांच अवधि के केवल अंतिम तीन महीनों में सऊदी अरब से आयात हुए हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य देशों से हुए आयातों के प्रभाव को सऊदी अरब से हुए आयातों के बराबर नहीं मान सकते हैं। समस्त जांच अवधि के दौरान आर्थिक प्राचलों पर नकारात्मक विकास देखा गया है, जबकि जांच अवधि के केवल अंतिम तीन महीनों में सऊदी अरब से आयात हुए हैं।
- इसके अतिरिक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी यह निष्कर्ष नहीं दे सकते हैं कि सऊदी अरब से आयातों के कारण जांच अवधि की अंतिम तिमाही में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट आई है।
- जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, क्षति और कारणात्मक संबंध का निर्धारण करने के लिए जांच अवधि को दो उप-समूहों में पृथक्कीकरण करने की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त ऐसा करना जांच शुरू करने की सूचना के भी विपरीत होगा जिसमें जांच अवधि एक वर्ष निर्धारित की गई है। किसी भी स्थिति में तीन

महीनों के आयात के आंकड़े, ऐसे आयातों और घरेलू उद्योग की क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का कोई भी निर्धारण करने के लिए अपर्याप्त हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

93. प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदनों और सउदी अरब से उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रकटन विवरण पर दिए गए उत्तर को नोट करते हैं और उनका यह मानना है कि सभी संबद्ध तथ्यों को अंतिम जांच परिणाम के आधार के रूप में प्रकट किया गया है। सार्वजनिक फाइल में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों/सूचना का सभी अगोपनीय वृत्तान्त निहित है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उपरोक्त पैराओं में घरेलू उद्योग के बारे में क्षति, कुछ आर्थिक और वित्तीय प्राचलों को हालांकि प्रतिकूल नोट किया गया है लेकिन वे केवल तीन महीनों में सउदी अरब से आयातों के कारण के लिए जिम्मेदार हैं और इसलिए उनका उपयुक्त विश्लेषण करने की आवश्यकता है। प्राधिकारी ने उपरोक्त पैराओं में उनको सूचित किए गए पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध जैसे जांच के विभिन्न पहलुओं पर घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों की जांच की है और उनका मानना इस प्रकार है :

- (i) प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि अर्थात् 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक पांच देशों नामतः यूरोपीय यूनियन, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमरीका से प्रथम नौ महीनों के दौरान संबद्ध वस्तुओं के आयात हुए हैं। ये देश 1 अप्रैल, 2013 से 30 जून, 2014 तक की जांच अवधि में 20 नवंबर, 2014 को शुरू की गई पाटनरोधी जांच के अध्यक्षीन थे और इसके दिनांक 19 फरवरी, 2016 के अंतिम जांच परिणाम में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की गई थी जिसे दिनांक 13 अप्रैल, 2016 को सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 13/2016-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा स्वीकार किया गया था।
- (ii) प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में वर्ष 2012-13 से 2015-2016 तक वृद्धि हुई है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच की जांच अवधि के दौरान हालांकि उपरोक्त पैरा (i) में उल्लिखित पांच देशों के लिए कोई पाटनरोधी उपाय नहीं किए गए थे, लेकिन घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में विगत दो वित्तीय वर्षों अर्थात् 2013-14 और 2014-15 जिसमें 5 देशों नामतः यूरोपीय यूनियन, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमरीका के विरुद्ध पूर्व पाटनरोधी जांच की पूरी जांच अवधि शामिल है, के साथ उत्पादन, बिक्रियों, क्षमता उपयोग, लाभ और बाजार के हिस्से जैसे प्राचलों की तुलना करने पर उसके कार्य निष्पादन में सुधार दृष्टिगत हुआ है। कार्य निष्पादन में इस सुधार के जिम्मेदार उपरोक्त पांच देशों से पाटन से भिन्न अन्य कारकों को माना जा सकता है क्योंकि पाटनरोधी उपाय इन पांच पाटन करने वाले देशों पर जांच अवधि के पश्चात् अप्रैल, 2000 में लागू किए गए थे। नोट किया गया एक कारक घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत में गिरावट आना है, जिसने प्रति यूनिट घाटों को कम कर दिया है। पांच पाटित श्रोतों के कारण हुई क्षति को पृथक करने के लिए पहले से ही जांच की गई है, अप्रैल, 2016 में पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद इन पांच देशों से आयात की कीमतों के चलन की जांच करने की आवश्यकता है जिसे इस जांच अवधि में अधिप्राप्त नहीं किया गया है। इन आंकड़ों से वस्तुतः आयातों के नए स्रोत अर्थात् सउदी अरब से आयात के कारण हुई क्षति को पृथक करना संभव होगा।
- (iii) इसके अतिरिक्त प्राधिकारी आगे यह भी नोट करते हैं कि जांच अवधि के प्रथम नौ महीनों के दौरान घरेलू उद्योग की “निवल बिक्रियों” की वसूली में पांच देशों नामतः यूरोपीय यूनियन, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमरीका विशेषकर मलेशिया और सिंगापुर से आयात की कीमतों के समनुरूप गिरावट आई है। इन आयातों द्वारा निर्धारित कीमत स्तर की

- तुलना जनवरी-मार्च, 2016 के दौरान सउदी अरब से निर्यात कीमतों के साथ की गई थी और नकि सउदी अरब से उत्पादकों/निर्यातकों के साथ ।
- (iv) वैश्विक बाजार में किसी भी नए व्यवसायी की बाजार में प्रवेश की कीमत की तुलना आयात बाजार में मौजूदा कीमत के साथ की जाती है । इस संबंध में जनवरी-मार्च, 2016 के दौरान सउदी अरब से उपलब्ध कीमतें पांच देशों नामतः यूरोपीय यूनियन, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमरीका से गलत कीमतें थीं जिन्हें पाटनरोधी शुल्क संबंधी उपाय लागू करने के बाद अप्रैल, 2016 में उचित स्तर पर आशोधित किया गया था । इसलिए, जनवरी-मार्च, 2016 में सउदी अरब से उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा कीमतें निर्धारित नहीं की गई थी बल्कि उन्हें दी गई थीं। ऐसी स्थिति में जिसमें भारत में प्रचलित कीमतों को उचित स्तर पर बहाल किया गया है, सउदी अरब से निर्यातों के पैटर्न की निर्यात कीमत का मूल्यांकन तभी किया जा सकता है जबकि जांच अवधि से अधिक की अवधि उपलब्ध हो जिसमें सउदी अरब से निर्यात/कीमतों के पैटर्न पर विचार किया जा सके । इसलिए वर्तमान जांच के अंतर्गत जांच अवधि के कारण सउदी अरब द्वारा भारत को किए गए निर्यात और जांच अवधि के दौरान विचारित घरेलू उद्योग को हुई उसकी परिणामी क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का उचित और तथ्यपरक निर्धारण करने में कठिनाई है ।
- (v) चूंकि इस जांच का प्रयोजन आर्थिक क्षति की जांच करना है और नकि घरेलू उद्योग को क्षति का खतरा होने अथवा आर्थिक मंदी आने का मूल्यांकन करना है, इसलिए सउदी अरब से कीमत और मात्रा की प्रवृत्ति को प्राप्त करने तथा विशेष रूप से पाटन और परिणामी क्षति के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करने के लिए पाटित आयातों से भिन्न कारकों के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए एक उचित अवधि की आवश्यकता है । इस मामले में जनवरी-मार्च, 2016 से निर्यातों की तीन मास की अवधि, सउदी अरब से निर्यातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को सिद्ध करने के लिए निर्णायक नहीं है । प्राधिकारी का यह मानना है कि उपरोक्त विश्लेषण करने के लिए जांच पश्चात अवधि के आंकड़ों पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस अवधि के दौरान पाटन के कारण घरेलू उद्योग को हुई आर्थिक क्षति का निर्धारण करने के लिए वर्तमान जांच के लिए जांच अवधि 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक निर्धारित की गई है ।
- (vi) प्राधिकारी पाटन मार्जिन के परिकलन पर सउदी अरब से उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा किए गए निवेदनों को नोट करते हैं और उनका यह मानना है कि 5 मई, 2000 को अपनाई गई जांच अवधि के दौरान के संबंध में पाटनरोधी पद्धतियों संबंधी समिति के दिशा-निर्देश सिफारिश मात्र हैं जिन्हें उस समय जांच प्राधिकारियों ने विशिष्ट आधार पर एक मामले में उपयुक्त जांच अवधि पर विचार करने के लिए अपनाया गया हो सकता है ।
- (vii) प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. सबुको द्वारा वाणिज्य उत्पादन की वास्तविक तारीख अर्थात मार्च, 2016 का तथ्य जांच की कार्रवाई के दौरान उत्पादक/निर्यातक के स्थल पर जांच करने पर ही ज्ञात हुआ था । इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि मै. सबुको द्वारा प्रायोगिक उत्पादन अक्तूबर, 2015 में शुरू किया गया था और वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा मार्च, 2016 में की गई थी जिसका मै0 सबुको, जोकि दो उत्पादकों/निर्यातकों का टोलर है, के लागत संघटक की संसाधक की प्रक्रिया का निर्धारण करने पर पड़ा है । दो उत्पादकों नामतः मै0 सदरा और मै0 साख के रिकॉर्डों से लिए गए कच्चे माल और एसजीए की लागत पर विचार किया गया है । चूंकि घरेलू अथवा निर्यात बाजार में वाणिज्यिक बिक्रियों के क्रियाकलाप सामान्यतः विवेकपूर्ण कीमत निर्धारण संबंधी समिति पर आधारित होने की आवश्यकता होती है, इसलिए यह तथ्य कि भारत को निर्यात जनवरी, 2016 में किए गए थे तथा मै. सदरा द्वारा पहली घरेलू बिक्रियां दिसंबर,

2015 में की गई थी, सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के संबंध में 6 महीने की जांच अवधि की न्यूनतम अवधि की आवश्यकता तकनीकी रूप से पूरी होती है और उसके संबंध में कोई समझौता नहीं किया गया है। यदि उत्पादकों/निर्यातकों ने वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा की तारीख से पहले घरेलू और निर्यात बाजार में बिक्रियां की होतीं, तो जांच प्राधिकारी ऐसी बिक्रियों की अनदेखी नहीं कर सकते हैं और ऐसे निर्यातों को पाटनरोधी जांच के अधिकार क्षेत्र से छूट नहीं दे सकते हैं। वस्तुतः इस मामले में प्राधिकारी को मै. सबुको के लागत संबंधी आंकड़ों को उचित रूप से अपनाया होता। लेकिन, प्राधिकारी का यह मानना है कि मै. सबुको से संबंधित संसाधक लागत के संघटक को आगे फिर वैध और परिशोधित किया जा सकता है यदि वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख के बाद के 6 महीनों के आंकड़ों को अपनाया जाए ताकि वसूली की जांच करने के साथ-साथ प्रारंभिक और असामान्य लागतों पर विचार किया जा सके जिससे कि “सामान्य मूल्य” को अधिक प्रतिनिधिक और विश्वसनीय बनाया जा सके।

निष्कर्ष एवं सिफारिशें :

94. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों की जांच करने के बाद तथा उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, सीमाओं और विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी का निष्कर्ष निम्नानुसार है :

- (1) सउदी अरब से संबद्ध वस्तुओं के निर्यात की जांच अवधि के अंतिम तीन महीनों की अवधि घरेलू उद्योग की क्षति का मूल्यांकन करने के लिए अपर्याप्त है क्योंकि आर्थिक क्षति का निर्धारण करने के लिए लंबी अवधि के आयातों और घरेलू उद्योग की बिक्रियों के आंकड़ों की आवश्यकता होगी।
- (2) उत्पादन, विशेषकर वाणिज्यिक उत्पादन की मात्रा एक माह की अल्पावधि भी सहयोगी उत्पादकों के लिए प्रतिनिधिक और वास्तविक सामान्य मूल्य का निर्धारण बाधित करती है।
- (3) निर्यात अवधि के तीन महीनों के आधार पर सउदी अरब से आयातों और घरेलू उद्योग की क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता है।
- (4) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी का यह विचार है कि सउदी अरब से संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने की सिफारिश करना उपयुक्त नहीं है और वे एतद्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 14(ख) के अनुसार इस जांच को समाप्त करते हैं।

आगे की प्रक्रिया

95. इस अंतिम जांच परिणाम की अधिसूचना के उपरांत केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील, अधिनियम के संबद्ध प्रावधानों के अनुसार सीमा-शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की जाएगी।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th November, 2017

Sub:— Anti-dumping investigation concerning imports of Normal Butanol or “N-Butyl Alcohol” originating in or exported from Saudi Arabia

No. 14/20/2016-DGAD: Having regard to Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules thereof, as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules).

A. PROCEDURE

1. The procedure described below has been followed:

- a) The Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”), under the above Rules, received a written application from The Andhra Petrochemicals Ltd. (‘APL’) (hereinafter referred to as the “petitioner”) as domestic industry of the subject goods, alleging dumping of Normal Butanol or “N-Butyl Alcohol” (hereinafter also referred to as “subject goods” or “NBA”) originating in or exported from Saudi Arabia (hereinafter referred to as the “subject country”) and resultant injury to domestic industry and requesting recommendations for imposition of anti-dumping duty on imports of the product under consideration from the subject country.
- b) The Authority, on the basis of prima facie sufficient evidence submitted by the petitioner to justify initiation of the investigation, decided to initiate the investigation against imports of the subject goods from the subject country.
- c) The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-Rule 5(5) of the AD Rules.
- d) The Authority issued a public notice dated 2nd September, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigations concerning imports of the subject goods from the subject country.
- e) The Authority forwarded a copy of the public notice to all known exporters (whose details were made available by the Petitioner) and gave them opportunity to make their views known in writing in accordance with the Rule 6(2) of the AD Rules.
- f) The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known importers of the subject goods in India and industry associations and advised them to make their views in writing within forty days from the date of the letter.
- g) The Authority provided a copy of the non-confidential version of application to the known exporters and the Embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules. A copy of the Application was also provided to other interested parties, wherever requested.
- h) The Authority sent questionnaires to elicit relevant information to the following known exporter in the subject country in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

Saudi Arabia Basic Industries Corporation (SABIC)
P.O. Box: 59090,
Riyadh- 11525, Saudi Arabia

- i) In response to the initiation notification, the following exporters/producers from the subject country have responded:
 - i. Saudi Butanol Company (SABUCO)
 - ii. Saudi Acrylic Acid Company (SAAC)
 - iii. Sadara Chemical Company (SADARA)

- iv. Petrochem Middle East FZE (PETROCHEM)
- v. National Industrialization Petrochemical Marketing Co (TASNEE MARKETING)
- vi. Toyota Tsusho Corporation (TOYOTA)

- j) Further, comments and submissions with regard to the present investigation have been made by Sadara Chemical Company and Saudi Butanol Company.
- k) Questionnaire was sent to the following known importers/users/associations of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule6(4) of the AD Rules:

K L J Group of Cos. H/O: KLJ House, 63, Rama Marg, Najafgarh Road, New - Delhi- 110015	PCL Group 703, 7th Floor, DLF Tower - B, District Centre Jasola, New Delhi - 110044
API Inds. Corporation NK Polymers & additives Mfg Co. 36/2 Ringanwada, Near Somnath Indl. Estate, Daman - 396201 (UT)	Rachna Plasticizers Plot No: 116 & 117, Piparia Indl. Estate UT of D & NH, Silvassa, Vapi - Gujarat
Visen Industries Ltd. 102/A, Virwani Industrial Estate Goregaon (E) Mumbai- 4000 063	Micro Inks Ltd. Plot No: 2801/3A & 3, 2082/B, 2083/2, 2084 & 2085-25, Survey No: 285/1, GIDC 3rd Phase, Vapi, Valsad, Gujarat
Alkyl Amines Chemicals Ltd. Plot No. 67, MIDC Patal Ganga Indl- Area Village : Kaire, Tal : Khalapur Dist - Raigad	Lalitha Chem Inds. Pvt. Ltd. Unit No: 2, Plot No: 32B, Nanji Indl. Area, Survey No:200/1/2, Village : Kharadi, Pune
Deepak Nitrite Ltd. Enterprise Centre, 301, III Floor Besides Hotel Orchid, Vileparle (E) Mumbai- 4000099	Payal Polyplast Pvt. Ltd. E-24, Netaji Subhash Marg Darya Gunj New Delhi - 110002
Dorf Ketel Speciality Pvt. Ltd. Intec. Polymer - Division 1 Dorf Ketel Tower, D'Monte Lane, Orilm Malad (W), Mumbai- 400 064	Anushakti Chemical & Drugs Ltd. 71, Udyog Kshetra, 2nd Floor Mulund Goregaon Link Road, Mulund (W), Mumbai- 400080
C J Shah & Co. 105, Bajaj Bhavan, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai- 400021	Ramnislal S. Gosalia & Co. National House, 608, B.J. Marg, Jacob Circle, Mumbai- 400011
Haresh Petrochem Pvt. Ltd. 404/405, Acme Plaza, Andheri Kurla Road, Opp. Sangam Theatre, Andheri (E), Mumbai-400059	Hazel Mercantile Ltd. 3/10, Kapadia Chambers 599, J.S.S. Road, Marine Lines, Mumbai- 4000 02
Kundan Rice Mills Ltd. D-16, City Chambers, Prashant Vihar, Delhi - 110085	Hazel Mercantile Ltd. 3/10, Kapadia Chambers 599, J.S.S. Road, Marine Lines, Mumbai- 4000 02

Asian Solvochem Pvt. Ltd. Windsor, 2nd Floor, CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai- 400098	KLJ Resources Ltd. 76, Juhu Shopping centre, 2nd Floor Gulmohar Cross, 9th Road, Juhu Scheme Mumbai- 400049
Petrochem Middle East (India) Pvt. Ltd. 201, Business Square, B-Wing, Andheri Kurla Road, Opp: Apple- Heritage, Andheri (E), Mumbai- 400093	Pon Pure Chem (P) Ltd. No: 32, H- Block, 15th Main Road, Anna Nagar, Chennai- 600 040
Yog International Pvt. Ltd. Khasra No. 36/8 Mundka Village, Delhi- 110041	Daga Global Chemicals Ltd. 302, Sakar -III, Opp old high court Navrangapura, Ahmedabad- 380009
Apra Enterprises Plot No:176, 2nd Floor, Dr.Keni House Sion (W), Mumbai- 400022	Overseas Polymer Pvt. Ltd. Vinmar House, A-41 MIDC Road No.2 Andheri (E), Mumbai- 400 093
Ketul Chem Pvt. Ltd. Western Edge-1, Kanakia Spaces, Unit No:403, Above Metro shopping Mall, Borivali (E), Mumbai- 400 066	Balmukund Chemicals Pvt. Ltd. Plot No: 4765, GIDC Estate Nr Ficom Char Rasta, Ankleshwar -393002
Paras Dyes & Chemicals B-82, Defence Colony, New Delhi-110024	Jagriti Plastics Ltd 107,M.G. House , Community Centre, Wazirpur Indl. Area, Delhi-110052
Surabhi Enterprises Pvt. Ltd. Head Office 4/1 Camac Street, Ground Floor, Kolkata - 700 016	Sanjay Chemicals (India) Pvt. Ltd. 5th Floor, Kanmoor House 281/287 Narshi Natha Street Masjid, Mumbai - 400 009 (Maharashtra)
Supreme India International C-11, Jeevan Jyot, 18/20, Cawasji Patel Street, Fort, Mumbai - 400 001	Buneesha Chem Pvt. Ltd. 203 / 204, Shiv Chambers, Plot No.21, A-Wing, Sector - 11, Next to MTNL Bldg. CBD Belapur (E), Navi Mumbai
Ankita Chemical Corporation No. 7, Sarwan Bhawan, Nai Gaum Cross Road, Dadar East, Mumbai - 400 014	Ketul Chem Pvt. Ltd. 403, WESTERN EDGE, METRO STORE, BORIVALI (E), Mumbai – 400092
Nutan Chemicals J - 37, M. I. D. C., Bhosari, Pune - 411026, Maharashtra, India	Triveni Aromatics And Perfumery Pvt. Ltd. 136, Pancharatna Char Rasta, G. I. D. C., Vapi - 386195, Gujarat
A.B. Enterprises 202, Shradanand Building 272/ 274, Samuel Street,	Plastichem Inds. Corporation A - 2001, Runwal Pride, 20th Floor, L. B. S. Road, Mulund West,

Mumbai - 400 003	Mumbai - 400 080
Tulsi Chemicals 3, Old No.2, Raja Annamalai Road 1st Floor, Puraswalkam Chennai - 600 084	Dev Chemicals 1-89, Adhyapak Nagar Nangloi Delhi - 110 041
Nayakem Organics (P) Ltd. 242, A to Z industrial estate G Kadam Marg, Lower Parel Mumbai- 400013	Agrichem 20, Jai Vishvambhari CHS, 153A, M.G. Road, Kandivali (W) Mumbai- 400067
Prathamesh Dychem Pvt. Ltd. D-6, M.I.D.C. Phase-II Dombivali (E)	Dai-Ichi Karkaria Ltd. Liberty Building Sir, Vithaldas Thackeray Marg, Mumbai-20
Key Organics Pvt. Ltd. 209, Standford plaza, Plot no. B-65 off.Andheri Malad New link Road, Andheri(W) Mumbai-53	Premier Solvents Pvt. Ltd. 11, Siddhigiri CHS, 2nd Floor S.V.Road Near UTL Borivali (W) Mumbai- 400092
Esters & Solvents, W- 180, TTC Industrial Area Pawane, Thane-Belapur Road Thane- 400613	Fine Organics Inds. Pvt. Ltd. Fine House, Anandji street Off. M.G. Road, Ghatkoper(E) Mumbai- 4000077
Pidilite Industries Ltd. Ramkrishna Mandir Road P.B.No. 17411 Andheri (E) Mumbai- 400059	Isro Product C' Wing East West Estate Unitop House, Safed Pool Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai- 4000072
Galaxy Surfactants Ltd. C-49/2, TTC Industrial Area Pawane Village, Navi Mumbai Vashi- 400703	Lubrizol India Pvt. Ltd. 9/3, Thane- Belapur Road Turbhe, Navi- Mumbai- 400705
Esdee Paints Ltd. Near Power House, Dhokroli Naka Kolshet Road Thane- 400607	Coatwell Paints 6/19, Tardeo Air Conditional Market, Tardeo Road, Mumbai- 400034
Kansai Nerolac Paints Ltd. Nerolac House, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai- 400013	Bharat Resins Ltd. 43, Dabhel Industrial Co.op Society Ltd. Dabhel, Daman- 396210
Synthetics & Polymer Inds/ Bluebell polymers. D-101, Koteswar Palace, opp Garware House Kole Dongri	Krishna Antioxidants Pvt. Ltd. 107/108, Raheja Plaza, Shah Industrial Estate, Opp. Yashraj Studios, Off Link Road

Lane No.4, Andheri (E) Mumbai- 400069	Andheri (W) Mumbai- 400053
Auchtel Product Ltd. 142/C Victor House, N.M Joshi Marg, Lower Parel Mumbai- 400077	Cadila Pharmaceuticals Ltd. Cadila Corporate Campus Sarkhej-Dholka Road, Bhat Ahmedabad- 382210
Aarti Drugs Ltd. Mahendra Inds. Estate Ground Floor, Plot No. 109-D Road No. 29, Sion (E) Mumbai- 400022	Atul Limited Atul 396020, Gujarat
Fineotex Chemicals Industries 42/43, Manorama Chambers, Above Hyundai Santro car Showroom, S.V.Road Bandra (W) Mumbai- 400050	Dhirajlal & Co. 300/3, Jayjee Dadajee Road, Nana Chowk, Mumbai- 400007
Narkhede Chemicals Plot No.C-462, MIDC, TTC Indl. Area, Pawane Navi Mumbai- 400705	Retort Chemicals (P) Ltd. 4/P. Arihant, Opp Anupam Cinema Goregaon (E) Mumbai- 400063
Shalimar Paints Ltd. C-Wing 5th Floor Oberoi Garden Estate Chandivali (E), Mumbai- 400072	Advanced Microdevices (P) Ltd. 21 Industrial Area Ambala Cantt - 133 006
Shree Organics Plot No. 75, Kalyan Nagar Opp. VKI Road No.4 JAIPUR (RAJ)	Divi's Laboratories Ltd. Divi Towers, 7-1-77/E/1/303 Dharam Karan Road, Ameerpet Hyderabad - 500 016
Dr. Reddy's Laboratories Ltd. API SCM Team 8-2-120/76/1/B, 2nd Floor Ashoka Chambers, Road No.2 Banjara Hills, HYDERABAD - 500 034	Mylan Laboratories Limited Plot No 564/A/22 Road No 92, Jubilee Hills, Hyderabad - 500034, India
Hetero Drugs Limited Hetero Corporate, 7-2-A2 Industrial Estate, Sanath Nagar HYDERABAD - 500 082	Hyderabad Chemicals Limited A-24/25, APIE, Balanagar HYDERABAD - 500 037
Sreepathi Pharmaceuticals Limited Plot No.22 B, Road No.2 Jubilee Hills,	Suven Life Sceinces Ltd. Serene Chambers, Road # 5 Avenue-7, Banjara Hills

HYDERABAD - 500 033	HYDERABAD - 500 034
M/s Sri Krishna Pharmaceuticals Ltd. C-4, Industrial Area, Uppal Hyderabad – 500 039	Aurobindo Pharmaceuticals Ltd. Plot No. 2, Maitrivihar, Ameerpet, Hyderabad - 500 038
Vivimed Labs. Ltd. 2nd Floor, Veerang Towers, Habsiguda Hyderabad - 500 007	Salicylates & Chemicals Pvt. Ltd. A-25, Road No.18, IDA, Nacharam Hyderabad - 500 076
Laurus Labs Pvt. Ltd. 2nd Floor, Serene Chambers Road No.7, Banjara Hills Hyderabad - 500 034	Ch. Yegnaiah & Sons 1-A, Rashtrapathi Road Secunderabad - 500 003
Akross Synthetics Pvt. Ltd. B4/1, Site 'B' Sudeshpur Inds. Area Greater Noida - 201 306	Bansal Trading Company 605, NDM-1, Netaji Subhash Place Pitampura, New Delhi - 110 034
Payal Group E-24, Netaji Subhash Marg Daryaganj, New Delhi - 110002	Indian Plasticizers Manufacturers Association KLJ House, 63, Rama Marg, Nazafgarh Road, New Delhi 110015

- l) None of the importers/users of the subject goods have responded in the form of questionnaire responses or provided comments to the initiation of the investigation.
- m) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties. The public file was inspected by interested parties, copies of the documents if requested from the public file, were provided.
- n) Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. The Authority accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis, which was made available through public file.
- o) Further information was sought from the petitioner and other interested parties to the extent deemed necessary. Verification of domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of present investigation.
- p) A spot verification was also conducted at the premises of the following producers/exporters:
 - (i) Saudi Butanol Company (SABUCO)
 - (ii) Saudi Acrylic Acid Company (SAAC)
 - (iii) Sadara Chemical Company (SADARA)
 - (iv) National Industrialization Petrochemical Marketing Co (TASNEE)
- q) The above producers/exporters were issued a report of the verification conducted. Comments offered by the exporters have further been taken into account in this finding.
- r) The Non-injurious Price (hereinafter referred to as 'NIP') considering the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) has been worked out to evaluate the extent of injury margin as applicable.

- s) Investigation was carried out for the period starting from 1st April 2015 to 31st March 2016 (12 months) (hereinafter referred to as the 'period of investigation' or the 'POI'). The examination of trends, in the context of injury analysis covered the period covering 2012-13, 2013-14, 2014-15 and the POI.
- t) In accordance with Rule 6(6) of the Anti-dumping Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a oral hearing held on 23rd June 2017. A 2nd oral hearing was held on 24th October, 2017. The parties, who presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- u) Exchange rate for conversion of US\$ to Rs. is considered for the POI as Rs.65.91 as per customs data.
- v) The Authority issued a disclosure statement under Rule 16 on 14th November, 2017 and provided an opportunity to give comments to the disclosure statement till 21st November, 2017.
- w) In this final findings, *** represents information furnished by the interested parties on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

- 2. The product under consideration in the present investigation is "Normal Butanol" or "N-Butyl Alcohol". Normal Butanol is a basic organic chemical normally classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act. Normal Butanol is a primary alcohol with a 4-carbon structure and molecular formula C₄H₉OH. Normal Butanol is an excellent solvent for acid-curable lacquers and baking finishes derived from urea, melamine or phenolic resins. A large part of Normal Butanol is converted into derivatives for use as solvents in coating industries. This product is classified under Customs Tariff heading No. 29051300.
- 3. The applicant has claimed that the subject goods, which are exported from subject country into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. Normal Butanol produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable and hence, should be treated as 'like article' under the AD Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country.

B.1 Views of the Domestic Industry

- 4. The domestic industry has made the following submissions with regard to the product under consideration: -
 - a) The product under consideration in the present petition is n-Butanol also known as n-butyl alcohol or normal butanol. Normal butanol is a primary alcohol with a 4-carbon structure and molecular formula C₄H₉OH. It is a clear, mobile, neutral liquid with a characteristic odor. It is miscible with all common solvents but it is only sparingly soluble in water. NBA occurs naturally as a minor product of the fermentation of sugars and other carbohydrates, and is present in many foods and beverages.
 - b) Normal butanol is an excellent solvent for acid-curable lacquers and baking finishes derived from urea, melamine or phenolic resins. A large part of N-Butanol is converted into derivatives for use as solvents in coating industries.

B.2 Views of Exporters, Importers, Consumers and other Interested Parties

- 5. None of the interested parties have raised any issues with regard to the product under consideration.

B.3 Examination by the Authority

- 6. The product under consideration in the present investigation is "Normal Butanol". Normal Butanol is a basic organic chemical normally classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act. Normal Butanol is a primary alcohol with a 4-carbon structure and molecular formula C₄H₉OH.
- 7. Normal Butanol is an excellent solvent for acid-curable lacquers and baking finishes derived from urea, melamine or phenolic resins. A large part of Normal Butanol is converted into derivatives for use as solvent in coating industries and printing inks. Normal Butanol also finds application as extractant in

production of drugs and natural substances, additive in polishes and cleaners, solubilizer in the textile industry, additive in deicing fluids, anti-icing additive in gasoline, humectant for cellulose nitrate, feedstock in the production of glycol ethers and flotation aids (Butyl Xanthate) and as starting material for the production of Butyl mono Carboxylates, Butyl Acetate, Butyl butyrate.

8. The product is classified under Customs Tariff heading No. 29051300. However, the said Customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.
9. Rule 2(d) relating to the definition of "like article" specifies that "like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation, or in the absence of such an article, another article having characteristics closely resembling those of the article under investigation.
10. The petitioner has claimed that the subject goods, which are exported from the subject country into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. Normal Butanol produced by the domestic industry and imported from subject country are comparable in terms of physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable and hence, should be treated as 'like article' under the AD Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the petitioner in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country.
11. The Authority notes that none of the other interested parties has made any submissions on the issue of like article. The Authority concludes that Normal Butanol manufactured by the petitioner constitutes like article to the subject goods being imported into India from the subject country.

C. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

12. Rule 2 (b) of the AD rules defines domestic industry as under:

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers"

C.1 Views of the Domestic Industry

13. The domestic industry has made the following submissions with regard to the 'domestic industry': -

- a) The petition has been filed by M/s The Andhra Petrochemicals Limited as domestic industry.
- b) The Petitioner is the sole producer of the subject goods in India.
- c) Petitioner has neither imported the subject goods nor is related (either directly or indirectly) to any exporter or importer of product under consideration in the subject country.
- d) The petitioner is eligible to constitute domestic industry as per Rule 2(b).

C.2 Views of Exporters, Importers, Consumers and other Interested Parties

14. None of the interested parties have raised any issues with regard to the scope and standing of the domestic industry.

C.3 Examination by the Authority

15. The Authority notes that the application was filed by M/s The Andhra Petrochemicals Limited as domestic industry. The Petitioner is the sole producer of the subject goods in India. The petitioner has not imported the subject goods during the POI. Further, the petitioner is not related (either directly or indirectly) to any of the exporters from the subject country or the importers in India of the product under consideration.

16. After due examination of the information on record and considering the legal provisions, the Authority holds that the petitioner satisfies the requirements of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules. The petitioner is, therefore, held to constitute domestic industry and has standing to file the petition.

D. DUMPING MARGIN

I. NORMAL VALUE

17. Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:

- (i) *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
- (ii) *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*
 - (a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under subsection (6); or*
 - (b) *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);*

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

D.1 Views of the Domestic Industry

18. The following are the submissions made by the petitioner in respect of normal value:

- (a) The following can form the basis for determination of normal value in the exporting country:
 - (i) The price of the like article in the domestic market of the exporting country in the ordinary course of trade,
 - (ii) Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country,
 - (iii) The cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling & general costs and for profits.
- (b) Efforts were made to get information/evidence of price of subject goods in the domestic market of the subject country. Efforts were also made to get price lists or quotations of producers of subject goods in the subject country. However, the petitioner has not been able to get any reliable information of prices prevailing in the domestic market of the subject country.
- (c) There is no difference in the Oxo Technology used by SABUCO and the Andhra Petrochemicals Limited. Hence, there would not be any difference in the production process of Butanol produced by SABUCO and the domestic industry. Therefore, petitioner has claimed determination of normal value using constructed value approach. The petitioner has adopted international prices of raw material and petitioner's power prices to construct the cost of intermediates – Syngas and Butraldehyde and the final product – Normal Butanol. The petitioner has claimed their conversion cost and consumption factors for raw material and utility to be adopted.
- (d) Post-initiation, questionnaire response has been filed by Producer Company, Saudi Butanol Company [SABUCO] and Exporter Companies, Saudi Acrylic Acid Company [SAAC], Sadara Chemical Company [SADARA], Petrochem Middle East FZE, National Industrialization Petrochemical Marketing Company (TASNEE) and Toyota Tsusho Corporation.
- (e) However, no response has been filed by Saudi Kayan (SK). The three joint venture companies have equal rights to control operations of SABUCO on day-to-day basis. Even though SK may not have exported to India, it has a role as important as SAAC and SADARA in exercising control over the operations of

SABUCO such as supplying its share of Propylene to SABUCO and off-take in Butanol, and is therefore, deemed to be related to SAAC and SADARA.

- (f) Failure to file response by one of the joint venture companies should lead to rejection of the entire group's response. Further, there is no clarification regarding the role of SK in the written submissions of the interested parties.
- (g) The representative of the interested parties has blatantly denied existence of any relationship among the three joint ventures in the hearing and evaded all questions raised by the Authority in this regard. The exporter has preferred not to respond to any of the queries raised by the Designated Authority and the domestic industry at the time of oral hearing and in their written submissions, thereby, completely frustrating the very purpose of the oral hearing.
- (h) The export sales of Saudi Kayan are – ZERO, as stated by the representative of the exporter.
- (i) There is no provision in the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (Anti-Dumping Agreement) which specifies the precise duration of the period of data collection.
- (j) The period of investigation fixed by the Authority in the present investigation is April 2015 to March 2016 as per the normal practice of the Authority.
- (k) There are a number of investigations where more than one country has been involved and imports from one of these subject countries have occurred only in the POI and sometimes only towards the end of the investigation period.
- (l) There is no requirement that dumping should have occurred throughout the investigation period.
- (m) The exporter, Saudi Kayan, is entitled to new shipper review, being a producer who has not exported the product to India during the investigation period.
- (n) Excessive confidentiality has been claimed by these producer/exporters.
- (o) Legal and operational structure of the respondents is not adequately explained and vital facts are suppressed.
- (p) Suppression of vital facts by these companies justifies rejection of their questionnaire response.
- (q) The three joint venture promoter companies should be deemed to be related to each other and there is vital suppression of facts in this regard.
- (r) Domestic sales by these companies may constitute sales to related party for production of downstream product, thus leading to absence of viable domestic sales.
- (s) The situation faced by the respondents constitutes existence of particular market situation justifying rejection of domestic sales prices.
- (t) The complex web of operations implies that the cost of production claimed is highly unreliable.
- (u) The cost of production claimed is highly understated due to significant support by parent companies through complex web of operations and inputs from the related entities.
- (v) The producer-exporters have claimed that SABUCO should not be treated as producer and instead SAAC, SK and Sadara should be treated as producers. The claim is highly disputed.
- (w) The producer-exporters were unwilling to even specify the date on which they commenced production and if the production commenced in March, 2016, how they could have started supplying from Jan., 2016. This shows absence of truthful disclosures justifying rejection of questionnaire response.
- (x) The production activities are being carried out by SABUCO only; however SAAC and Sadara (the two joint venture companies) have also claimed start-up cost adjustment.
- (y) The "Tolling Agreement" between SABUCO and its three joint venture promoters may be thoroughly examined.
- (z) The three joint venture companies are owned by large companies such as SABIC, degree of relationship with subsidiaries is not disclosed to reveal information such as sourcing of inputs and services.
- (aa) Sadara has claimed to have purchased propylene from related as well as from unrelated company. The prices of propylene from the related supplier may be checked to ensure that the propylene was sourced at arm's length price.
- (bb) SAAC has not even stated whether they have obtained propylene from related or unrelated supplier.
- (cc) SABUCO has given credit of Iso Butanol in the cost of production of Normal Butanol. The Authority may kindly verify the credit for by-product claimed by the exporter.
- (dd) Actual date of start of trial production by SABUCO may be verified.
- (ee) SABUCO has stated that only Propylene is being supplied by promoter companies. The statement is clearly a false and misleading claim. There is vital suppression of the facts in the response regarding valuation of other facilities for operations.

- (ff) Whether SABUCO has recovered all expenses of tolling with profit from the joint venture parties by means of tolling charges.
- (gg) Whether various inputs received from other related companies are at arm's length price. Sadara has claimed to have purchased propylene from related as well as from unrelated company. The prices of propylene from the related supplier may be checked to ensure that the propylene was sourced at arm's length price.
- (hh) Domestic sales by these companies may constitute sales to related party for production of downstream product, thus leading to absence of viable domestic sales.
- (ii) Shale Gas is used by SABUCO, valuation of which is questionable.
- (jj) SABUCO has been set up in TASNEE Commercial Complex. The declared address of SABUCO is a Post Box number and not a postal address.

D.2 Views of Exporters, Importers, Consumers and other Interested Parties

19. Following submissions have been made by other interested parties with regard to normal value, export price and dumping margin:

- (a) The methodology followed by the Petitioner to determine dumping margin violates the provisions laid down in Article 5.2 and Rule 5(2). The Authority should reject the methodology followed by the Petitioner and determine dumping margin on the basis of information provided in EQR of the exporters.
- (b) Excess of confidentiality has been claimed with regard to CNV methodology and adjustments to export price.
- (c) Initiation notice contends that international prices of raw materials were used for construction of normal value, whereas the Petitioner contends that raw material prices of the Petitioner were used.
- (d) M/s Saudi Butanol Company ("SABUCO") has submitted as under:
 - (i) SABUCO is a joint venture company formed by Sadara Chemical Company, Saudi Acrylic Acid Co., and Saudi Kayan Petrochemical Co. SABUCO converts propylene into Normal Butanol and Iso Butanol on tolling basis for the three joint venture companies. The three companies then proceed to sell the subject goods in the domestic market as well as through exports in markets abroad.
 - (ii) The key raw materials for manufacturing the product are propylene and syngas/ oxogas.
 - (iii) The Saudi Butanol Company has started commercial production of subject goods on 1st March, 2016 and requested for adjustment of start-up cost.
 - (iv) By product generated during the process is Butanol off gas. The amount realized from the sales of Butanol off gas is taken as a credit while determining the production cost of the product concerned.
- (e) SADARA has submitted as under:
 - (i) Sadara Chemical Company is one of the three companies that entered a joint venture agreement in order to form Saudi Butanol Company.
 - (ii) Sadara Chemical Company along with the other two joint venture companies, supplies propylene to SABUCO for conversion into NBA and Iso butanol on tolling basis.
 - (iii) Sadara Chemical Company exports the subject goods to India through Petrochem Middle East FZE.
- (f) M/s Saudi Acrylic Acid Co. (SAAC) has submitted as under: -
 - (i) Saudi Acrylic Acid Co. is one of the three companies that entered a joint venture agreement in order to form Saudi Butanol Company.
 - (ii) Saudi Acrylic Acid Co., along with the other two joint venture companies, supply Sabuco with propylene and Sabuco produces Butanol for each of them on a tolling basis.
 - (iii) Saudi Acrylic Acid Co. then sells the Butanol in the domestic and export markets.
 - (iv) Saudi Acrylic Acid Co. exports the subject goods to India through National Industrialization Petrochemical Marketing Co., who in turn export directly or through Petrochem Middle East FZE and Toyota Tsusho Corporation to Indian customers.
- (g) Petrochem Middle East FZE has submitted as under: -
 - (i) Petrochem Middle East FZE is free zone enterprise located in the Jebel Ali Free Zone Authority,

Dubai, Saudi Arabia.

- (ii) Petrochem Middle East FZE acts as an exporter for both Saudi Acrylic Acid Co. and Sadara Chemical Company for the Butanol procured by them from SABUCO.

- (h) Petrochem Middle East FZE has submitted as under: -

Petrochem Middle East FZE is free zone enterprise located in the Jebel Ali Free Zone Authority, Dubai, Saudi Arabia. Petrochem Middle East FZE acts as an exporter for both Saudi Acrylic Acid Co. and Sadara Chemical Company for the Butanol procured by them from SABUCO.

- (i) National Industrialization Petrochemical Marketing Co. (Tasnee Marketing) has submitted as under: -

- (i) Tasnee Marketing is a limited liability company registered in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia.
 (ii) Tasnee Marketing acts as a marketing company as well as an exporter for Saudi Acrylic Acid Co.
 (iii) It directly exports the subject goods procured from Saudi Acrylic Acid Co., or it transfers such goods to other trading companies who in turn export the same to India.

- (j) Toyota Tsusho Corporation has submitted that it acts as an exporter for Saudi Acrylic Acid Co. by procuring the goods through Tasnee Marketing.

- (k) Embassy of Saudi Arabia has submitted the following:

- (i) The POI for the purpose of present investigation is April 2015 to March 2016. It is an admitted fact that there were no imports from Saudi Arabia before the POI and also during the first nine months of the POI. Imports from Saudi Arabia took place only during last three months of the POI to an extent of 8,791 MT.

- (ii) The commercial production of normal butanol started in Saudi Arabia on 1st March, 2016. Some exports of trial production product took place from Saudi Arabia to India during January 2016 and February 2016. As imports from Saudi Arabia took place only during three months of January 2016-March 2016, the POI being considered by the Designated Authority has in fact been reduced to three months even though technically it is being shown as one year period. If the Designated Authority continues the Subject investigation and determines existence of dumping, injury and causal link, it will imply that the Designated Authority is only considering a short period of three months as the POI for its analysis and not one year as stated in the notice of initiation.

- (iii) Import data of three months is insufficient for assessment of dumping, injury & Causal link. Even though the Anti-dumping Agreement does not expressly provide any specific period as the minimum duration for period of investigation, recommendation by the WTO Committee on Anti-dumping practices provides that:

The period of data collection for dumping investigations normally should be twelve months, and in any case no less than six months, ending as close to the date of initiation as is practicable.”

Thus, the committee considers that the POI should be such that it shall have at – least six months of import data for assessment of dumping, injury and causal link.

Import data for a period of at least six months is necessary because it will not be possible to reach a decisive and reliable conclusion regarding dumping on the basis of a shorter period of one, two or three months. Article 2.2.1 of the WTO Anti-dumping Agreement and Annexure I, para. 2(i) of the Indian Anti-dumping Rules also provide for minimum six months of data concerning domestic sales made by the exporter, which is essential for determining normal value. Therefore, it is logical that import transactions should also occur for a minimum period of six months to allow appropriate comparison.

Secondly, import volume from a subject country is also the starting point and the most crucial information for the purpose of injury determination. A short period of three months cannot provide accurate and unbiased picture of (a) volume and price effect of imports on prices in the domestic market and (b) its impact on domestic producers of such products.

Thirdly, a short period of three months will also not result in an objective assessment of causal link.

It is not possible to establish that injury caused to the domestic industry throughout the injury investigation period of 4 years and particularly during the POI is due to imports during three months of January to March 2016.

- (iv) No legal and equitable determination by the Designated Authority regarding existence of dumping, injury and causal link can be made with the import data of only three months. The initiation of the subject investigation and selection of POI by the Designated Authority is clearly pre-mature. Thus, Kingdom of Saudi Arabia requests the Designated Authority to terminate the present investigation against Saudi Arabia.

(l) M/s Saudi kayan Petrochemical Company (Saudi Kayan) has submitted the following:

- (i) Saudi Kayan along with Saudi Acrylic Acid Co (“SAAC”) and Sadara Chemical Co (“Sadara”) have setup a joint venture company, M/s Saudi Butanol Company (“SABUCO”), each with one-third shareholding. Saudi Kayan, Sadara and SAAC supply propylene to SABUCO and it converts propylene into Normal Butanol and iso Butanol on tolling basis for the three producers.
- (ii) Saudi Kayan has not exported the subject goods to India during the period of investigation (i.e. 1st April 2015 to 31st March 2016). Also, Saudi Kayan is not related to any of the exporters or producers in Saudi Arabia who have exported the subject goods to India during the period of investigation.
- (iii) In term of Rule 22 of the Anti-Dumping Duty Rules 1995, Saudi Kayan would like to reserve its right to apply for a New Shipper Review in case the Authority recommends for imposition of Anti-dumping duty in the subject investigation.

(m) M/s Lakshmi Kumaran & Sridharan Attorneys representing producers/exporters from Saudi Arabia viz. Saudi Butanol Company, Saudi Acrylic Acid Company, Sadara Chemical Company, National Petrochemical Industrialization Marketing Company, Toyota Tsusho Corporation, Petrochem Middle East FZE has additionally submitted the following:

- The selection of POI is inappropriate. Imports from the subject country were made into India only in the last 3 months of the POI. In fact, POI considered by the Authority is of 3 months only even though technically it is named as one year. WTO Committee on Anti-dumping Practices recommends that the period of data collection for dumping investigations normally should be twelve months, and in any case no less than six months, ending as close to the date of initiation as is practicable. Import data of three months is insufficient for assessment of dumping. Import data of a shorter period will not give decisive and reliable conclusion regarding dumping. Injury caused by other known factors must not be attributed to dumped imports. No legal and equitable determination regarding existence of dumping, injury and causal link can be made with the import data of only 3 months. Selection of POI by the Authority is premature. Present investigation should be terminated.
- The methodology followed by the Petitioner to determine dumping margin violates the provisions laid down in Article 5.2 and Rule 5(2). The Authority should reject the methodology followed by the Petitioner and determine dumping margin on the basis of information provided in the exporter questionnaire responses of the exporters.

A. Domestic Industry has raised the following apprehensions which have been responded thereafter

- (i) Suppression of vital facts by these companies justifies rejection of their questionnaire response;
- (ii) Existence of particular market situation implies rejection of domestic sales price;
- (iii) The cost of production is highly understated due to significant support by parent companies through complex web of operations and inputs from related companies;
- (iv) Producer-exporters claimed that SABUCO should not be treated as producers and instead SAAC, SK and Sadara should be treated as producers. Claim is highly disputed;
- (v) The producer-exporters are unwilling to even specify the date on which they commenced production and if the production commenced in the March 2016, how they could have started supplying from Jan 2016;
- (vi) The production activities are being carried out by SABUCO only; however SAAC and Sadara have also claimed start-up cost adjustment;
- (vii) The Authority may also carefully examine the “Tolling Agreement” between SABUCO and its three joint venture companies;

- (viii) Sadara, in response to the questions pertaining to purchase and consumption for all materials/inputs used, responded that propylene has been purchased from related as well as from unrelated company. The petitioner requests the Designated Authority to kindly check the prices of propylene from the related supplier in order to ensure that the propylene was sourced at arm's length price;
- (ix) SAAC, in response to the questions pertaining to purchase and consumption for all materials/inputs used responded "please refer to Appendix – 6". In Appendix-6, all the information is being claimed as confidential. The company has not stated whether they have obtained propylene from related or unrelated supplier. The petitioner is not able to comprehend the difficulty that the exporters seemingly faced in replying to a very simple question;
- (x) SABUCO has given credit of Iso Butanol in the cost of production of Normal Butanol. The Authority may kindly verify the credit for by-product claimed by the exporter.

B. As regards the above apprehensions of Domestic Industry, the issue wise response as under:

- (i) Allegation is vague and unsubstantiated. Designated authority has not made any such observation regarding suppression of vital facts.
 - (ii) There is no particular market situation in the present case. Also, it is not clear what particular market situation domestic industry is referring to. As noted, examination regarding ordinary course of trade with respect to domestic sales is to be carried out by the authority.
 - (iii) Domestic industry does not have access to cost of production details. Producers, toll manufacturers, and traders have submitted complete responses. Designated authority has verified all the information Allegation of domestic industry is without any factual basis.
 - (iv) Allegation is baseless. Explanation and precedents in this regard are provided in the subsequent part of the rejoinder submission.
 - (v) Allegation is false and inconsequential. Commercial production commenced on 1st March 2016. Trial production started prior to 1st March 2016.
 - (vi) As noted, SAAC and Sadara are producers. This is as per the consistent practice of the authority.
 - (vii) The Respondents agree with the domestic industry. Tolling agreement should be carefully examined.
 - (viii) Designated Authority has verified all the prices.
 - (ix) Allegation is false. SAAC has provided all the necessary details. Domestic industry has confused claims of confidentiality and absence of response.
 - (x) Respondents agree that Designated Authority may kindly verify the credit.
- Responses filed by the Respondents cannot be rejected merely because Domestic industry is unable to understand the operations of the Respondents. The Respondents have been fully cooperating with the Designated Authority and have submitted questionnaire responses within the prescribed time-limit. It has also provided responses to queries of the Designated Authority and the Designated Authority has also conducted physical verification at the premises of the Respondents. Thus, there is no case of refusal to access information or absence of necessary information and therefore there is no basis for application of facts available.
 - Domestic industry is incorrect in stating that there are doubts regarding actual producer of the product under consideration in Saudi Arabia. The operations of the Respondents are very simple. SAAC, Saudi Kayan ("SK") and Sadara have setup a joint venture company SABUCO. Each of the promoter company has one third shareholding in SABUCO. SAAC, SK and Sadara supply propylene to SABUCO and it converts propylene into Normal Butanol and Iso Butanol on tolling basis for SAAC, SK and Sadara. Processing charges are paid to SABUCO by the promoter companies. Ownership of propylene and Normal Butanol remains with SAAC, SK & Sadara. The ownership of Normal Butanol is never passed on to SABUCO. Sales of Normal Butanol are also made by these promoter companies only and not by SABUCO. It is clear from the above chain of production that SABUCO is a toll processor and Sadara, SAAC and SK are the producers of the subject goods. During the period of investigation, exports were made by Sadara to India through unrelated trader Petrochem Middle East. A

toll processor cannot be regarded as a manufacturer or producer where it does not acquire ownership over the goods, and does not control the relevant exports or domestic sales. This is also reflected in the practice adopted by the Designated Authority in India. In the anti-dumping investigation on Bulk Drug Cefadroxil Monohydrate originating in or exported from the European Union, the facts regarding toll manufacturing in the exporting countries were similar. DSM Netherlands supplied 7-ADCA and enzymes to DSM Spain along with other raw materials/inputs required for manufacturing the subject goods. DSM Spain carried out the final manufacturing process to manufacture the subject goods in its plant at Spain. For carrying out the final manufacturing step, DSM Spain was paid a tolling fee. The subject goods were then sold by DSM Netherlands either in the domestic market within EU or export markets outside EU. Designated Authority considered DSM Netherlands to be the producer and exporter of subject goods. Authority accepted the response of DSM Netherlands and determined normal value and export price based on the data furnished in the questionnaire response. There is no reason why the authority should deviate from the established practice in this regard. Inability or unwillingness of the domestic industry to understand the simple fact situation regarding production and export of the product under consideration cannot be the ground for rejection of response. Moreover, Domestic industry cannot rely on the absence of response of SK as the ground for rejection of all information. It is not disputed that SK did not export product under consideration to India during the period of investigation either directly or indirectly trader. Thus, there is no necessary information to be supplied by SK for the purpose of this investigation. Completeness of the information submitted by the producers and exporters from Saudi Arabia is not affected. Entire value chain of production and export for the product under investigation during the period of investigation is complete.

- Domestic industry has also generally claimed that all three promoter companies are related. Firstly, relationship between parties are relevant for the purpose of domestic industry definition and not per se relevant in case of exporters. Even assuming that these entities are related, there is no legal requirement for related entities to participate in the investigation if they are not part of the value chain for the product under consideration. Thus, domestic industry fails to refer to any legal provision where promoter companies of a joint venture in the exporting countries are considered to be related.
- Domestic industry has claimed that there may not be viable domestic sales due to the fact that domestic sales are made to related parties. It is submitted that domestic sales made by producers in Saudi Arabia are to be considered for assessment of normal value, if such sales are determined to be in the ordinary course of trade in accordance with Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 r/w Annexure I of the Anti-Dumping Rules, 1995. There is no additional condition attached to the acceptability of domestic sales.
- Normal value cannot be assessed based on economic parameters furnished by the domestic industry in the petition, which are based on its own cost and consumption ratios. Detailed submission regarding irrelevance of such information for the purpose of normal value assessment is already filed in the submissions made earlier and is not repeated herein.
- Domestic industry also requests the authority to rely on evidence furnished in the petition for calculation of export price. Such submission is unwarranted because respondents are co-operating in the present investigation and data provided by respondents should be considered for calculation of export price. If the domestic industry cannot provide any justifiable reason to discard the response submitted by the Respondents from Saudi Arabia, there can be no valid basis to contend that export price calculation should be made based on information furnished by the domestic industry in its petition. Thus, claim regarding substantial dumping margin, which is based on imaginary normal value and export price cannot be accepted.

Examination by the Authority

Determination of Normal Value

20. The Authority sent questionnaires to the known exporters/producers from the subject country, advising them to provide information in the form and manner prescribed. The following parties have filed Exporters Questionnaire Responses:

- a) Saudi Butanol Company
- b) Saudi Acrylic Acid Company
- c) Sadara Chemical Company
- d) National Petrochemical Industrialization Marketing Company
- e) Toyota Tsusho Corporation
- f) Petrochem Middle East FZE

General Methodology for working out Normal Value

21. The Authority in the instant case determined whether the total domestic sales of the subject goods by the producers/exporters in the subject country wherever applicable are representative when compared to the exports of the subject goods to India.
22. Thereafter, it has been examined whether their sales are under ordinary course of trade in terms of Para 2 of the Annexure I to the Anti-dumping Rules. Wherever the producers/exporters have provided transaction wise details of sales made in home market and same have been accepted by the Authority, the said information has been relied upon to determine the normal value of the subject goods sold in the home market.
23. For conducting ordinary course of trade test, the cost of production of the product concerned as determined for cooperative producers/exporters has been referenced and compared with domestic selling price to determine whether the domestic sales are in the ordinary course of trade or not. The authority noted transactions in the domestic market for the determination of the normal value for the cooperating producers/exporters where profit making transactions are more than 80% of volume the domestic selling price during PoI is referenced and in cases, where profitable transactions are less than 80% of volume, only profitable domestic sales have been taken into consideration for the determination of the normal value. In case, there are no profitable domestic sales, the normal value has been determined on the basis of cost of production and administrative, selling and general costs as verified for the cooperating producers duly adjusted and including a reasonable profit margin.
24. The Authority notes that Domestic industry has raised issues regarding relationships between the 3 producers/exporters, wrongly treating the 3 exporters as producers also and considering partial responses only of 2 exporters and non-filing of response by 3rd joint venture partner i.e. Saudi kayan chemical co. In this regard the Authority clarifies that the data of the producers/exporters has been considered as per the books of accounts/relevant financial and commercial documents as verified onsite and accordingly 'dumping margin' has been evaluated. The issue of relationship has also been considered and wherever relationship exists, normal value has been referenced on the cost plus basis. The Authority has verified various relevant issues raised by Domestic Industry onsite/from producers/exporters records. The ownership of raw materials and the final goods i.e. the subject goods has been the basis of considering M/s. SAAC, M/s. Sadara and M/s. Saudi Kayan as producer/exporter. M/s. Sabuco undertakes the tolling/processing activities for these three producers/ exporters as per the agreed arrangement.
25. The authority has noted as under with regard to the production of subject goods in Saudi Arabia:
- a. M/s. Saudi Acrylic Acid Co ("SAAC"), Saudi Kayan Petrochemical Co ("Saudi Kayan") and Sadara Chemical Co ("SADARA") have setup a joint venture company, M/s. Saudi Butanol Company ("SABUCO"), each with one-third shareholding.
 - b. SAAC, Saudi Kayan and SADARA supply propylene to SABUCO and it converts propylene into Normal Butanol and iso Butanol on tolling basis for SAAC, Saudi Kayan and SADARA.

SABUCO has started commercial production of subject goods as on 1st March 2016. The parties have claimed startup cost adjustment on the plea that the unit was under start-up phase during the POI.

- c. The ownership of propylene and well as normal butanol always remains with SAAC, Saudi Kayan and SADARA.
- d. SAAC, Saudi Kayan and SADARA are not related to each other. Their agreement with SABUCO on tolling is based on a commercial arrangement which does not render these 3 entities as related.
- e. SAAC and SADARA along with their related/unrelated exporters have participated in the subject investigation as they have exported the subject goods to India during the POI.
- f. Saudi Kayan has not participated in the subject investigation as they have not exported the subject goods to India during the POI.

Normal value of cooperating producer/exporters

Normal Value for M/s Sadara Chemical Company (“SADARA”), (Producer)

26. During the POI, SADARA has sold subject goods in the domestic market. All sales in the domestic market were made to non-affiliated parties during the POI. The domestic sales were in sufficient volumes when compared with exports to India. As all the domestic sales by SADARA were below the cost of production plus SGA, the normal value has been determined on the basis of cost of production and administrative, selling and general costs as verified and including a reasonable profit margin of ***%.
27. Accordingly, normal value at ex-factory level for SADARA has been determined for subject goods as *** \$/MT as depicted in the Dumping Margin Table below.

Normal Value for M/s. Saudi Acrylic Acid Co. (“SAAC”), (Producer)

28. During the POI, SAAC has sold subject goods in the domestic market. All sales in the domestic market were made insufficient quantity when compared to exports India but were to a related party during the POI. As all the domestic sales by SAAC were further below the cost of production plus SGA, the normal value has been determined on the basis of cost of production and administrative, selling and general costs as verified and including a reasonable profit margin of ***%.
29. Accordingly, normal value at ex-factory level for SAAC has been determined for subject goods as *** \$/MT as depicted in the Dumping Margin Table below.

Normal Value for non-cooperating producers and exporters from subject country

30. The Authority notes that no other producer/exporter from Saudi Arabia has responded to the Authority in the present investigation. For all the non-cooperative producers/exporters in Saudi Arabia, the Authority has determined normal value at ex-factory level for subject goods on the basis of best available information by referencing the highest normal value amongst the cooperating producers/exporters as depicted in the Dumping Margin Table below.

Export Price

Export Price for M/s. Saudi Acrylic Acid Co (“SAAC”) and National Industrialization Petrochemical Marketing Co (“Tasnee Marketing”), M/s. Toyota Tsusho Corporation and M/s. Petrochem Middle East FZE

31. SAAC, a producer of the subject goods in Saudi Arabia, has filed the questionnaire response along with its related trading company, Tasnee Marketing and unrelated traders, namely, M/s. Toyota Tsusho Corporation, Japan & M/s. Petrochem Middle East FZE, Dubai. These trading companies exported the subject goods to India manufactured by SAAC during the POI. All of these exporters/traders have filed their Questionnaire responses with the Authority.

32. The authority notes that SAAC has claimed adjustment on account of ocean freight, insurance and credit expenses and the same have been allowed. Accordingly, the weighted average export price has been determined for SAAC at ex-factory level for subject goods as *** \$/MT as depicted in the Dumping Margin Table below.

Export Price for M/s. Sadara Chemical Company (“SADARA”) and M/s. Petrochem Middle East FZE

33. SADARA, a producer of the subject goods in Saudi Arabia, has filed the questionnaire response along with its unrelated trader, namely M/s. Petrochem Middle East FZE, Dubai.

34. The authority notes that SADARA has claimed adjustment on account of credit expenses as all the sales were on ex-work basis and the same has been allowed. Accordingly, the export price has been determined for SADARA at ex-factory level for subject goods as *** \$/MT as depicted in the Dumping Margin Table below.

Export Price for non-cooperating producers and exporters from Saudi Arabia

35. The Authority notes that no other producer/exporter from Saudi Arabia has responded to the Authority in the present investigation. For all the non-cooperative producers/exporters in Saudi Arabia, the Authority has determined the export price for subject goods on the basis of best available information by referencing the least ex-factory export price amongst the cooperating producers/exporters as depicted in the Dumping Margin Table below.

Dumping Margin

SN	Producer	Exporter	Normal Value	Ex-factory Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin	Dumping Margin
			US\$/MT	US\$/MT	US\$/MT	%	Range
1	SADARA	Petrochem Middle East FZE	***	***	***	***	85 - 95
2	SAAC	Tasnee Marketing	***	***	***	***	35 - 45
3	SAAC	Tasnee Marketing-Petrochem Middle East FZE	***	***	***	***	35 - 45
4	SAAC	Tasnee Marketing – Toyoto Tsusho	***	***	***	***	35 - 45
5	Non-cooperative/Residual producers/exporters other than (1) to (4) above		***	***	***	***	85 - 95

The Authority has examined the adequacy of duration of imports from subject country and commencement of commercial production only in March 2016 appropriately in Para 93 of this findings.

E. INJURY

E.1 Submissions made by the Domestic Industry

36. The domestic industry has submitted that: -

- a) Imports from the subject country started in January 2016 and the volume of such dumped imports in just three months was significant enough to cause material injury to the domestic industry.
- b) The petitioner has segregated the entire injury information within the POI into two parts – (i) April – December 2015 – when there were no imports from the subject country, and, (ii) January – March 2016 – when the imports from the subject country started.
- c) While still examining the injury to the domestic industry during the POI, the Authority may additionally consider the period January to March, 2016 in particular, to examine the extent and degree of injury caused to the domestic industry by dumped imports from the subject country.
- d) Imports in the post POI period shows that the imports during the POI were not casual exports to India from a new plant, but a market opportunity seen by the subject exporters to dump the product.
- e) The capacities with SABUCO, the production sharing by the three promoter companies and the options with them for utilization of the production further shows that the imports in the POI were not casual, but were conscious decisions of these companies to grab the Indian market.
- f) There is significant difference between the prices offered by the domestic industry and the foreign producers. Thus, the domestic industry is unable to raise the prices above the costs as a result of dumping of the product in the Country.
- g) Even when the domestic industry has been offering sub-optimal prices, it was losing sales. Thus, decline in sales volumes is a direct consequence of dumped imports from the subject country.
- h) Despite sub-optimal prices offered by the domestic industry, the imports were undercutting the prices of the domestic industry and creating price pressure on the domestic industry.
- i) Imports are depressing the prices of the domestic industry and preventing the price increases that would have occurred in the absence of dumping.
- j) Performance of the domestic industry with respect to sales, production and capacity utilization had improved as investigations for imposition of anti-dumping duty on other sources were under process in the first nine months of the POI, i.e. April-December 2015. However, the performance in respect of the above parameters has significantly deteriorated in the last three months of the POI, i.e. January-March 2016 as fresh dumping from the subject country started. Further, the Authority had notified positive findings recommending imposition of anti-dumping duty on imports from these sources on 19th February, 2016.
- k) Performance of the domestic industry was adverse in terms of profits, return on investments and cash profit throughout the injury period. Situation has worsened with the commencement of dumped imports from the subject country in Jan-Mar, 2016 period of the POI.
- l) Dumping margin is significant.
- m) The most important factor affecting the prices of the domestic industry is import price from subject country. Thus, the price depression is due to dumping of the product in the market.
- n) Growth of the domestic industry is adverse in terms of both, volume and price parameters.
- o) The domestic industry has suffered material injury as a result of dumping from the subject country.
- p) The injury margin is significant.
- q) Definitive anti-dumping duty is required to be imposed in accordance with the dumping margin and injury margin.
- r) The form of measure is required to be kept as fixed quantum in US\$.
- s) The purpose of segregation of POI in two parts is to show the effect of dumping of the subject goods on the performance of domestic industry and its causal link with injury.
- t) The impact of dumping of subject goods in just 3 months is so significantly felt, that, material injury has been caused to the domestic industry.
- u) Imports upto Dec., 2015 were from other sources dumping the product under consideration and where ADD was imposed after March, 2016. Imports from Saudi started in last quarter of the POI and were significant in no time. Shifting of dumping from one source to other source does not imply that causal link is broken.
- v) The issue concerning shut down because of fire in the plant of propylene supplier of petitioner in the previous period has already been examined by the Designated Authority.
- w) The cause of plant shut down in the present POI was suspension of production in view of un-remunerative prices in the market because of the presence of low priced dumped imports from the subject country.
- x) Domestic industry is not required to cater to 100% of the demand before seeking protection under the law. Further, there is no restriction on imports of the product in the country at fair prices.

E.2 Views of Exporters, Importers, Consumers and other Interested Parties

37. The other interested parties have submitted as follows: -

- a) The application neither fulfills the preconditions for initiation nor qualifies the test of adequacy and accuracy under Rule 5 as sufficient evidence establishing dumping, injury and causal link was not supplied.
- b) Confidentiality - Some of the information provided in the non-confidential version of the Petition is either misleading or insufficient to allow the interested parties to comment meaningfully thereupon. The domestic industry must be directed to disclose the data at least in ranges to allow a meaningful understanding of that table.
- c) Price undercutting margins alleged in the petition should not be considered. Exports are made by Saudi Arabian producers to Indian traders, who incur expenses of storage and warehousing. These costs increase the landed value by 25 – 30%. Price undercutting should be based on comparison of domestic selling price with the resale price of traders in India.
- d) There is absence of causal link between the imports from Saudi Arabia and injury suffered by the domestic industry. Imports from Saudi Arabia increased from NIL in 2014-15 to 8,791 MT in the POI. The sales of domestic industry also increased by 7,117 MT over the same period.
- e) Imports from the other countries were coming into India at dumped prices and free of anti-dumping duty in the POI, which was imposed after the completion of POI. Imports from Saudi Arabia entered Indian market only for the last 3 months of the POI (Apr 15 to Mar 16) and the entire injury period.
- f) The injury suffered is self-inflicted by the domestic industry. The Annual Report of the petitioner shows that they have only one source of raw material supply and had to shut down plant because of fire accident in the plant of the supplier.
- g) Imposition of anti-dumping duties on imports from Saudi Arabia would go against the public interest. There is a demand supply gap. The domestic industry would be able to supply only 32% of demand in India even when producing at full capacity.
- h) There is absence of non-confidential versions of costing data.
- i) M/s. Lakshmi Kumaran & Sridharan Attorneys representing producers/exporters from Saudi Arabia viz. Saudi Butanol Company, Saudi Acrylic Acid Company, Sadara Chemical Company, National Petrochemical Industrialization Marketing Company, Toyota Tsusho Corporation, Petrochem Middle East FZE has submitted the following:
 - Price undercutting margins alleged in the petition should not be considered. Exports are made by Saudi Arabian producers to Indian traders, who incur expenses of storage and warehousing. These costs increase the landed value by 25 – 30%. Price undercutting should be based on comparison of domestic selling price with the resale price of traders in India.
 - Imports from the other countries were coming into India at dumped prices and free of anti-dumping duty in the POI, which was imposed after the completion of POI. Imports from Saudi Arabia entered Indian market only for the last 3 months of the POI (Apr 15 to Mar 16) and the entire injury period.
 - The injury suffered is self-inflicted by the domestic industry. The Annual Report of the petitioner shows that they have only one source of raw material supply and had to shut down plant because of fire accident in the plant of the supplier.
 - Imposition of anti-dumping duties on imports from Saudi Arabia would go against the public interest. There is a demand supply gap. The domestic industry would be able to supply only 32% of demand in India even when producing at full capacity.
 - Domestic industry has segregated POI in two periods (i) April to December, 2015 and (ii) January to March, 2016. Domestic industry does not dispute that there were no imports from the subject country in the first period i.e. for first 9 months of the POI. Domestic industry also admits that period of data collection in the present investigation is effectively of three months and not one year as identified by the Designated Authority. Domestic industry does not deny that the period of data collection for dumping investigations normally should be twelve months and in any case not less than six months.

However, Domestic industry relies on the observation made by the Committee of Anti-dumping practices that investigating authority can take into account particular circumstances of a given investigation in setting the periods of data collection for both dumping and injury to ensure that they are appropriate in each case. Domestic industry claims that dumping, injury and causal link is to be determined based on the import data of three months.

- The claim of the domestic industry cannot be accepted; Firstly, Domestic industry fails to provide for 'particular circumstance' that would necessitate shorter period of investigation; Secondly, the Designated Authority as a matter of practice has followed the recommendation of Committee on Anti-dumping practice in all investigations in past. Domestic industry has failed to provide even one instance in India or in any other jurisdiction where assessment of dumping, injury and causal link is based on the data of three month period only; Thirdly, if the 'particular circumstance' in the present case would have required a shorter period of investigation for data collection, the Designated Authority would not have formally selected one year as the period of investigation in the notice of initiation. In other words, the Designated Authority has already decided that there is no 'particular circumstance' that would necessitate shorter period of investigation; Fourthly, the reliance by the Domestic industry on the observations made by the Panel in *Guatemala – Cement II* is incorrect. Observation of Panel is regarding duration of injury investigation period and not POI. In fact, Panel in *Guatemala – Cement II* allowed a shorter period of one year and not three months for determination of injury due to existence of particular circumstance.
- Merely because the Anti-dumping Agreement does not expressly mandate specific duration for POI does not mean that selection of a shorter time duration of one month, two months or three months as POI is permitted. Appellate Body in *EC-Tube or Pipe Fittings* clearly noted that a POI provides data collected over a sustained period of time, which period can allow the investigating authority to make a dumping determination that is less likely to be subject to market fluctuations or other vagaries that may distort a proper evaluation.
- If the Designated Authority will base its determination regarding dumping, injury and causal link based on a three month time period, it will set a wrong precedent. There would be no minimum duration for which import data has to be analyzed and determination will be based even in cases where imports are occurring for one month or two months. Moreover, it cannot be disputed that three month data cannot reasonably reflect the export behavior of the producers and exporters in Saudi Arabia. Anti-dumping duty recommendation is prospective in nature, which is applicable for next five years. It is required that assessment of dumping, injury and causal link is based on the import data which is reflective of the export behavior of the producer and exporter in the exporting country. Thus, it is incorrect to contend that shorter period of three months is consistent with the provisions of WTO Anti-dumping Agreement and the Anti-dumping Rules. Consequently, entire claim of dumping, injury and causal link that is based on three months data is incorrect and unreliable.
- If the Designated Authority decides to continue the investigation despite the fact that there is import data of only three months, it is submitted that there can be no bifurcation of the period of investigation into nine months and three months for assessment of injury and causal link. Domestic industry cannot continue to sub-divide the period of investigation once the same is fixed by the Designated Authority. Considering the period of investigation as a whole, there is complete absence of causal link between the imports originating in Saudi Arabia and the alleged injury. The production & domestic sales of the domestic industry increased in the same period when the imports from Saudi Arabia entered India, therefore signifying that imports from Saudi Arabia had no impact on the performance of the domestic industry. Similarly, production capacity remained stable and production, capacity utilization and market share increased. Below table is illustrative:

Production capacity of the domestic industry and total demand in India in MT

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Imports from Saudi Arabia	MT	0	0	0	8,791
Imports from EU, Malaysia, Singapore, South Africa & the USA	MT	31,929	42,016	55,243	50,606

Total Demand	MT	46,769	49,798	59,243	70,552
Production capacity	MT	22,500	22,500	22,500	22,500
Sales	MT	14,472	6,425	4,037	11,154
Production	MT	14,409	5,484	4,203	11,080
Capacity utilization	%	64.04%	24.37%	18.68%	49%
Market share	%	31%	13%	7%	16%

- Thus, the injury suffered by the domestic industry, if any, is attributable to imports of normal butanol exported from the EU, Malaysia, Singapore, South Africa and the USA which constituted 85% of the volume of imports and had a 72% share in the domestic demand. Further, the factors such as the shutdown of the production plant for 7 months, the fire accident of 23 August 2013, the lasting consequences of those two events and the shortage in the supply of raw materials have caused the alleged injury suffered by the domestic industry.
- Domestic industry is for the first time claiming that imports Saudi Arabia are causing threat of material injury based on post POI data. At the onset, it is submitted that Domestic industry cannot now claim that there is threat of material injury. Scope of investigation is determined by the initiation notice which did not provide for assessment of threat of Injury. The Domestic industry has never alleged threat of material injury at the time of filing of the petition or even during the public hearing. Present investigation is limited to the assessment of material injury as alleged in the petition and for which the Designated Authority determined that there was prima facie evidence in the notice of initiation. It is settled practice of the Designated Authority that post POI period is not considered for assessment of material injury in the original investigation. In the recently concluded Anti-dumping investigation concerning imports of Wire Rod of Alloy or Non-Alloy Steel originating in or exported from China PR, the Designated Authority observed that:

“With regard to the contention of the interested parties that post POI trends should be examined, the Authority notes that in an original investigation, post POI trends are not relevant. In case of reviews initiated in terms of Rule 23 of the AD Rules, would post POI trends become relevant because the Authority has to examine the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury if anti-dumping duty is withdrawn”

It is an established practice of the Designated Authority to determine material injury based on the data of the POI in the original investigation. In other words, post POI data is irrelevant in the original investigation.

- A. Domestic Industry has made following claims:
 - (i) The three joint venture promoter companies should be deemed to be related to each other;
 - (ii) Designated Authority should thoroughly verify the claim of Respondents that there is increase in the landed value by 25% to 30% due to expenses incurred by Indian traders/importers;
 - (iii) Commencement of imports from Saudi Arabia in last three months of the POI is leading to displacement of domestic sales in the last three months of the POI;
 - (iv) Evidence in the form of Annual Report demonstrating that injury suffered by the domestic industry was due to plant shut down of the supplier of raw material is for the year 2014-15 and not for the POI.
- B. The Producers/Exporters from Saudi Arabia offer rejoinder to the Domestic Industry's claims as under:
 - (i) There is no legal provision which requires the authority to treat three promoter companies as related. Domestic industry has also not cited any legal provision. There is no case where the Designated Authority treated promoter companies as related because together they control a joint venture enterprise.

- (ii) Designated Authority can certainly verify the claim made by the Respondents.
- (iii) There is no injury or displacement of domestic sales during the POI. Data of only last three months is insufficient for the purpose of assessment of material injury and causal link. Unbiased and objective investigating authority cannot base its assessment of material injury and causal link based on three months period.
- (iv) The year 2014-15 is covered in the injury investigation period. Thus, Annual report demonstrating injury caused due to other factors during this period is also required to be analyzed. It is also required to be analysed if performance of the domestic industry was affected in the POI i.e. 2016-2017 due to difficulties experienced in the previous year.

E.3 Examination by the Authority

38. The Authority has taken note of submissions made by Domestic Industry and various interested parties. The Authority has examined injury to the domestic industry in accordance with the Anti-dumping Rules and considering the submissions made by the interested parties.
39. With regard to the contention of violation of Rules in respect of adequacy and accuracy of information provided by the petitioner, the Authority notes that the investigations were initiated only on the basis of sufficient prima facie evidence of dumping, injury and causal link in accordance with Rule 5 of the AD Rules.
40. With regard to the contention on confidentiality, information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file.
41. The AD Rules require the Authority to examine injury by examining both volume and price effect. A determination of injury involves an objective examination of both (a) the volume of the dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like article and (b) the consequent impact of these imports on domestic industry. With regard to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the effect of the dumped imports on prices the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree.
42. As regards the consequent impact of dumped imports on the domestic industry, Para (iv) of Annexure-II of Anti-dumping Rules states as under:

“The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.”

43. It is not necessary that all parameters of injury need to show deterioration, while the Authority considers all injury parameters comprehensively and objectively to conclude whether the domestic industry has suffered injury due to dumping or not.
44. The Authority has examined the injury parameters taking into account the facts and arguments made by the parties in their submissions. The Authority has also examined comments to this disclosure statement appropriately in para 93 of this findings.
45. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation was considered as April, 2015 to March, 2016 (12 months). However, imports from the subject country have occurred only in the last quarter of the POI, that is, January – March, 2016.

I. Assessment of Demand

46. The demand of subject goods has been determined by adding domestic sales of domestic like product with imports of subject goods from all countries obtained from DGCI&S. The Authority notes that demand of subject goods increased significantly over the injury period as depicted in the table below.

Demand	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Sales of Domestic Industry	MT	14,472	6,425	4,037	11,154
Imports – Subject Country	MT	0	0	0	8,791
Imports – Countries with AD Measures	MT	31,929	42,015	55,243	50,606
Imports – Other Countries	MT	205	750	0	0.32
Demand/consumption	MT	46,606	49,190	59,280	70,551
<i>Trend</i>		<i>100</i>	<i>106</i>	<i>127</i>	<i>151</i>

**POI: 2015-16*

II. Volume Effect of Dumped Imports and Impact on Domestic Industry

a) Import Volumes and Share of Subject Country

47. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority notes that there has been a significant increase in imports, in absolute terms from Saudi Arabia during PoI, which has been during January, 2016 to March, 2016 as shown in table below:

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Imports -					
Subject Country	MT	0	0	0	8,791
Countries with AD Measures	MT	31,929	42,015	55,243	50,606
Other Countries	MT	205	750	-	0.32
Total Imports	MT	32,134	42,765	55,243	59,397
Demand	MT	46,606	49,190	59,280	70,551
Production	MT	14,409	5,484	4,203	11,080
Subject imports in relation to -					
Total Imports	%	No imports from Subject country			15%
Consumption	%				12%
Production	%				79%

III. Price Effect of the Dumped Imports on the Domestic Industry

48. With regard to the effect of the dumped imports on prices, Annexure II (ii) of the Rules lays down as follows:

“With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of rule 18 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree.”

49. The impact of dumped imports on the prices of the domestic industry has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any.

a) Price Undercutting

50. The Authority has compared landed price of imports from the subject country with net sales realization of the domestic industry, net of all rebates and taxes, at the same level of trade. This comparison shows that during the period of investigation, the subject goods originating in the subject country were imported into the Indian market at prices which were lower than the selling prices of the domestic industry in the last three months. The table below shows that there is price undercutting from the subject country but this is only during the last 3 months of PoI as there have been no imports during the first 9 months of PoI.

Particulars	Unit	POI
Net Selling Price	Rs/Kg	***
Landed Price	Rs/Kg	39.43
Price undercutting	Rs/Kg	***
Price undercutting	%	25-35%
Price undercutting	Range (%)	25-35%

b) Price Underselling

51. The Authority has also examined price underselling impact on the domestic industry on account of dumped imports from the subject country. For this purpose, the NIP determined for the domestic industry has been compared with the landed price of imports as follows:

Particulars	Unit	POI
Non-injurious Price	Rs/Kg	***
Landed Price	Rs/Kg	39.43
Price underselling	Rs/Kg	***
Price underselling	%	55-75%
Price underselling	Range (%)	55-75%

52. It is seen that the landed prices of the subject goods from the subject country during January 2016 to March 2016 were significantly lower than the NIP determined for the domestic industry. The Authority has examined this aspect later in para 93 of this finding.

c) Price Suppression/Depression

53. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority considered the changes in the costs and prices over the injury period. The position is shown as per the table below:

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Selling Price	Rs/Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	110	92	73
Cost of Sales	Rs/Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	112	113	79

54. It is seen that the costs have increased up to 2014-15, and then declined significant in the POI. The selling price increased up to 2013-14 and then declined in 2014-15 and the POI. The petitioner has claimed that the domestic industry was under constant pressure to sell the subject goods below its cost, resulting in financial losses throughout the injury period and these losses suffered by the domestic industry during the entire injury period are attributed to the dumped imports from present and previous set of dumping countries. The Authority notes that the imports from Saudi Arabia entered the Indian market in last three months of PoI matching the prices prevailing at that time.

IV. Economic parameters of the domestic industry

55. Annexure II to the Anti-dumping Rules requires that determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of like product. The Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth and the ability to raise capital investments. An examination of performance of the domestic industry reveals that the domestic industry has suffered material injury. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

a) Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales

56. The performance of the domestic industry with regard to production, domestic sales, capacity & capacity utilization is as follows:

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Capacity	MT	22,500	22,500	22,500	22,500
Production	MT	14,409	5,484	4,203	11,080
Capacity Utilization	%	64.04%	24.37%	18.68%	49.24%
Domestic Sales	MT	14,472	6,425	4,037	11,154
Demand	MT	46,606	49,190	59,280	70,551

57. It is seen from the above table that the performance of the domestic industry had shown improvement in terms of production, sales volume and capacity utilization in the POI when compared to previous two financial years, however production, sales and capacity utilization has declined as compared to the base year, 2012-13.

58. The petitioner has claimed that decline in production, sales volume and capacity utilization in Jan-Mar 2016 was due to un-remunerative prices and not any technical or other considerations. The Authority notes

that import prices in PoI declined during first 9 months and continued thereafter as well including prices from Saudi Arabia which also matched the prevailing price in India during the last 3 months of PoI.

59. It is noted that production, domestic sales and capacity utilization of the domestic industry has not increased to the extent of increase in demand for the product in the Country in the POI. The Authority holds that correction to the dumped prices from EU, Malaysia, Singapore, South Africa and the USA was made post PoI only and its effect would only be available in post PoI period which is not part of this investigation.

b) Profits, profitability, return on investment and cash profits

60. The cost of sales, selling price, profit/loss, cash profits and return on investment of the domestic industry has been analyzed as follows:

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Cost of Sales	Rs/Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>112</i>	<i>113</i>	<i>79</i>
Selling Price	Rs/Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>110</i>	<i>92</i>	<i>73</i>
Profit/Loss (per unit)	Rs/Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>-100</i>	<i>-155</i>	<i>-732</i>	<i>-268</i>
Profit/loss total	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>-100</i>	<i>-69</i>	<i>-204</i>	<i>-206</i>
Profit before interest	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>-100</i>	<i>-58</i>	<i>-305</i>	<i>-280</i>
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>-100</i>	<i>-82</i>	<i>-308</i>	<i>-290</i>
Return on Investments	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>-100</i>	<i>-67</i>	<i>-360</i>	<i>-379</i>

61. The above analysis shows that the selling price of the domestic industry remained below the cost throughout the PoI, resulting in loss per unit. The profit before interest, cash profit and return on investment remained negative over the injury period. It is seen that losses were also reported in the POI. It is however important to note that imports from Saudi Arabia came after January, 2016 only and the Authority has addressed this issue subsequently in this finding in response to post disclosure comments in para 93.

c) Market Share

62. The effects of the dumped imports on the market share of the domestic industry have been examined as below:

Market Share	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Domestic Industry	%	31%	13%	7%	16%

Subject country	%	0%	0%	0%	12%
Countries with AD Measures	%	69%	85%	93%	72%
Other Countries	%	0%	2%	0%	0%

63. It is seen from the above table that the market share of the domestic industry has declined upto 2014-15 but improved in the POI. The market share of domestic industry in PoI has improved as compared to last 2 financial years i.e. 2013 – 14 and 2014 – 15. However, the market share of the domestic industry in the POI is lower than market share in the base year, 2012-13, on account of major market share being held by other non-subject countries under AD investigation in the POI. The Authority notes that imports from Saudi Arabia happened during last 3 months of PoI and their impact on domestic industry has been addressed subsequently in this finding in para 93.

d) Employment, Productivity and Wages

64. The position with regard to employment, wages and productivity is as follows:

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Employment	Nos.	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>98</i>	<i>97</i>	<i>93</i>
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Wages</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>103</i>	<i>112</i>	<i>107</i>
Productivity per day	MT per day	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>38</i>	<i>29</i>	<i>77</i>
Productivity per employee	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>39</i>	<i>30</i>	<i>82</i>

65. The level of employment has declined over the injury period, whereas wages have increased. The petitioner has claimed that employment and wages are not reflective of the adverse performance of the domestic industry, as these factors are governed by overall operations of the company and the economy. Productivity has moved in the same direction as that of production showing improvement over the last two financial years. The petitioner has claimed that the production of the domestic industry suffered due to un-remunerative product prices (i.e., dumping). However the Authority notes imports from Saudi Arabia happened only during January to March, 2016 and its impact has been dealt appropriately in para 93 of this finding in response to the post disclosure comments.

e) Inventories

66. The data relating to inventory of the subject goods are shown in the following table:

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Average Inventory	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>50</i>	<i>11</i>	<i>16</i>

67. It is seen that the average inventory level has declined with decline in the level of production with the production level in PoI being almost double when compared to last 2 years, the inventory level in PoI does not reflect an adverse situation on this factor.

f) Growth

68. The data relating to growth of the domestic industry is shown in the following table:

Growth	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Production	MT	-	-62%	-23%	164%
Domestic Sales	MT	-	-56%	-37%	176%
Cost of sales	Rs./Kg	-	12%	1%	-30%
Selling price	Rs./Kg	-	10%	-16%	-21%
Profit/(loss)	Rs./Kg	-	55%	373%	-63%
ROI	%	-	1%	-6%	0%
Market Share	%	-	-18%	-6%	9%

The growth table also depicts the improvement made by Domestic Industry in PoI especially on volume parameters when compared to previous 2 years.

69. The Authority notes that the growth of the domestic industry in terms of the volume parameters such as, production and sales volume, shows improvement in the POI as compared to immediately preceding year/years. Growth in terms of price parameters, such as, profits, cash profits and return on investment has remained adverse throughout the injury period. However imports from Saudi Arabia were only post January, 2016 and its impact on Domestic industry has been analyzed in para 93 of this finding.

g) Ability to raise capital investments

70. The Authority notes that the domestic industry is unable to utilize its capacity even in a situation of rising demand of the product in the country, resulting in heavy losses. The fact whether imports from Saudi Arabia over just 3 months can be considered as a cause towards this has been examined in para 93 of this finding.

h) Level of dumping & dumping margin

71. It is noted that imports from the subject country are entering the country at dumped prices and that the margin of dumping is above de-minimis limits. Linkage of imports from Saudi Arabia to injury has been examined in para 93 of the findings.

i) Factors Affecting Domestic Prices

72. The examination of the import prices both from the subject country and other countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market shows that the landed value of imported material from the subject country and other countries concurrently dumping the product were below the selling price and the non-injurious price of the domestic industry, causing significant price undercutting as well as price underselling in the Indian market. Thus, the primary factor affecting the domestic prices is landed value of subject goods from the countries viz. EU, Malaysia, Singapore, South Africa and the USA subjected to Anti-Dumping investigation earlier along with Saudi Arabia for a duration of only 3 months i.e. January to March 2016 under anti-dumping investigation.

j) Conclusion on injury

73. It is thus seen that imports from the subject country had entered India in significant volume in the last 3 months of POI only, both in absolute terms and in relation to production and consumption in India. These dumped imports are also undercutting the prices of the domestic industry in the market.
74. Dumped imports from subject country as well as other non-subject countries have adversely impacted the performance of the domestic industry in respect of production, domestic sales, capacity utilization, inventories, market share, profits, cash profits and return on investment.

75. Performance of the domestic industry with respect to sales, production and capacity utilization had improved when investigations for imposition of anti-dumping duty on other sources were still under process in the first nine months of the POI, i.e. April-December 2015. However the Anti-Dumping measures were imposed post PoI. The performance in respect of the above parameters deteriorated in the last quarter of the POI, i.e. January-March 2016 as fresh imports from the subject country started. The contributory effect imports from Saudi Arabia has been examined in para 93 of this finding.

76. The Authority has also considered first 9 months and last 3 months of PoI separately as under.

77. First 9 Months of PoI (April 2015 to December 2015)

Injury Parameters - Price Undercutting

SN	Particulars	Unit	April to Dec 15
1	Landed Price- Countries attracting ADD		
A	EU	Rs/Kg	63.80
B	Malaysia	Rs/Kg	54.53
C	South Africa	Rs/Kg	56.40
D	USA	Rs/Kg	59.88
E	Singapore	Rs/Kg	58.29
2	NSR	Rs/Kg	***
3	Price undercutting		
A	EU	Rs/Kg	***
B	Malaysia	Rs/Kg	***
C	South Africa	Rs/Kg	***
D	USA	Rs/Kg	***
E	Singapore	Rs/Kg	***

Injury Parameters - Price Depression

SN	Particulars	Unit	April to Dec 15
1	NIP	Rs/Kg	***
2	NSR	Rs/Kg	***
3	Price depression	Rs/Kg	***
4	Profit/(loss)	Rs/Kg	***
5	ROI	%	***

Injury Parameters- Market Share

SN	Particulars	Unit	April to Dec 15
1	Demand		
A	Sales of domestic industry	MT	10,362
B	Imports from Saudi Arab	MT	-
C	Imports from Countries attracting ADD	MT	37,502
	Total	MT	47,864
2	Market Share		
A	Domestic Industry	%	22%
B	Saudi Arab	%	0%
C	Other Countries attracting ADD	%	78%

In first 9 months of PoI, there is a positive price undercutting from Malaysia only. The price depression effect is also quite significant. The market share of Domestic Industry is 22% of demand.

78. Last 3 Months of PoI (January to March 2016)

Injury Parameters – Price undercutting

SN	Particulars	Unit	Jan to Mar 16
1	Landed Price- Saudi Arab	Rs/Kg	39.43
2	Landed Price- Countries attracting ANTI-DUMPING DUTY		
A	EU	Rs/Kg	59.19
B	Malaysia	Rs/Kg	37.83
C	South Africa	Rs/Kg	39.75
D	USA	Rs/Kg	38.38
E	Singapore	Rs/Kg	38.36
3	NSR	Rs/Kg	***
4	Price undercutting		
A	Saudi Arab	Rs/Kg	***
B	EU	Rs/Kg	***
D	Malaysia	Rs/Kg	***
E	South Africa	Rs/Kg	***
F	USA	Rs/Kg	***
G	Singapore	Rs/Kg	***

The price undercutting is positive for all major countries including Saudi Arabia except EU which was negative even in earlier 9 months.

Injury Parameters - Price Depression

SN	Particulars	Unit	Jan to Mar 16
1	NIP	Rs/Kg	***
2	NSR	Rs/Kg	***
3	Price depression	Rs/Kg	***
4	Profit/(loss)	Rs/Kg	***
5	ROI	%	***

The price depression is slightly less as compared to previous 9 months. Market Share of Domestic Industry from 22% of demand is now reduced to 3%.

Injury Parameters- Market Share

SN	Particulars	Unit	Jan to Mar 16
1	Demand		
A	Sales of domestic industry	MT	792
B	Imports from Saudi Arab	MT	8,791
C	Imports from Countries attracting ADD	MT	13,104
	Total	MT	22,688
2	Market Share		
A	Domestic Industry	%	3%
B	Saudi Arab	%	39%
C	Other Countries attracting ADD	%	58%

79. Month wise NSR and Landed values of imports during PoI

	CIF Price					
Month	Saudi Arab	Malaysia	Singapore	South Africa	USA	EU
	Rs/Kg	Rs/Kg	Rs/Kg	Rs/Kg	Rs/Kg	Rs/Kg
Jan-16	39.94	36.86		36.66	34.75	
Feb-16	35.53	38.31		36.31	-	
Mar-16	34.60	37.26	37.98	36.74	-	54.40
	Landed Price					
Jan-16	43.46	37.23	-	39.88	37.81	-
Feb-16	38.65	38.69	-	39.50	-	-
Mar-16	37.65	37.63	38.36	39.98	-	59.19

Month	NSR	Capacity Utilisation	Saudi Arab	Malaysia	Singapore	South Africa	USA	EU
	Rs/Kg	%	Rs/Kg	Rs/Kg	Rs/Kg	Rs/Kg	Rs/Kg	Rs/Kg
Apr-15	***	***	-	59.17	55.74	55.95	59.88	56.53
May-15	***	***	-			60.77		61.30
Jun-15	***	***	-	63.27		65.38		64.34
Jul-15	***	***	-	62.08	64.73			67.45
Aug-15	***	***	-	61.21	63.68			68.65
Sep-15	***	***	-	55.92	60.10			
Oct-15	***	***	-	51.24	54.33	57.86		
Nov-15	***	***	-	46.86	50.41	50.71		
Dec-15	***	***	-	39.25	47.89	45.38		
Jan-16	***	***	43.46	37.23		39.88	37.81	
Feb-16	***	***	38.65	38.69		39.50		
Mar-16	***	***	37.65	37.63	38.36	39.98		59.19

It is seen that landed values of PUC from Malaysia and Singapore have dropped during the first 9 months of PoI and continue at that level and even drop in the last 3 months of PoI. NSR also shows a declining trend during first 9 months and marginally improves in the last 3 months of PoI.

F. Evaluating Causal Link

80. The Authority notes that the interested parties have argued that injury to the domestic industry is due to their dependence on one source of propylene, plant shutdown of its supplier i.e. HPCL due to fire accidents, dumping from other countries in the POI and other factors like inevitability to import due to huge demand supply gap. The Authority has considered these aspects while computing NIP so that while undertaking evaluation of causal link between Dumping and consequential Injury, the inefficiency due to these parameters are not attributed to injury to Domestic industry.
81. The Authority has undertaken appropriate segregation of various factors so as to evaluate the extent of injury only on account of dumped imports. In the instant investigation, the Authority has analyzed injury caused to the domestic industry by segregating the POI in two periods – (a) April – December 2015 – when there were no imports from the subject country; and, (b) January – March 2016 – when the imports from the subject country started as stated above.
82. The Authority has examined below other factors listed under the Antidumping Rules which could have contributed to injury to the domestic industry for examination of causal link between dumping and material injury to the domestic industry.

a) Imports from third countries

83. The Authority has examined import data of the subject goods obtained from DGCI&S. It is noted that the domestic industry is facing injury from dumped imports entering into the country from the subject country as well as other countries for which a separate investigation was done earlier. The Authority has evaluated impact of prices from these countries as well on injury to Domestic Industry in para 93 in later part of the findings.

b) Contraction in demand

84. The Authority notes that the demand for the subject goods has shown significant improvement during the injury period. Possible contraction in demand could not have caused injury to the domestic industry.

c) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

85. The Authority notes that there is no trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry.

d) Developments in technology

86. The Authority notes that the technology adopted and manufacturing process adopted by the domestic industry is quite comparable with that adopted by producers in the subject country. However there is a wide difference in the capacity of producer/exporter of subject country which is many times higher than the Domestic Industry's capacity.

e) Changes in pattern of consumption

87. The domestic industry is producing the subject goods that have been imported into India. Possible changes in the pattern of consumption are not a factor that could have caused claimed injury to the domestic industry.

f) Export performance

88. As the petitioner has not exported the product under consideration, the claimed injury to the domestic industry is on account of domestic operations only.

g) Performance of the domestic industry with respect to other products

89. The performance of other products being produced and sold by the domestic industry has not affected the assessment made by the Authority of the domestic industry's performance since the information considered by the Authority is with respect to the product under consideration only.

h) Productivity of the domestic industry

90. The impact on account of productivity due to various factors like non-availability of raw material are appropriately taken care of while computing NIP.

91. The Authority has determined non-injurious price for the domestic industry in terms of the principles outlined in Annexure III to the AD Rules. The non-injurious price of the domestic industry has been compared with the landed value of the subject imports from each of the responding exporters in the subject country to determine injury margin. The injury margin so determined for each exporter/ producer has been considered for determination of weighted average injury margin. The level of injury margins as

determined are given below. The cooperative producer/exporter have been assessed individually while for non-cooperative best available information has been adopted. The analysis as to whether computation of this injury margin can be attributed to imports from Saudi Arabia during a short period of 3 months has been analyzed appropriately in para 93 of the findings.

<u>Injury Margin</u>							
SN	Producer	Exporter	Non-injurious Price	Landed Price	Injury Margin	Injury Margin	Injury Margin
			US\$/MT	US\$/MT	US\$/MT	%	Range
1	SADARA	Petrochem Middle East FZE	***	***	***	***	80 - 90
2	SAAC	Tasnee Marketing	***	***	***	***	70 - 80
3	SAAC	Tasnee Marketing — Petrochem Middle East FZE	***	***	***	***	70 - 80
4	SAAC	Tasnee Marketing – Toyoto Tsusho	***	***	***	***	70 - 80
5	Non-cooperative/Residual producers/exporters other than (1) to (4) above		***	***	***	***	80 - 90

92. Post disclosure comments

Submissions made by the domestic industry

- The petitioner requests disclosure of following facts, in order to enable them to offer meaningful comments to the disclosure statement:
 - (a) The Authority may kindly disclose the non-confidential version of the verification report of the exporters/producers from the subject country to offer meaningful comments on the dumping margin calculated.
 - (b) The Authority may kindly make available a copy of all the communications sent via mail or letter, to the opposing interested parties and replies filed by these interested parties. Petitioner is not requesting any confidential information. Petitioner is requesting only NCV of this information.
 - (c) It is apparent that Saudi Kayan has made some submissions at a very late stage. Petitioner requests copy of the same to be made available to them.
 - (d) Authority may disclose the actual dumping margin. In this case, the injury margin is much higher than dumping margin. In any case, once the Designated Authority issues final findings, the interested parties shall know the actual dumping margin determined. What would not remain confidential at that stage cannot be confidential at this stage.
- The above is vital for the domestic industry to offer their meaningful comments on the disclosure statement. However, pending such disclosure, the domestic industry offers hereunder following preliminary submissions to the Disclosure Statement. The domestic industry craves leave to make further submissions, as and when the above essential facts are disclosed.
- Petitioner considers that the disclosure statement does not meet the requirements of Rule 16, in as much as it records the contentions of parties with regard to absence of imports throughout the injury period and presence

of dumped imports from other sources in the same period; but does not contain the impact of the same on this aspect with regard to the injury to the domestic industry. The disclosure statement merely states that the Authority proposes to consider these aspects for the purpose of examining causality between imports from Saudi Arabia and injury claimed by the Domestic Industry. The disclosure statement further states that the Authority proposes to consider whether a short period of 3 months of imports from Saudi Arabia is just and reasonable to determine the key parameters of Dumping and Injury to Domestic Industry, in light of relevant WTO guidelines/AD rules and analytic evaluation. Petitioner submits that these statements clearly implies that the disclosure statement is incomplete. When the Authority has not even examined (or revealed to interested parties) these aspects on causality aspects, it follows that the disclosure document does not contain “essential facts” with regard to causal link. What the Designated Authority has disclosed is not a fact. It is an “information”. The petitioner submits that the meaning of disclosure of essential facts means disclosure with regard to existence of relevance facts. Relevant facts in this regard are (a) whether there is dumping, (b) amount of dumping margin, (b) whether there is injury, (c) injury margin, (d) whether injury is due to dumping or some other factors.

- Petitioner concludes as follows from the disclosure statement:
 - a. The product under consideration is Normal Butanol.
 - b. The petitioner is the sole domestic producer of subject goods in India.
 - c. The product under consideration is exported at prices below normal value, resulting in dumping from the subject country. The dumping margin determined for the responding exporters is significant.
 - d. Domestic industry has suffered material injury and such injury is evidenced by adverse price effect of dumped imports from the subject country.
 - e. Anti-dumping duty is required to be imposed to address dumping causing injury to the domestic industry.
- M/s Saudi kayan has made some submissions at a very late stage and claimed the right to apply for New Shipper Review. Petitioner submits that Saudi Kayan is related to SAAC and SADARA by means of forming SABUCO together and therefore, Saudi Kayan should not be allowed to take the advantage of New Shipper in future. In any case, the issue is extraneous to the present case and the petitioner requests the Designated Authority to kindly not make any observations with regard to entitlement or otherwise of the company.
- In the disclosure statement at para no. 18 (m) under Views of the Domestic industry, it is inadvertently stated that:

The exporter, Saudi Kayan, is entitled to new shipper review, being a producer who has not exported the product to India during the investigation period.
- It is requested that the above statement may be read as:

The exporter, Saudi Kayan, is not entitled to new shipper review, being a producer who has not exported the product to India during the investigation period.
- The Authority has considered cost of production of the responding exporters for determination of normal value because of the reason that the sales made in the domestic market were not representative of the sales in the normal course of business. It is not clear from the disclosure statement, whether the tolling charges received by SABUCO from their affiliates are reasonable as otherwise the cost of production of normal

butanol of related parties will not reflect true and fair amount. The Authority may clarify this fact in the Final Findings.

- Both the producers have not claimed commission in the export price. The Authority may kindly consider adjusting the export price for the amount of commission in the Final Findings.
- Petitioner submits that the requirement under the law is not that dumped imports must be the sole or even principal cause of injury. With regard to causal link, it is well settled jurisprudence that dumping need not even be the principal cause of injury, let alone the only cause. The Appellate Body in the case Malleable Cast Iron Tube or Pipe Fittings from Brazil [WT/DS219/AB/R] held as under:

“193. We now turn..... The European Commission first identified other factors that may be causing injury to the domestic industry. In then evaluating each “other factor” individually, the European Commission determined that each factor’s contribution to injury was insignificant (or, for one factor, not so much as to break the causal link between dumped imports and injury).”

- It is a well-settled law that for satisfying the requirement of existence of causal link in anti-dumping investigations, it is absolutely not necessary that dumped imports must be the sole or even principal cause of injury. In DOTP from Korea and Steel Concrete Reinforcing Bar from Japan and Turkey, USITC has determined that the existence of injury caused by other factors does not compel a negative determination. Relevant extracts of the same are enclosed.
- Assuming but not conceding, existence of other factors causing injury does not vitiate or break the causal link between dumping from Saudi Arabia and injury to the domestic industry so as to conclude no injury on account of dumped imports from Saudi Arabia. The petitioner refers and relies on WTO Panel Report in the matter of anti-dumping duties on malleable cast iron tube or pipe fittings from Brazil.
- While the responding exporters have identified “other factors” that could have caused injury to the domestic industry, however, they have not quantified injury being suffered by the domestic industry due to these “other factors”.
- Petitioner submits that there are several cases where imports from a particular country did not occur throughout the investigation period. It is quite possible and, in fact, it indeed is the case in some investigations conducted by the Authority in respect of imports from more than one country that imports from one or more countries under investigation have occurred only in few months of the POI, which could either be in the beginning or in between or towards the end or even periodic over the POI. However, if the imports are beyond 3%, the authority has not excluded such country from the scope of subject countries only because the imports from such country were not spread over the entirety of investigation period. It is because of the reason that merely because imports are not uniformly spread or are only in the beginning or towards the end of the POI, it cannot be said that those imports have not caused injury. Thus, existence of imports only in part of the POI does not mean absence of causal link, so long as the imports are at dumped price and domestic industry has suffered injury.
- The POI of this case is 12 months, which is as per the normal practice of the Authority. It is not necessary that the dumped imports should be present throughout the POI. There is no requirement in the AD law to examine the continuity of the imports over the injury period or in POI. The requirement for imposing the antidumping duties is that the imports should be more than 3% and the prices are dumped prices. In the present case, the

market share of imports from Saudi Arabia is 14.80% in the POI and the export price is Rs 36.24 per Kg, which is lowest among all the importing countries and significantly lower than the domestic industry. There are a number of cases, where the exports made by the exporter were sporadic, however, individual margins have been granted. The Authority never insisted that the imports should be at least for a period of 6 months in order to assess the behavior of the exporter whether it is habitual in dumping the goods. The DA has recommended imposition of anti-dumping duty in the following cases where imports were reported only in the POI or part thereof, evidence to this effect is enclosed herewith:

- a) Ammonium Nitrate – Georgia – Imports in three months of POI (only in Jul, Aug & Feb in 2015-16 period).
 - b) Flexible Slabstock Polyol from Australia, EU & Singapore – Australia only in POI
 - c) R-DVD from Malaysia, Thailand & Vietnam – Vietnam in POI(2008-09)
 - d) Thermal Sensitive Paper from Indonesia, Malaysia & UAE – all subject countries imported in POI only
 - e) Certain Phosphorous based compounds – POCl_3 from EU and China imported in POI only
 - f) DFS – 1st case – China's imports in POI only
 - g) Caustic Soda from Qatar – Imports from Qatar in POI only. Further, threat of injury was also examined by the DA.
 - h) Vitamin A Palmitate from EU, Singapore and Georgia – Imports from Georgia were reported in POI only
 - i) Vittrified/ Procelain Tiles from China and UAE.
- In the instant case, there is no doubt about the dumping behavior of the exporters as dumping of the subject goods started even before the commencement of commercial production and the Authority has determined significant dumping margin. Further, significant volumes were exported by these exporters at dumped prices even in a period as short as 3 months shows aggressive dumping behavior of the exporters. Nothing more is required to assess the behavior of the exporters. While imposition of AD duty is prospective for 5 years, the exporter is free to export the goods at un-dumped prices and the concerned importer can claim refund of excess duty paid with the active co-operation of the exporter. Further, there is provision for mid-term review by which, the AD duty imposed could be reduced or withdrawn based on the price behavior of the exporter.
 - The Authority has stated under the paragraph 92 of the Disclosure Statement that in the first 9 months, there was price pressure on the domestic industry because of the imports from other countries which were subjected to antidumping duty levy in April, 16. The domestic industry admits that there was price pressure from these countries during first 9 months of POI. However, during the last 3 months of POI, the price pressure on the domestic industry increased to the extent that the decline in selling price was more than 4.50/Kg without corresponding decline in raw material prices. Further, the dumped prices from Saudi Arabia created price pressure not only on the domestic industry's prices, but also gave stiff competition to the other countries, who were exporting significantly during the first 9 months of POI. During the last 3 months of POI, the share of other countries declined from 100% to 60% in total imports and from 78% to 51% in demand. The decline in share of domestic industry and other imports in last 3 months of POI are attributed to primarily to imports from Saudi Arabia which shows direct nexus of injury and dumped imports from Saudi Arabia.
 - While it is admitted that the injury suffered by the domestic industry during POI is also simultaneously caused by dumped imports from the subject countries of another investigation as well as dumped imports from the subject country of this investigation; the impact of injury caused by dumping of imports from Saudi Arabia in

present period cannot be ignored, irrespective of the period for which dumping took place. Even if injury caused by subject imports is not segregated for 3 month period, following parameters show injury caused by subject imports as established in the Disclosure Statement:

- a) Significant dumping margin for responding exporters
 - b) Price undercutting and price underselling are also significant
 - c) Subject imports hold market share of 12% in the POI
- While the domestic industry has sought the remedial measure against EU, Malaysia, Singapore, S. Africa and USA in the earlier investigation, the domestic industry is seeking relief measure against dumping from Saudi Arabia through this investigation. The performance of the domestic industry has slightly improved in first 9 months of POI, when the dumped imports from other countries were present, the performance of domestic industry has deteriorated steeply during last 3 months of POI when the exporters from the subject country resorted to unprecedented dumping causing material injury to domestic industry in terms of volume parameters such as production, sales volume, market share and capacity utilization. Further injury in terms of price parameters intensified as losses and cash losses increased and return on investment which was already negative, further declined.
 - The opposing interested parties have contended that domestic industry has for the first time claimed that imports from Saudi Arabia are causing threat of material injury based on post POI data. It is submitted that “Injury” in terms of Section 9B (1)(b)(iii) includes all three forms of injury, i.e., material injury, threat of material injury and material retardation to the establishment of the domestic industry.
 - In Sewing Machine Needles case from China, the DA has examined and considered threat of injury along with material injury, even when the same is not considered for examination in the initiation notice.
 - Domestic industry submits that the form of anti-dumping duty should be fixed quantum of anti-dumping duty (fixed form of duty), in US\$ terms.

Submissions made by the exporters, importers and Other Interested Parties/ other Parties

M/s Lakshmi Kumaran & Sridharan Attorneys representing producers/exporters from Saudi Arabia viz. Saudi Butanol Company (“SABUCO”), Saudi Acrylic Acid Company (“SAAC”), Sadara Chemical Company (“Sadara”), National Petrochemical Industrialization Marketing Company (“Tasnee Marketing”), Toyota Tsusho Corporation (“Toyota”), Petrochem Middle East FZE has filed various submissions:

- We support the identification of producers in Saudi Arabia by the Designated Authority. Designated Authority has correctly noted that SAAC is producer of Normal Butanol. Designated Authority has rightly observed that SAAC, Saudi Kayan and SADARA are not related to each other.
- Respondents also support the determination of the Designated Authority treating Respondents as cooperating producer/exporter.
- If the Designated Authority were to change any of these essential facts disclosed in the disclosure statement, we request the Designated Authority to provide us adequate opportunity to provide our comments.

- The Designated Authority has proposed to consider “*whether a short period of 3 months of imports from Saudi Arabia is just and reasonable to determine the key parameters of dumping and injury to Domestic industry, in light of WTO guidelines/AD rules and analytic evaluation.*”
- Respondents submit that it is not just and reasonable to determine key parameters of dumping and injury to domestic industry based on 3 months import data in light of WTO guidelines, Anti-dumping Rules and analytical evaluation.

Determination of dumping and injury based on short period of 3 months is incorrect in light of WTO law and Indian Anti-dumping Rules

- The Designated Authority has acknowledged that period of data collection in the present investigation is a three months period. WTO Committee on Anti-dumping Practices provides that period of data collection should be of at least six months. It states that:
“The Committee recommends that with respect to original investigations to determine the existence of dumping and consequent injury -
1. as a general rule:
a. the period of data collection for dumping investigations normally should be twelve months, and in any case no less than six months, ending as close to the date of initiation as is practicable.”

Further the Committee considers that minimum period of six months of data collection is appropriate to determine existence of dumping. The guideline effectively means that the period of investigation should be such that it shall have at-least 6 months of import/export data from the subject countries. Even though it is in the form of a recommendation, there is no ambiguity in the guideline regarding the obligatory nature of the provision which stresses that the minimum period should be ‘no less than six months’.

- Indian authority has consistently followed the recommendation of the Anti-dumping committee while determining the period of investigation. In no case, the Designated Authority has issued positive recommendation of dumping and injury based on import/export data of just three months.
- Practice followed by the European Commission for the selection of period of investigation is no different to that of the practice followed by DGAD. The European Commission typically adopts one-year time period as the investigation period. Investigation period have been longer or in some cases shorter. The shorter periods are of 11 months, 9 months and 6 months in some cases but not of 3 months period.
- The objective of providing for a minimum of six months POI is to ensure data collection over a sustained period of time. Data for a sustained period is essential for reliable determination of dumping as well as injury.
 - i. Domestic sales data or import/export data of three months is insufficient for assessment of dumping
- In *EC – Tube or Pipe Fittings*, the European Commission conducted its examination using a POI of one year from 1 April 1998 to 31 March 1999. The Brazilian Real was devalued by 42 percent towards the end of this period in January 1999. Brazil argued that the European Commission was obligated to compare normal values with export prices solely from the post-devaluation period.
- The Appellate Body observed that Brazil’s approach would imply that determination will be based on the data of a very short period. Permitting such discretionary selection of data from a period of time within

the POI would defeat the objectives underlying investigating authorities' reliance on a POI for the purposes of a dumping determination.

- In *EC-Tube or Pipe Fittings*, the Panel also observed that dumping determination based on data collection over a sustained period of time is less likely to be subject to market fluctuations or other vagaries that may distort a proper evaluation and the use of a sufficiently long period of investigation is critical in order to ensure that any dumping identified is sustained rather than sporadic.
- In the present case, the Designated Authority has determined positive dumping margin for exports made by SAAC.
- For determination of normal value for SAAC, the Designated Authority constructed the normal value because it determined that domestic sales by SAAC were made below cost of production. Accordingly, domestic sales by SAAC were discarded for the purpose of determination of normal value. Normal value was determined based on cost of production plus SGA expenses and reasonable profit.
- Section 9A (1)(c) provides that normal value is the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption in the exporting country i.e. the sales of like article in the domestic market of the exporting country. When such sales do not permit proper comparison, normal value can be determined on the basis of cost of production plus SGA expenses and reasonable profit in accordance with Section 9A (1)(c)(ii)(b).
- When determination of normal value is based on domestic sales made by the producer/exporter, Article 2.2.1 of the Anti-dumping Agreement and Annexure I, para. 2(i) of the Indian Anti-dumping Rules provide for minimum of six months of data collection of such domestic sales by the exporter. Similarly, even when normal value is constructed based on cost of production of the producer/exporter, it is only logical that such cost of production of the producer/exporter should also be for a reasonable period of time i.e. minimum of six months. Minimum six months' time period is essential to ensure that cost of production data is stable and representative of its actual cost.
- In the present case, commercial production of SABUCO (toll processor of SAAC) started only on March 2016. Actual cost of production data was available only for one month period and thus cost of production based on which normal value has been determined for SAAC is of one month period only. Determination of normal value based on only one month cost data cannot be considered as just and reasonable.
- Without prejudice to the above, it is also submitted that for calculation of the normal value, the authority has [***].
- Also, import/export data for the period of six months is necessary for decisive and reliable determination of export price. As already noted, Article 2.2.1 of the Anti-dumping Agreement and Annexure I, para. 2(i) of the Indian Anti-dumping prescribes minimum of six months' time period of data collection for domestic sales by the exporter for determination of normal value. It is logical that export price and consequent dumping margin should also be based on import/export data of six months. In the present case, import/export data of Normal Butanol from Saudi Arabia is available for only three months i.e. January 2016 to March 2016 because there were no imports of Normal Butanol from Saudi Arabia before this period. Import data of a shorter period of one, two or three months cannot be considered as reliable.
- For determination of normal value for SADARA, the Designated Authority constructed the normal value because it determined that domestic sales by SADARA were made below cost of production.

Accordingly, domestic sales by SADARA were discarded for the purpose of determination of normal value. Normal value was determined based on cost of production plus SGA expenses and reasonable profit.

- Section 9A 1(c) provides that normal value is the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption in the exporting country i.e. the sales of like article in the domestic market of the exporting country. When such sales do not permit proper comparison, normal value can be determined on the basis of cost of production plus SGA expenses and reasonable profit in accordance with Section 9A1(c)(ii)(b).

ii. Import data of three months is insufficient for identification of injury

- The Designated Authority has noted that it has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and arguments made by the parties in their submission.
- In relation to the examination of injury in the disclosure statement, the Designated Authority concluded that:

“the imports from the subject country had entered India in significant volume in the last 3 months of POI, both in absolute terms and in relation to production and consumption in India. These dumped imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market”

- The Designated Authority has further noted that:

“imports from Saudi Arabia are only during last 3 months to examine the injury to Domestic industry during POI, the Authority has extremely limited data and proposes to consider first 9 months and last 3 months of POI separately”

- When the duration of the POI was fixed for one year time period, assessment of injury should also be made on the basis of data for one year time period. Further sub-division of the one-year POI into nine months and three months period will frustrate the purpose of selecting the POI of longer duration.
- In other words, the Designated Authority cannot determine that imports from Saudi Arabia are affecting the performance of the domestic industry in the last quarter of the POI and therefore there is material injury to the domestic industry due to imports from Saudi Arabia.
- Import volume from subject country is the starting point and very important information for the purpose of injury determination. Article 3.1 of the Anti-dumping Agreement and Para 1 of Annexure II to Indian Anti-Dumping Rules 1995 provide that a determination of injury shall be based on positive evidence and involve an objective examination of both (a) volume of the dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market of like products and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. A short period of three months cannot provide accurate and unbiased picture of (a) volume and price effect of imports on prices in the domestic market and (b) its impact on domestic producers of such products.
- Thus, the Designated Authority does not enjoy absolute discretion in deciding the duration of the POI as shorter period of data collection will not permit objective assessment and will contravene other provision of the Anti-dumping Agreement and Anti-Dumping Rules.
- In the disclosure statement, the Designated Authority has observed that:

“Keeping in view the fact that the period of imports from Saudi Arabia is just 3 months and the backdrop of declining prices in the first 9 months of POI which is prior to imports from Saudi Arabia, the Authority proposes to consider these aspects for the purpose of examining causality between imports from Saudi Arabia and injury claimed by the domestic industry.”

- It is needless to stress that declining prices in the first 9 months of POI and the resultant injury to the domestic industry in the first 9 months of the POI cannot be attributed to imports from Saudi Arabia. Also, any injury caused to the domestic industry during first three years of injury investigation period is attributable to other factors like shutdown of the HPCL (raw material supplier) plant, imports from other countries already attracting anti-dumping duty etc. and not to imports from Saudi Arabia for the simple reason that there were no imports from Saudi Arabia during that period.
- At best, imports from Saudi Arabia can only be responsible for injury to the domestic industry in the last three months of the POI. However, such attribution analysis is incorrect and unjust.
- It is humbly submitted that a short period of 3 months will not result in an objective assessment of causal link. It is insufficient for assessment of causal link. In accordance with Article 3.5 of the Anti-dumping Agreement and Annexure II, para. 5 of Indian Anti-dumping Rules, it must be demonstrated that dumped imports are, through the effects of dumping causing injury to the domestic industry. It is not possible to establish that injury caused to the domestic industry throughout the injury investigation period of 4 years and particularly during the POI is due to imports during three months of January to March 2016. Needless to say, such an evaluation will not satisfy the requirement of objective examination under Article 3.1 of the Anti-dumping Agreement and Annexure II, para (i) of Indian Anti-dumping Rules.
- Moreover, Designated Authority shall also examine any known factors other than dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, and the injury caused by these factors must not be attributed to the dumped imports.
- Examination of the situation of domestic industry over number of years i.e. 4 years injury investigation period is advisable because it will reveal injury caused by other factors recession, business or product cycles or by structural adjustment problems of the domestic industry. Needless to say, 3 months of period will not allow such assessment of causal link at all.
- No assessment of causal link in accordance with the provisions of Anti-dumping Agreement and Indian Anti-dumping Rules is possible in the present case where imports have happened only during three months, leave alone the requirement of objective assessment based on positive evidence.
- The Designated Authority has observed positive improvements on certain parameters such as production, sales volume and capacity utilisation in the POI.
- For other parameters where there are negative trend prior to the POI such as market share, productivity etc. imports from Saudi Arabia cannot be considered responsible for such injury.
- The Designated Authority has noted that negative trend for some parameters has continued in the POI and imports from Saudi Arabia took place in last three months of the POI. Such continuation of negative trend on certain parameters in the POI cannot be attributed to imports from Saudi Arabia that took place only in last three months of the POI.
- We disagree with the assessment of the Designated Authority in the disclosure statement that dumped imports from subject country as well as other non-subject countries have adversely impacted the

performance of domestic industry. Imports from non-subject country took place throughout the injury investigation period. However, imports from Saudi Arabia took place only during last three months of the POI. The Designated Authority cannot equate impact of imports from other countries with the imports from Saudi Arabia. Negative development on economic parameters was experienced throughout the investigation period whereas imports from Saudi Arabia took place only during last three months of the POI.

- Also, the Designated Authority cannot conclude that performance of domestic industry deteriorated in the last quarter of the POI due to imports from Saudi Arabia. As already noted segregation of the POI into sub-groups for determination of injury and causal link is not permitted. It would also be against the initiation notice which prescribed POI of one year period. In any case, import data of three months is insufficient to make any assessment of causal link between such imports and injury to the domestic industry.

Examination by the Authority

93. The Authority notes various submissions made by Domestic Industry and the producers/exporters from Saudi Arabia filed in response to the disclosure statement and holds that all relevant facts to be made as the basis for final findings have been disclosed. The public file contains all non-confidential version of documents/information filed by different interested parties. The Authority notes that in the foregoing paras under injury, certain economic and financial parameters regarding Domestic Industry have though been noted to be adverse however attributing cause of these to imports from Saudi Arabia over 3 months only requires appropriate analysis. The Authority has examined the contentions of Domestic Industry and the other interested parties on various aspects of investigation viz. dumping, injury and causality reported by the Authority in the foregoing paragraphs and holds as under:

- (i) The Authority notes that during the PoI i.e. 1st April, 2015 to 31st March, 2016 the imports of subject goods in the first 9 months occurred from 5 countries viz. EU, Malaysia, Singapore, South Africa and the USA. These countries were subjected to an Anti-Dumping investigation initiated on 20th November, 2014 with PoI of 1st April, 2013 to 30th June, 2014 and final findings dated 19th February, 2016 recommending Anti-Dumping measures being accepted on 13th April, 2016 vide Customs Notification No. 13/2016 – Cus (ADD).
- (ii) The Authority notes that demand of the subject goods have continued to increase from 2012 – 13 to 2015 – 16. The Authority further notes that during the PoI for the current investigation, though there were no Anti-Dumping measures on the 5 countries mentioned in (i) above levied, the Domestic Industry's performance showed improvement on parameters like production, sales, capacity utilisation, profit and market share when compared with the previous 2 financial years i.e. 2013 – 14 and 2014 – 15 which include the complete PoI of earlier Anti-Dumping investigation against 5 countries viz. EU, Malaysia, Singapore, South Africa and the USA. The improvement in performance can only be attributed to factors other than dumping from above mentioned 5 countries as AD measure on 5 dumped sources was made applicable post PoI in April 2016. One of the factors noted is the declining cost of sales of Domestic Industry which has reduced the per unit losses. In order to segregate injury due to 5 dumped sources already investigated, the behaviour of the import prices from these 5 countries post levy of ADD in April 2016 maybe needed which is not captured during this PoI. This data could in fact enable segregating injury due to the fresh source of imports i.e. Saudi Arabia.
- (iii) Further the Authority notes that 'net sales realisation' of the domestic industry during first 9 months of the PoI has declined in line with the import prices from the 5 countries viz. EU,

Malaysia, Singapore, South Africa and the USA especially Malaysia and Singapore. The price level set by these imports was matched by the export prices from Saudi Arabia during January – March 2016 and not set by producers/exporters from Saudi Arabia.

- (iv) The market entry price by any new player in a global market tend to match and compete with the existing prices in the importing market. The prices available to Saudi Arabia for reference during January – March 2016 were the uncorrected prices from 5 countries viz. EU, Malaysia, Singapore, South Africa and the USA which got corrected to a fair level in April 2016 after levy of AD measures. The prices in January – March 2016 were therefore not set by producers/exporters from Saudi Arabia but given to them. The export price pattern of exports from Saudi Arabia in a situation where other prevailing prices in India were restored to a fair level can only be evaluated if a larger period beyond PoI was available to consider export pattern/prices from Saudi Arabia. The PoI under present investigation therefore constrains a fair and objective assessment of causality between the exports by Saudi Arabia to India and consequential injury to Domestic industry during the considered PoI.
- (v) Since the investigation is for examining material injury and not for evaluating threat of injury or material retardation to Domestic Industry, a reasonable duration of period is warranted to capture the price and volume trend from Saudi Arabia and to analyse impact of factors other than dumped imports to exclusively establish a causal link between dumping and consequential injury. The 3 months of exports from January – March 2016 is not sufficient enough in this case to conclusively establish a causal link between exports from Saudi Arabia and injury to Domestic Industry. The Authority holds that post PoI data cannot be referenced for the above analysis as for the current investigation PoI is fixed as 1st April, 2015 to 31st March, 2016, for determining material injury to Domestic Industry on account of dumping during this period.
- (vi) The Authority notes the submissions by producers/exporters from Saudi Arabia on dumping margin computation and holds that guidelines of the committee on Anti-Dumping practices regarding duration of PoI adopted on 5th May, 2000 are only recommendations which recognize at the same time that the Investigating Authorities may consider appropriate PoI's on a case specific basis.
- (vii) The Authority notes that the fact of exact date of commercial production by M/s Sabuco i.e. March 2016 was known after onsite verification of the producer/exporter during the course of investigation. The Authority further notes that the trial production by M/s Sabuco started in October 2015 and the declaration of commercial production in March 2016 has impact only on determination of processing cost component of M/s Sabuco, the toller for the 2 producers/exporters. Raw materials and SGA costs are considered from the records of two producers i.e. M/s Sadara and M/s SAAC. Since any commercial sales activity in domestic or export market generally needs to be based on a prudent pricing policy, the fact that exports to India occurred in January 2016 and first domestic sales by Sadara was made in December 2015, the requirement of minimum period of 6 months PoI with reference to normal value determination is technically met and not compromised. If the producers/exporters have undertaken sales in domestic and exports market prior to date of declaration of commercial production, the Investigating Authorities cannot ignore such sales and exempt such exports from the purview of dumping examination. In the facts of this case, the Authority had to adopt the cost data of M/s Sabuco appropriately. However the Authority holds that the processing cost component pertaining to M/s Sabuco could be further validated and refined if 6 months data after date of commercial production was adopted to take care of start-up and unusual costs along with recovery test to make the 'normal value' more representative and realistic.

Conclusions and Recommendations:

94. Having examined the contention of various interested parties and on the basis of the above facts, circumstances, limitations and analysis, the Authority concludes as under:

- (i) Period of last 3 months of PoI of exports of subject goods from Saudi Arabia is not sufficient to evaluate injury to the domestic industry as material injury determination would require data on imports and Domestic industry's sales for a longer duration.
- (ii) The short period of production especially commercial production of just one month also constrains determination of a representative and realistic normal value for cooperating producers/exporters.
- (iii) Causal link between imports from Saudi Arabia and injury to the Domestic Industry is not conclusively established on the basis of 3 months of export period.
- (iv) The Authority in view of the above does not consider it appropriate to recommend levy of an Anti-Dumping Duty on the subject goods from Saudi Arabia and hereby terminates this investigation in accordance with Rule 14 (b) of AD Rules.

Further Procedure

95. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this Final Findings Notification shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.